चौथी दुनिया
www.chauthiduniya.com
मूल्य 5 रुपये
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार
1986 से प्रकाशित
23 मार्च –29 मार्च 2015
Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

देश का सबसे बड़ा ऊर्जा घोटाला

जज ने लांघी क़ानून की हद

प्रभात रंजन दीन

ऊर्जा घोटाले में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर संज्ञान लेने और तीन सालों तक रिपोर्ट दबाए रखने वाले जज के ख़िलाफ़ इलाहाबाद हाईकोर्ट के विजिलेंस ब्यूरो ने कार्रवाई शुरू कर दी है. जज के ख़िलाफ़ शिकायत यह भी है कि उन्होंने न्याय विभाग में प्रमुख सचिव रहते हुए संवेदनशील तथ्य छिपाकर एक विवादास्पद सरकारी वकील के जज बनने में मदद की थी. यह प्रकरण सामने आते ही उत्तर प्रदेश के ऊर्जा सेक्टर में हुए अरबों के घोटाले की लीपापोती में लगे जजों, नौकरशाहों और विभागीय अफसरों के साथ–साथ सीबीआई के भी क़ानून के शिकंजे में आने की संभावना बढ़ गई है. उत्तर प्रदेश का ऊर्जा घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने वाला है, जिसमें न केवल नेता और नौकरशाह, बल्कि जज और सीबीआई के अधिकारी भी लिप्त हैं. यह रोचक और रोमांचक ही है कि अरबों के ऊर्जा घोटाले की सीबीआई जांच का औपचारिक आदेश हो जाने के बाद भी उसे अदालत में दबाए रखा गया और आख़िरकार सीबीआई ने ही जांच करने से मना कर दिया. ऊर्जा घोटाले में सीबीआई भी अभियुक्त है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने लखनऊ के तत्कालीन ज़िला जज केके शर्मा के ख़िलाफ़ गंभीर शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए शिकायतकर्ता नंदलाल जायसवाल को हलफनामा दाखिल करने और संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. केके शर्मा अभी एटा में ज़िला जज के पद पर तैनात हैं. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड में हुए सैकड़ों करोड़ के घोटाले में सीजेएम अदालत के निर्देश पर 23 जनवरी, 2008 को ही हजरतगंज थाने में प्रदेश के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय, आठ आईएएस अफसरों आरबी भास्कर, वीरेश कुमार, अशोक खुराना, राजकमल गुप्ता, जीबी पटनायक, कुंअर फतेह बहादुर सिंह, महेश गुप्ता, आलोक टंडन और उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड के 19 अधिकारियों के ख़िलाफ़ एफआईआर (संख्या– 72/2008) दर्ज की गई थी. इनके ख़िलाफ़ भारतीय दंड विधान की धारा 193, 409, 420, 465, 471, 471–ए, 120–बी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की. राजनीतिक दबाव और पुलिस की शिथिलता पर 20 जनवरी, 2009 को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई. इस पर अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह त्वरित कार्रवाई करे, लेकिन पुलिस ने तब भी कोई कार्रवाई नहीं की. विडंबना यह है कि इस बीच 19 विवेचना अधिकारी (आईओ) बदल भी दिए गए.

इसके पहले से ही पानी सिर के ऊपर से बह रहा था.

वर्षों दबाए रखी फाइनल रिपोर्ट

न्यायाधीश जगदीश भल्ला

न्यायाधीश विनय कुमार माथुर

न्यायाधीश बी एन अग्रवाल

न्यायाधीश अनिल कुमार

न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी

न्यायाधीश डी के उपाध्याय

न्यायाधीश इम्तियाज़ मुर्तज़ा

न्यायाधीश वाई के सबरवाल

न्यायाधीश कमल किशोर

न्यायाधीश रमेश दत्त शुक्ला

व्हिसिल ब्लोअर नंदलाल जायसवाल

न्यायाधीश के के शर्मा

लीपापोती में लगे रहे दर्जन भर जज

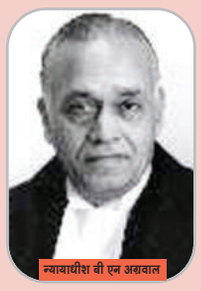

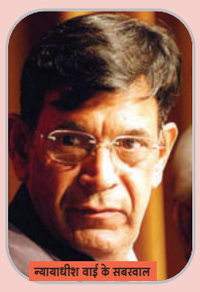

केके शर्मा अकेले जज नहीं हैं, जिन्होंने ऊर्जा घोटाले की लीपापोती में संदेहास्पद भूमिका अदा की. विदेशी कंपनी के साथ मिलीभगत कर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पांच हज़ार करोड़ रुपये का घोटाला किए जाने के मामले में सीबीआई से जांच कराने की सरकारी अधिसूचना जारी हो जाने के बाद भी जांच नहीं करने दी गई. इस षड्यंत्र में सीबीआई के अधिकारी भी शरीक रहे. विचित्र, किंतु सत्य यह है कि पावर कॉरपोरेशन की विजिलेंस शाखा ने घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की और स्टेट विजिलेंस ने भी कहा कि पूरा प्रकरण गंभीर जांच की अपेक्षा करता है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के तत्कालीन जज स्वनामधन्य जगदीश भल्ला और कमल किशोर ने विजिलेंस की सिफारिश को तकनीकी पड़ताल के लिए उन्हीं लोगों के सुपुर्द कर दिया, जो अरबों रुपये के घोटाले में लिप्त थे. हाईकोर्ट के तत्कालीन जज एसएचए रजा और आरडी शुक्ला की बेंच ने सीबीआई जांच के अपने ही पूर्व के फ़ैसले का ऑपरेटिव पोर्शन बदल डाला. जज डीके त्रिवेदी और नसीमुद्दीन की बेंच ने क़ानूनी पेचोख़म में उलझा कर मामले को आगे बढ़ने नहीं दिया. जज वीरेंद्र शरण और आरडी शुक्ला की बेंच ने एसएचए रजा वाली बेंच का विरोधाभासी फ़ैसला ही पकड़े रखा तथा जज रितुराज अवस्थी और अनिल कुमार शिकायतकर्ता का पक्ष सुने बगैर तारीख पर तारीख देते रहे. इन सारे जजों की संदेहास्पद भूमिका के बारे में राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी जाती रही, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जज रहे इम्तियाज मुर्तजा और विनय कुमार माथुर ने तो हद ही कर दी. उन्होंने याचिकाकर्ता नंदलाल जायसवाल को अंधेरे में रखकर उनकी जनहित याचिका खारिज कर दी. जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह और जज श्रीनारायण शुक्ला की बेंच ने याचिकाकर्ता को शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दे रखा था. शपथ पत्र दाखिल करने के बाद नंदलाल जायसवाल सुनवाई की तारीख का इंतज़ार ही करते रह गए और उधर उनकी याचिका खारिज कर दी गई. जज इम्तियाज मुर्तजा और विनय माथुर के बेजा फ़ैसले की शिकायत पर वह जनहित याचिका फिर से री–स्टोर हुई. हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा उस जनहित याचिका को वापस क़ानूनी प्रक्रिया में लाने का निर्णय उन जजों और मौजूदा न्यायिक व्यवस्था पर करारे तमाचे की तरह साबित हुआ. ■

सरकार ने विधानसभा में यह मान लिया था कि जल विद्युत निगम में महाप्रबंधक से लेकर अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं तक की फर्जी तरक्कियां और अन्य अनियमितताएं की गईं. इस पर गृह विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव ने लखनऊ पुलिस को एफआईआर भी दर्ज करने को कहा, लेकिन पुलिस ने यह कह दिया कि भ्रष्टाचार और अनियमितता नहीं पाई गई. इस पर सरकार ने तत्कालीन ऊर्जा सचिव हरिराज किशोर को जांच का आदेश दिया. ऊर्जा सचिव ने 28 नवंबर, 2006 को प्रमुख सचिव ऊर्जा को पेश की गई अपनी जांच रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के सभी मामले सही पाए और निदेशक (वित्त) को आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखा. वह रिपोर्ट 29 नवंबर, 2006 को आवश्यक कार्रवाई के लिए नियुक्ति विभाग भी भेजी गई. 28 दिसंबर, 2006 को लोकसभा में पूछे गए सवाल पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब भी दिया कि जांच के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. लेकिन हुआ कुछ भी नहीं. फिर सत्ता बदली और सपा की जगह बसपा की सरकार आ गई. बसपा सरकार के ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय ने सारी फाइलें अपने पास मंगवा लीं और उन्हें 2012 (बसपा सरकार के कार्यकाल) तक अपने पास दबाए रखा. इससे सपा और बसपा दोनों के कार्यकाल के घोटाले दबे रह गए. बसपा सरकार के समय तीस हज़ार करोड़ रुपये

(शेष पृष्ठ 2 पर)

मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और कोयला घोटाला
पेज-03

हिस्सेदारी की दावेदारी
पेज-04

पहले किसानों, मज़दूरों और ग़रीबों की बात हो
पेज-06

साईं की महिमा
पेज-12

जज ने लांघी क़ानून की हद

पृष्ठ एक का शेष

का बिजली घोटाला हुआ था. बसपा सरकार ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और निजी कंपनियों के साथ बिजली खरीद करार करके इस घोटाले को अंजाम दिया था. इस घोटाले के कई सबूत और दस्तावेज़ी प्रमाण भी लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा को सौंपे गए थे. लोकायुक्त ने शिकायत को संज्ञान में ले लिया था, लेकिन कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने पांच निजी पावर ट्रेडिंग कंपनियों के साथ द्विपक्षीय समझौता किया था. इसमें पावर कॉरपोरेशन ने इन कंपनियों से महंगी दर से पांच हज़ार करोड़ यूनिट बिजली खरीदने का समझौता किया था. समझौते की शर्त यह थी कि पावर कॉरपोरेशन को उस दौरान सस्ती बिजली मिलने पर भी उसे अन्य कहीं से खरीद का अधिकार नहीं होगा, चाहे वह केंद्रीय ग्रिड की एनटीपीसी और दूसरी कंपनियों से मिलने वाली सस्ती बिजली ही क्यों न हो. राज्य सरकार ने जिस तरह से बिजली खरीदी, उससे सरकारी खज़ाने को भीषण नुक़सान पहुंचा. बसपा सरकार से पहले सपा के शासनकाल में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 1600 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था. उस मामले में भी केवल जांच ही चलती रही, नतीजा शून्य रहा.

मायावती के कार्यकाल के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने कई सार्वजनिक बयानों में कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में मायावती सरकार 25 हज़ार करोड़ रुपये का घाटा छोड़कर गई है, लेकिन इस घाटे की वजह जानने की अखिलेश सरकार ने कभी कोशिश नहीं की. अकेले जेपी समूह को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही प्रदेश सरकार को 30 हज़ार करोड़ रुपये की चपत लगाई जा चुकी है. इसके लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष राजेश अवस्थी को निष्कासित भी होना पड़ा, लेकिन घोटाले को लेकर कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं की गई. उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम में भी 750 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ, लेकिन इस घोटाले में लिप्त तत्कालीन सीएमडी आईएएस आलोक टंडन समेत अन्य अधिकारियों एवं अभियंताओं का कुछ नहीं बिगड़ा. सपा के मौजूदा शासनकाल में बिजली बिलों में फर्जीवाड़ा कर हज़ार करोड़ रुपये का घोटाला किए जाने का मामला सामने आया. यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अधिकृत बिलिंग कंपनी की मिलीभगत के ज़रिये इस घोटाले को अंजाम दिया गया है.

बहरहाल, इन घोटालों की लीपापोती में अभी तक नेताओं–नौकरशाहों का खेल चल रहा था, इसके बाद अदालतों का खेल भी सामने आया. 16 अप्रैल, 2013 को नंदलाल जायसवाल की तरफ़ से दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के दरम्यान 18 अप्रैल को अपर महाधिवक्ता बुलबुल गोदियाल ने प्रमुख सचिव गृह का हवाला देते हुए बताया कि इस मामले में चार अक्टूबर, 2012 को ही फाइनल रिपोर्ट (संख्या 5/12) सीजेएम अदालत में दाखिल हो चुकी है. लिहाजा शिकायतकर्ता अपनी आपत्ति वहीं दाखिल करे. हालांकि, याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया भी कि यह तथ्य ग़लत है, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना और सीजेएम कोर्ट में ही आपत्ति दाखिल करने को कहा. 29 अप्रैल, 2013 को सीजीएम कोर्ट ने बताया कि फाइनल रिपोर्ट उस अदालत में है ही नहीं. इस पर हाईकोर्ट ने चार दिसंबर, 2013 को सीजेएम लखनऊ को पुलिस की फाइनल रिपोर्ट के साथ अदालत में हाजिर होने को कहा. वह रिपोर्ट न तो सीजेएम कोर्ट में थी और न प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में थी. सीजेएम लखनऊ ने बताया कि फाइनल रिपोर्ट लखनऊ के सत्र न्यायाधीश की अदालत में है. तब 19 दिसंबर, 2013 को हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को सत्र न्यायाधीश (सेशन जज) की अदालत में आपत्ति दाखिल करने का आदेश दिया. अदालती औपचारिकताएं और पेचीदगियां चल ही रही थीं कि 29 जनवरी, 2014 को आधिकारिक तौर पर यह सामने आया कि फाइनल रिपोर्ट लखनऊ के ज़िला (सेशन) जज केके शर्मा की अदालत में ही पड़ी थी. इसके बाद भी ज़िला जज ने याचिकाकर्ता को फाइनल रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी. उसे कोर्ट में ही पढ़ लेने की ताकीद की. हज़ार पन्नों की फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में कुछ समय में पढ़ लेना नामुमकिन था. बहरहाल, कोर्ट ने यह भी कहा कि यह फाइनल रिपोर्ट 10 अप्रैल, 2013 को अदालत में आई है. जबकि तथ्य यह है कि चार अक्टूबर, 2012 को ही फाइनल रिपोर्ट ज़िला जज के यहां आ चुकी थी. लेकिन इस बारे में याचिकाकर्ता को कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई. कोर्ट के क्षेत्राधिकार का सवाल भी उठा और कोर्ट को बताया गया कि भ्रष्टाचार का उक्त मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत विशेष न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार में आता है. ज़िला जज केके शर्मा इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उन्होंने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को संज्ञान में कैसे और क्यों लिया और लंबे अर्से तक उसे दबाए क्यों रखा?

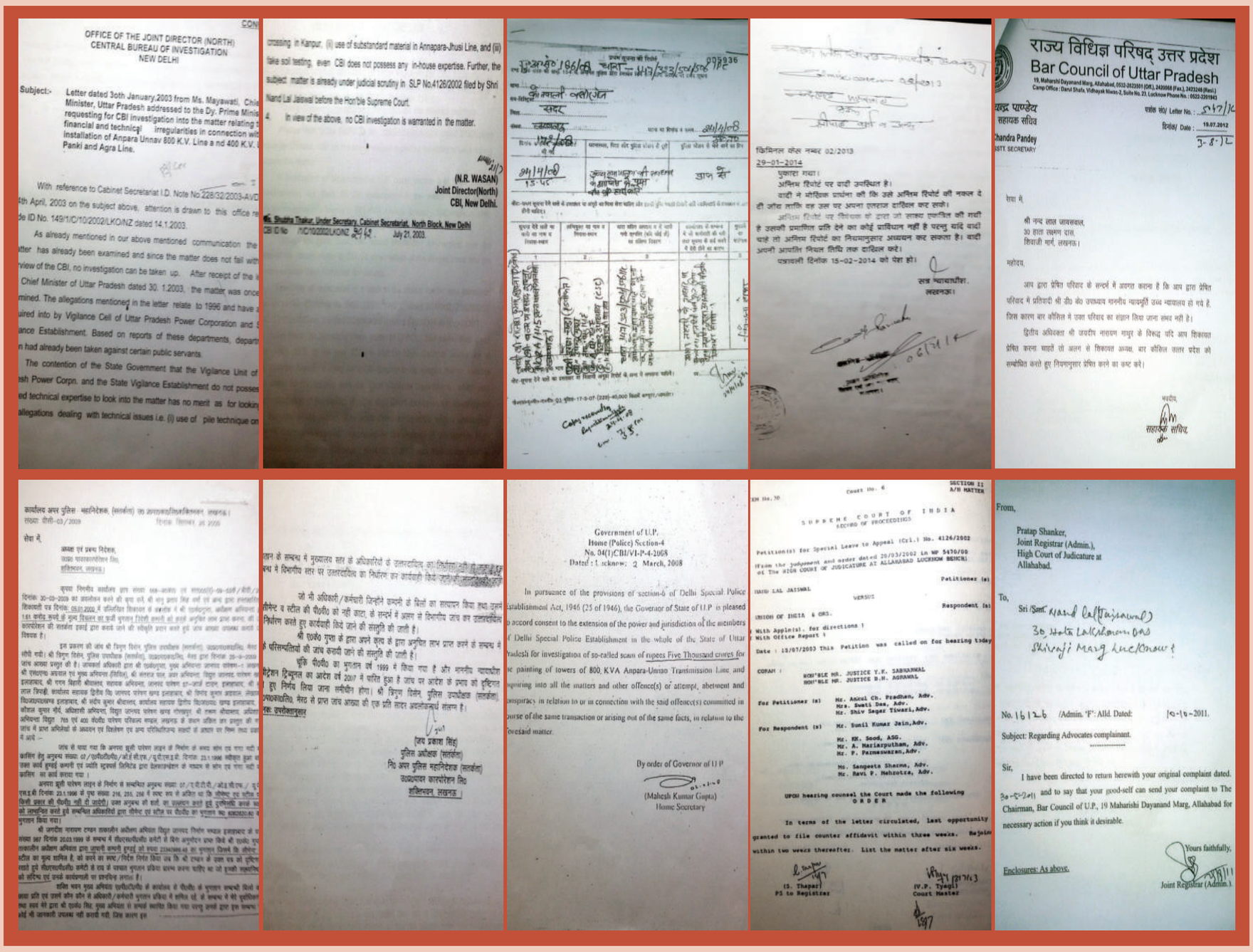

कोर्ट का संदेहास्पद रवैया देखते हुए लखनऊ के तत्कालीन ज़िला जज केके शर्मा के ख़िलाफ़ इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज के यहां 19 मार्च, 2014 को शिकायत दाखिल की गई. इसके बाद ही छह मई, 2014 को केके शर्मा का एटा तबादला कर दिया गया. उनकी जगह पर लखनऊ के ज़िला जज बनकर आए वीके श्रीवास्तव ने पदभार ग्रहण करते ही संदर्भित मामले को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत का मामला माना और उसे फौरन विशेष जज के सुपुर्द कर दिया. इस तरह यह साफ़ हो गया कि तत्कालीन ज़िला जज केके शर्मा ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर फाइनल रिपोर्ट को अपनी अदालत में दबाए रखा था. दक्षिण कोरिया की कंपनी मेसर्स हुंडई इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस द्वारा 220 करोड़ रुपये का फर्जी भुगतान ले लिए जाने के मामले में भी केके शर्मा हुंडई कंपनी के पक्ष में फ़ैसला देकर विवादों में आ चुके हैं. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के भ्रष्ट अधिकारियों ने हुंडई के साथ मिलीभगत करके उसे फर्जी भुगतान दे दिया था.

याचिकाकर्ता नंदलाल जायसवाल ने हाईकोर्ट प्रशासन से यह भी शिकायत की है कि केके शर्मा जब न्याय विभाग के प्रमुख सचिव थे, तब उन्होंने सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता (चीफ स्टैंडिंग काउंसिल) देवेंद्र कुमार उपाध्याय पर दर्ज आपराधिक मुकदमे का तथ्य छिपा लिया था. उपाध्याय के जज बनाए जाने की फाइल क़ानूनी सलाह के लिए प्रमुख सचिव रहे केके शर्मा के पास भेजी गई थी. उपाध्याय नवंबर 2011 में जज बने, जबकि आपराधिक मुकदमा चलने के बारे में केंद्रीय क़ानून मंत्रालय ने 29 जून, 2011 को ही प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन प्रदेश सरकार ने केंद्र को कोई जवाब नहीं भेजा. आपराधिक मुकदमे वाली पृष्ठभूमि के व्यक्ति को जज बनाए जाने के ख़िलाफ़ इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी शिकायत की गई थी, लेकिन वहां से कहा गया कि इस बारे में बार काउंसिल से शिकायत करें. बार काउंसिल ने शिकायत दबाए रखी और तीन अगस्त, 2012 को लिखा कि जज बनने के कारण बार काउंसिल देवेंद्र कुमार उपाध्याय के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती. उल्लेखनीय है कि लखनऊ के वजीरगंज थाने में देवेंद्र कुमार उपाध्याय समेत छह लोगों पर भारतीय दंड विधान की धारा 147 (बलवा करना), 323 (मारपीट कर जख्मी करना), 504 (लोक शांति भंग करना) और 506 (आपराधिक अभित्रास) का मुकदमा (संख्या 186/08) दर्ज हुआ था. इस मामले में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी, जिसके ख़िलाफ़ एसीजेएम सीबीआई (एपी) की अदालत में प्रोटेस्ट दाखिल किया गया था. यह मामला उपाध्याय के जज बनने के साल भर बाद तक चलता रहा. खूबी यह है कि अदालत में बाकायदा इसकी तारीखें पड़ती रहीं, प्रक्रिया चलती रही, लेकिन इसे सूचना को डिस्प्ले नहीं किया जाता रहा. सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता देवेंद्र कुमार उपाध्याय और प्रदेश के अपर महाधिवक्ता जेएन माथुर पर ऊर्जा विभाग से लाखों रुपये के फर्जी भुगतान प्राप्त करने के भी गंभीर आरोप पहले से लग रहे थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

सुप्रीम कोर्ट के जज कम दागदार नहीं

तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने 30 जनवरी, 2003 को मामले की सीबीआई जांच कराने का बाकायदा शासनादेश जारी किया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वाईके सबरवाल एवं बीएन अग्रवाल की बेंच ने 13 जुलाई, 2003 को केंद्र, सीबीआई और यूपी पावर कॉरपोरेशन को अंतिम मौक़ा देते हुए प्रति–शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. केंद्र सरकार, सीबीआई और यूपी पावर कॉरपोरेशन की इस खुली नाफरमानी पर सख्त संज्ञान लेने के बजाय सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच ने मामले को ही खारिज कर दिया. वही सबरवाल बाद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने.

व्हिसिल ब्लोअर ने बड़ी क़ीमतें चुकाईं

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा घोटालों को उजागर करने वाले नंदलाल जायसवाल ने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बिगुल फूंकने की बड़ी क़ीमतें चुकाईं. जायसवाल विद्युत विभाग के ही कर्मचारी थे. उन्होंने ऊर्जा सेक्टर में फैले भ्रष्टाचार को अपने शीर्ष अधिकारियों के समक्ष उजागर करना शुरू किया, लेकिन शीर्ष अधिकारियों ने उनका ही उत्पीड़न शुरू कर दिया. धीरे–धीरे शीर्ष अधिकारियों के भ्रष्टाचार की परतें खुलती गईं और नंदलाल जायसवाल के ख़िलाफ़ साजिशें बढ़ती गईं. उनके ख़िलाफ़ आपराधिक षड्यंत्र तक हुए. फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए, कातिलाना हमला हुआ, फर्जी मुकदमों में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और नौकरी से निकाल बाहर किया गया. अदालत ने भी पाया कि जायसवाल पर फर्जी मुकदमे लादे गए. अदालत के हस्तक्षेप पर वर्षों बाद उन्हें पेंशन मिलनी शुरू हुई. इस बीच उनके घर के सारे जेवर बिक गए और जायसवाल काला कोट पहन कर वकील के रूप में ऊर्जा सेक्टर के भ्रष्टाचारियों के ख़िलाफ़ क़ानूनी लड़ाई में उतर गए. ऊर्जा सेक्टर में अरबों रुपये के घोटाले उजागर करने वाले व्हिसिल ब्लोअर को संरक्षण और सुरक्षा देने के बजाय नेता, नौकरशाह एवं कुछ जज तक उनका मुंह बंद करने की साजिशों में लगे रहे और देश के सबसे बड़े घोटाले को निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंचने दिया गया. फिर भी लड़ाई जारी है...

मायावती के कार्यकाल के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने कई सार्वजनिक बयानों में कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में मायावती सरकार 25 हज़ार करोड़ रुपये का घाटा छोड़कर गई है, लेकिन इस घाटे की वजह जानने की अखिलेश सरकार ने कभी कोशिश नहीं की. अकेले जेपी समूह को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही प्रदेश सरकार को 30 हज़ार करोड़ रुपये की चपत लगाई जा चुकी है.

अधिसूचना को सीबीआई ने दिखाया ठेंगा

पांच हज़ार करोड़ रुपये के ऊर्जा घोटाले की सीबीआई जांच कराने की अधिसूचना जारी होने के बावजूद सीबीआई ने जांच करने से मना कर दिया. यह हैरतअंगेज हुकुमउदूली सीबीआई ने की और केंद्र एवं राज्य सरकार चुप बैठी रह गई. घोटाले की रकम इतनी बड़ी थी कि उसने राज्य एवं केंद्र सरकार में बैठे सियासतदानों, नौकरशाहों और सीबीआई के अधिकारियों तक को अपने प्रभाव में ले लिया. तभी सीबीआई ने सरकार की अधिसूचना तक को ताख पर रखकर यह कह दिया कि यह मामला जांच के उपयुक्त नहीं है. सीबीआई के अधिकारियों की इस अराजकता के ख़िलाफ़ कोई सुगबुगाहट भी नहीं हुई. सीबीआई के अधिकारियों ने जांच से मना करते हुए इसे पुराना मामला बताया, फिर कहा कि घोटाले से संबंधित जानकारियां नहीं दी जा रही हैं. फिर कहा कि उसके पास जांच की तकनीकी क्षमता नहीं है, फिर यह भी कहा कि इस घोटाले का कोई अंतरराष्ट्रीय प्रसार नहीं है. जबकि सीबीआई के सारे तर्क आधारहीन पाए गए. पांच हज़ार करोड़ रुपये का यह ऊर्जा घोटाला दरअसल विदेशी कंपनी के साथ यूपी पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों की मिलीभगत से ही अंजाम दिया गया था.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 03
दिल्ली, 23 मार्च –29 मार्च 2015
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय	0120–6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022–42296060
	+91–8451050786
	+91–9266627379
फैक्स न.	0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

फोटो– प्रभात पाण्डेय

चौथी दुनिया ने अपने 25 अप्रैल, 2011 के अंक में कोयला घोटाले का पर्दाफाश किया था. उस वक्त न सीएजी की रिपोर्ट आई थी और न किसी ने सोचा था कि इतना बड़ा घोटाला भी हो सकता है. उस वक्त हमारी रिपोर्ट पर किसी ने विश्वास नहीं किया. चौथी दुनिया ने अपनी पहली रिपोर्ट में ही कहा था कि यह घोटाला नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का पहला महाघोटाला है, जिसमें इस देश को 26 लाख करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ है. देश की तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया अब भी तटस्थ बैठा है. वह तय नहीं कर पा रहा है कि घोटाला है भी या नहीं. और, अगर घोटाला है, तो फिर कितने का है. चौथी दुनिया की रिपोर्ट को देश के उच्चतम न्यायालय ने सही साबित किया और 218 में से 214 कोयला ब्लॉकों के आवंटन रद्द कर दिए. मोदी सरकार अब फिर से इन कोयला खदानों की नीलामी कर रही है. अब तक 33 खदानों की नीलामी से ही दो लाख नौ हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा पैसा देश को मिल चुका है. मतलब यह कि नीलामी प्रक्रिया ने चौथी दुनिया की रिपोर्ट पर भी मुहर लगा दी है. 09 सितंबर, 2013 के अंक में चौथी दुनिया ने एक कवर स्टोरी छापी, जिसका शीर्षक था-मनमोहन सिंह जेल जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह को आरोपी बनाकर इस ख़बर की भी पुष्टि कर दी है.

मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और कोयला घोटाला

मनीष कुमार

मनमोहन सिंह के आरोपी बनते ही सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं को मनमोहन सिंह का बचाव करने के आदेश दे दिए. सोनिया ने कांग्रेस दफ्तर से मनमोहन सिंह के घर तक मार्च करके उनके प्रति पार्टी के समर्थन का इजहार किया. अजीबोगरीब स्थिति है. एक व्यक्ति इतिहास के सबसे बड़े घोटाले का आरोपी बनता है और देश की सबसे पुरानी पार्टी उसके साथ खड़ी हो जाती है. क्या यही गांधी, नेहरू और पटेल की पार्टी का चरित्र रह गया है? सवाल यह है कि सोनिया गांधी ने ऐसा क्यों किया, इस राजनीतिक ड्रामे के पीछे क्या कारण था? मनमोहन सिंह के साथ सॉलिडेरिटी तब क्यों नहीं दिखाई गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछताछ करने का आदेश दिया? मनमोहन सिंह अब तक चुप रहे हैं. लेकिन, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले में आरोपी नंबर छह बनाया, तो कांग्रेस पार्टी का पसीना छूटने लगा. सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस कार्यसमिति की आपात बैठक बुलाई. बैठक में कार्यसमिति के वरिष्ठ रणनीतिकारों ने मनमोहन के ख़िलाफ़ मुकदमे और अन्य अहम मसलों पर रणनीति तैयार करते हुए सिंह के समर्थन में पार्टी दफ्तर से उनके आवास तक मार्च करने का निर्णय लिया. हालांकि, ऐसी बैठकों में यह पहले ही तय हो जाता है कि क्या फ़ैसला करना है. बैठक सिर्फ़ औपचारिकता होती है. सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर आपात बैठक बुलाकर यह साबित कर दिया कि मनमोहन सिंह को आरोपी बनाया जाना कांग्रेस पार्टी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है. इसलिए एक रणनीति के तहत आपात बैठक बुलाई गई. सोनिया गांधी कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों से मिलीं, साथ ही दोनों सदनों के पार्टी सांसदों को भी तलब किया गया. मजेदार बात यह है कि इस बैठक में मनमोहन सिंह को नहीं बुलाया गया. सभी ने वही किया, जो पहले से तय था. सारे लोग कांग्रेस कार्यालय से मार्च करते हुए मनमोहन सिंह के घर पहुंचे. अब सवाल यह है कि सोनिया गांधी ने ऐसा क्यों किया?

सच्चाई यह है कि मनमोहन सिंह उस दौरान प्रधानमंत्री ज़रूर थे, लेकिन वह कभी भी एक स्वतंत्र प्रधानमंत्री के रूप में काम नहीं कर सके. वह शायद देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री रहे, जिन्हें अपनी मनपसंद कैबिनेट चुनने की आज़ादी नहीं थी. मनमोहन सरकार से जुड़े लोगों द्वारा जितनी भी किताबें लिखी गईं, सबने यही लिखा कि मनमोहन सिंह सिर्फ़ मुखौटा थे, सत्ता का केंद्र हमेशा 10 जनपथ ही रहा. मनमोहन सिंह राजनेता कभी नहीं रहे, उनके पास जनसमर्थन नहीं है, वह आज तक कोई चुनाव नहीं जीते और हमेशा पिछले दरवाजे से राज्यसभा के सदस्य बनते रहे. ये उनकी कमियां नहीं, बल्कि खूबियां थीं, जिनकी वजह से उन्हें सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनाया था. दस साल की यूपीए सरकार की कहानी सोनिया गांधी के इस फ़ैसले से सही साबित हुई. मनमोहन सिंह नीतीश कुमार के मांझी नहीं निकले, उन्होंने कभी विद्रोह नहीं किया, क्योंकि वह एक करियरिस्ट हैं. सीधे शब्दों में कहें, तो वह प्रधानमंत्री पद की नौकरी कर रहे थे. उनमें देश और कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व देने की कभी इच्छा ही नहीं जगी. चूंकि वह एक करियरिस्ट हैं, इसलिए स्वयं को बेदाग रखने और बचाने के लिए हरसंभव क़दम उठाएंगे. यही वजह है कि वह दबाव में टूट जाते हैं. सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी इस बात को जानती है. जब 2-जी घोटाला हुआ, मामला कोर्ट पहुंचा और गिरफ्तारियां होने लगीं तथा जब शक की सुई मनमोहन सिंह की तरफ़ मुड़ने लगी, तब वह टूट गए. उन्होंने ऐसा बयान दिया कि कांग्रेस की किरकिरी हो गई. उन्होंने कहा कि 2-जी घोटाला गठबंधन के दबाव का नतीजा है. लेकिन, कोयला घोटाले में तो वह यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब घोटाला हुआ था, तब मनमोहन सिंह स्वयं कोयला मंत्री थे. मनमोहन सिंह के दस्तखत से कोयला खदानों का आवंटन हुआ और इसलिए वह इस घोटाले की ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते.

अब जरा समझते हैं कि सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ एकजुट होकर मनमोहन सिंह के घर तक मार्च क्यों किया. दरअसल, एक ख़बर यह आई कि आरोपी बनाए जाने के तुरंत बाद मनमोहन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से संपर्क साधा और फोन करके अपनी व्यथा सुनाई. बताया गया कि मनमोहन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं एवं मंत्रियों से कहा कि यह उनकी लड़ाई है. उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी उनका बचाव नहीं करेगी, इसलिए वह खुद अपना बचाव करेंगे. भाजपा नेताओं ने मनमोहन सिंह को आश्वासन दिया कि बदले की भावना के साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी. यह ख़बर आते ही कांग्रेस पार्टी के अंदर हड़कंप मचना स्वाभाविक था. मनमोहन सिंह को अदालत में एक आरोपी बनकर पेश होना है और यह उनके लिए एक शर्मनाक परिस्थिति है. कोयला खदानों का आवंटन उनके दस्तखत से हुआ है, ऐसे में बचने का बस एक ही रास्ता है. मनमोहन सिंह तभी बच सकते हैं, जब वह या तो सरकारी गवाह बन जाएं या फिर यह साबित कर दें कि उन्होंने जो किया, वह किसी के दबाव में किया. मतलब यह कि वह कोयला घोटाले के सारे राज उजागर करके खुद पर लगा दाग मिटा दें. मनमोहन सिंह कहीं दबाव में आकर कोर्ट में सब कुछ उजागर न कर दें, उसी को रोकने के लिए सोनिया गांधी ने मार्च किया.

यह बात है 2006-07 की, जब शिबू सोरेन जेल में थे और सरकार तेज़ी से कोयला खदान मुफ्त में बांटने लगी थी. सबसे बड़ी बात यह है कि उक्त कोयला खदानें सिर्फ़ 100 रुपये प्रति टन की खनिज रॉयल्टी के एवज में बांट दी गईं. मतलब यह कि पहले मुफ्त में खदानें दे दी गईं, फिर उन खदानों से कोयला निकालने के बाद 100 रुपये प्रति टन के रेट से सरकार को पैसे मिलने का प्रावधान बनाया गया. ऐसा तब किया गया, जब कोयले का बाज़ार मूल्य 1800 से 2000 रुपये प्रति टन के ऊपर था. समझने वाली बात यह है कि मनमोहन सरकार ने संसद को यह विश्वास दिलाया था कि माइंस और मिनरल (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 1957 में संशोधन किया जाएगा और तब तक कोई भी कोयला खदान आवंटित नहीं की जाएगी. नोट करने वाली बात यह है कि इस विधेयक में साफ़-साफ़ लिखा था कि कोयले या किसी भी खनिज की खदानों के लिए सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. अगर यह विधेयक 2006 में ही पास हो जाता, तो 26 लाख करोड़ रुपये का नुक़सान नहीं होता. 2006 में यह बिल राज्यसभा में पेश किया गया और यह माना गया कि जब तक दोनों सदन इसे मंज़ूरी नहीं दे देते और यह बिल पास नहीं हो जाता, तब तक कोई भी कोयला खदान आवंटित नहीं की जाएगी, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार ने यह विधेयक चार सालों तक लोकसभा में जानबूझ कर लंबित रखा और इस दौरान देश के सबसे बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया. संसद में किए गए वादे से सरकार मुकर गई और कोयला खदान बांटने का गोरखधंधा चलता रहा.

कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात पर भरोसा नहीं किया और शपथपत्र देने के लिए कहा. कई बार मनमोहन सरकार के अटॉर्नी जनरल वाहनवती को फटकार लगाई गई. कई बार संसद के अंदर और बाहर सरकार को माफी मांगनी पड़ी. यह घोटाला ऐसा था, जिसे छिपाने के लिए कांग्रेस सरकार ने हरसंभव उपाय किए. तत्कालीन क़ानून मंत्री अश्विनी कुमार ने सीबीआई रिपोर्ट ही बदल दी. पकड़े जाने पर झूठ बोला कि उन्होंने सिर्फ़ रिपोर्ट का व्याकरण ठीक किया. कोर्ट ने जब कड़ा रुख अपनाया, तो सीबीआई ने स्वीकार किया कि सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट को पेश करने से पहले उसे क़ानून मंत्री और पीएमओ ने देखा तथा उसमें बदलाव भी कराए. इतना ही नहीं, बेशर्मी की हद यह कि घोटाले से जुड़े कागजात गायब हो जाने की ख़बर फैला दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने जब सीबीआई से अधिकारियों और ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने को कहा, तो सारे कागजात अपने आप मिल गए. यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सारे ग़ैर क़ानूनी आवंटनों पर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर हैं. अब सवाल यह है कि कांग्रेस सरकार ने इस घोटाले पर पर्दा डालने और सीबीआई की जांच को पथभ्रष्ट करने के लिए अनैतिक तरीके क्यों अपनाए तथा किसे बचाने की कोशिश की जा रही है?

दरअसल, 2006 से 2009 के बीच तत्कालीन कोयला मंत्री शिबू सोरेन जेल में थे. उस दौरान इस मंत्रालय की ज़िम्मेदारी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास थी. उन दिनों कोल ब्लॉक आवंटन का काम पीएमओ की ओर से गठित एक स्क्रीनिंग कमेटी देख रही थी, लेकिन सारे फ़ैसले प्रधानमंत्री कार्यालय के कुछ अधिकारी ले रहे थे. तत्कालीन कोयला सचिव बार-बार पत्र लिखकर प्रधानमंत्री को बता रहे थे कि कोयला खदानों के आवंटन में नियमों की अनदेखी हो रही है, आवंटन के लिए नीलामी प्रणाली अपनानी चाहिए, लेकिन मनमोहन सिंह ने उनकी बात नहीं मानी. सवाल है कि आख़िर क्या वजह थी कि कोल ब्लॉक आवंटन के लिए नीलामी कराने के कोयला सचिव के सुझाव को प्रधानमंत्री कार्यालय ने नज़रअंदाज़ किया? जाहिर है, जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि पीएमओ में बैठे किस व्यक्ति या अधिकारी ने कोयला सचिव की राय खारिज की और किसके कहने पर ऐसा किया? क्या तत्कालीन प्रधानमंत्री देश को यह बताएंगे कि उनकी सरकार ने किस नियम के तहत कोल ब्लॉक आवंटन नीलामी के ज़रिये न कराकर पहले आओ-पहले पाओ की नीति पर किया? यह सब जानते हुए उन्होंने खदानों के आवंटन पर दस्तखत क्यों किए? क्या उन पर किसी का दवाब था? ऐसे कई सवाल हैं, जिनका जवाब मनमोहन सिंह को देना है. कांग्रेस पार्टी को डर यही है कि कहीं मनमोहन सिंह अपनी छवि बचाने के लिए सच न उगल दें. मनमोहन सिंह के सामने अब बस दो रास्ते हैं. एक यह कि वह इस घोटाले की ज़िम्मेदारी ले लें और इतिहास में एक भ्रष्ट प्रधानमंत्री के रूप में खुद को प्रस्तुत करें या फिर वह सच-सच सारी बातें बता दें.

जब विनाश मनुष्य पर आता है, पहले विवेक मर जाता है. यह कहावत कांग्रेस पार्टी और खासकर सोनिया गांधी पर अक्षरश: लागू होती है. पहले घोटाला करो, देश के संसाधन लुटवा दो. पकड़े जाने पर घोटाले से इंकार कर दो. मीडिया हो-हल्ला मचाए, तो जीरो लॉस थ्योरी देकर उसे शांत कर दो. सीएजी जब आरोप की पुष्टि कर दे, तो आंख दिखाओ और कहो कि वह अपनी औकात में रहे. और, जब सुप्रीम कोर्ट तलब करे, तो वहां जाकर झूठ बोल दो. सीबीआई की जांच का आदेश हो जाए, तो उसकी चार्जशीट बदल दो. पकड़े जाओ, तो कोर्ट में कहो कि यह एक नीतिगत फ़ैसला है और कोर्ट को इस पर बोलने का अधिकार नहीं है. कांग्रेस पार्टी और उसके वकील नेताओं को लगता है कि वे देश में अकेली ऐसी प्रजाति हैं, जिसके पास ज्ञानचक्षु है और बाकी पूरे देश की जनता मूर्ख है. कांग्रेस की यही सोच उसे रसातल में ले गई है. अगर कांग्रेस की यह सोच नहीं बदली, तो दिल्ली की तरह देश के राजनीतिक पटल पर उसका अस्तित्व शून्य रह जाएगा.■

कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात पर भरोसा नहीं किया और शपथपत्र देने के लिए कहा. कई बार मनमोहन सरकार के अटॉर्नी जनरल वाहनवती को फटकार लगाई गई. कई बार संसद के अंदर और बाहर सरकार को माफी मांगनी पड़ी. यह घोटाला ऐसा था, जिसे छिपाने के लिए कांग्रेस सरकार ने हरसंभव उपाय किए. तत्कालीन क़ानून मंत्री अश्विनी कुमार ने सीबीआई रिपोर्ट ही बदल दी. पकड़े जाने पर झूठ बोला कि उन्होंने सिर्फ़ रिपोर्ट का व्याकरण ठीक किया. कोर्ट ने जब कड़ा रुख अपनाया, तो सीबीआई ने स्वीकार किया कि सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट को पेश करने से पहले उसे क़ानून मंत्री और पीएमओ ने देखा तथा उसमें बदलाव भी कराए.

manishbph244@gmail.com

बिहार

हिस्सेदारी की दावेदारी

बिहार में कांग्रेस की स्थिति काफी दयनीय है. 1990 के विधानसभा चुनाव में वह सत्ता से बेदखल हुई थी और फिर निरंतर सिकुड़ती चली गई. उस चुनाव में अविभाजित बिहार विधानसभा की 72 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई थी. अगले चुनाव में वह पचास सीटों के आसपास सिमट गई और फिर उसके अगले चुनाव में 23 पर. राज्य की मौजूदा विधानसभा में कांग्रेस के पांच विधायक हैं. आसन्न विधानसभा चुनाव में उसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, यह कहना अभी मुश्किल है. इस अधोमुखी और ऐतिहासिक क्षरण की अपनी वजह है. जिन राजनीतिक ताकतों ने कांग्रेस का वोट बैंक तहस-नहस किया, पार्टी उनके लिए ही खाद बनती रही और उनकी दया पर विधानमंडल और संसद की दूरी तय करती रही.

सुकांत

बिहार में कांग्रेस की और कोई पहचान बची हो या नहीं, एक विशेषता ज़रूर शेष है, वर्चस्व का गुटीय संघर्ष. यहां कांग्रेस में जब कुछ नया या खास होता है, तो सूबे की राजनीति को पता लगने में थोड़ा भी विलंब नहीं होता यानी पार्टी का आंतरिक गुटीय सत्ता संघर्ष सड़कों पर आ जाता है. असंतुष्ट खेमों की गोलबंदी और दिल्ली दौड़ का सिलसिला अनायास शुरू हो जाता है. नई समिति बनी, तो विरोध होने लगा, अब तो इसमें प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की मांग जोड़ दी गई है. पटना में विरोधी खेमों की समान मांग पर गोलबंदी का सिलसिला चल रहा है, वहीं अनेक विक्षुब्ध नेता दिल्ली में जमे हैं. प्रदेश संगठन पर काबिज गुट विक्षुब्धों के अभियान को सत्ता से बेदखल समूहों की स्वाभाविक राजनीतिक प्रतिक्रिया मानकर उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझता. उसके लिए तो चुनावी साल में पार्टी को ज़्यादा धारदार बनाने के कार्यक्रम अमल में लाना सबसे बड़ी राजनीतिक ज़रूरत है. गंभीर से गंभीर मामला फुस्स बना देने की यह पुरानी और आजमाई हुई कांग्रेसी शैली है. सो, विक्षुब्ध खेमों के क्रियाकलापों से बेफिक्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी और उनकी टीम घोषित पदयात्रा कार्यक्रम की तैयारी में जुटी है.

चुनावी साल में राज्य में पार्टी को नए सिरे से पहचान देने या पुरानी पहचान ताजा बनाने के ख्याल से प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने बुद्ध से गांधी तक की पदयात्रा का कार्यक्रम तय किया है, जो बोधगया से शुरू होकर दो चरणों में भीतिहरवा (पश्चिम चंपारण) तक जाएगी और 25 मार्च की रात पटना पहुंचेगी. पहला चरण पूरा होने के बाद अगले चरण का कार्यक्रम तय किया जाएगा. पदयात्रा में प्रदेश कांग्रेस समिति के दो सौ पदाधिकारी शामिल होंगे. हर ज़िले या क्षेत्र में भी स्थानीय स्तर पर लोग इसमें हिस्सा लेंगे. प्रदेश नेतृत्व का दावा है कि किसी भी बिंदु पर चार-पांच सौ लोग यात्रा में होंगे. कांग्रेस की यह पदयात्रा अपने दो उल्लेखनीय कार्यों की रक्षा या उनके बारे में लोगों को पूरी जानकारी देने के लिए आयोजित की गई है. कांग्रेस का मानना है कि मौजूदा केंद्र सरकार मनरेगा के नियम-कायद बदल कर ग़रीब ग्रामीणों को रोज़गार से वंचित करने की तैयारी कर रही है और इस कार्यक्रम में मशीनों के इस्तेमाल की योजना बनाई जा रही है. यह रोज़गार गारंटी कार्यक्रम बचाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करना ज़रूरी है.

पदयात्रा का दूसरा मकसद भूमि अधिग्रहण क़ानून में किसान विरोधी बदलाव का विरोध करना है. यूपीए सरकार ने 2013 में जो क़ानून पास कराया था, उसमें किसानों के हितों की रक्षा की गई थी, लेकिन एनडीए सरकार ने वे सारे प्रावधान समाप्त कर दिए हैं. इस मसले पर किसानों को गोलबंद किया जाएगा. भूमि अधिग्रहण क़ानून में बदलावों के लिए जारी अध्यादेश के विरोध में बिहार में कई स्थानों पर धरने दिए गए थे, जिनकी हालत क्या रही, बताने की ज़रूरत नहीं है. पदयात्रा किस हद तक सफल होती है, यह देखना बाकी है. हालांकि, कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा से लोगों का मोह निरंतर भंग हो रहा है, लिहाजा वे राष्ट्रीय स्तर पर उसकी ओर रुख करेंगे. वजह, राष्ट्रीय स्तर पर वही भाजपा की मुखालफत कर रही है. कांग्रेस का संकट है कि उसके नेता (दिल्ली से लेकर ज़िला स्तर तक) यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि पार्टी निरंतर सिकुड़ती जा रही है और उन सभी राज्यों में उसकी ज़मीन छिन चुकी है, जहां कोई तीसरी राजनीतिक ताकत सक्रिय है.

बिहार में कांग्रेस की स्थिति काफी दयनीय है. 1990 के विधानसभा चुनाव में वह सत्ता से बेदखल हुई थी और फिर निरंतर सिकुड़ती चली गई. उस चुनाव में अविभाजित बिहार विधानसभा की 72 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई थी. अगले चुनाव में वह पचास सीटों के आसपास सिमट गई और फिर उसके अगले चुनाव में 23 पर. राज्य की मौजूदा विधानसभा में कांग्रेस के पांच विधायक हैं. आसन्न विधानसभा चुनाव में उसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, यह कहना अभी मुश्किल है. इस अधोमुखी और ऐतिहासिक क्षरण की अपनी वजह है. जिन राजनीतिक ताकतों ने कांग्रेस का वोट बैंक तहस-नहस किया, पार्टी उनके लिए ही खाद बनती रही और उनकी दया पर विधानमंडल और संसद की दूरी तय करती रही. भागलपुर दंगे के बाद कांग्रेस के सामाजिक समर्थक आधार समूह क्षत-विक्षत हो गए, अल्पसंख्यक समुदाय जनता दल के साथ चला गया. फिर मंडल लहर में दलित एवं अति पिछड़ा तबका कांग्रेस से टूटकर लालू प्रसाद के साथ गया, वहीं अगड़ा समुदाय भाजपा की तरफ़ मुड़ गया. कांग्रेस ने इन तमाम राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण किए बगैर लालू प्रसाद के कंधे पर चढ़कर कुछ हासिल करने को ज़्यादा फ़ायदेमंद समझा और शॉर्टकट की राजनीति के तहत अपने 23 में से 22 विधायकों को राबड़ी सरकार में मंत्री बनवा लिया. आम कांग्रेसी अब तक नहीं समझ सके कि अपनी राजनीति को धारदार बनाकर जनता का विश्वास हासिल करने के बजाय पार्टी नेतृत्व ने कंधे की राजनीति को तरजीह क्यों दी? पार्टी ने मंडल-कमंडल की अतिवादी राजनीति से दूरी रखने वाले बिहारी मतदाता समूहों के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा, जिन्हें मजबूरन इधर-उधर जाना पड़ा और पार्टी चुनावी अखाड़े में नए-नए पराभव भोगने को विवश हो गई. बिहार की राजनीति में कांग्रेस की हैसियत अब सदाकत आश्रम और मीडिया तक सीमित रह गई है.

इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस एक बार फिर चुनावी अखाड़े में उतरने की तैयारी कर रही है. यह भी तय है कि आसन्न विधानसभा चुनाव में वह प्रस्तावित एकीकृत जनता परिवार के साथ रहेगी. यदि किसी कारण जनता परिवार के घटकों (लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के दलों) का विलय नहीं हुआ, तो उनमें से दोनों या किसी एक के साथ कांग्रेस को तालमेल करना होगा. उस राजनीतिक परिस्थिति में तालमेल लालू प्रसाद के राजद या नीतीश कुमार के जद (यू) के साथ होगा, कहना कठिन है. दोनों के पक्ष-विपक्ष में बिहार कांग्रेस में गोलबंदी है. लेकिन, इतना तय है कि किसी भी हालत में कांग्रेस के खाते में 40 से अधिक सीटें नहीं आनी हैं. यह भी तय है कि इन सीटों के उम्मीदवारों के चयन में सहयोगी दल के प्रमुख की भूमिका बड़ी होगी. पिछले कई चुनावों का अनुभव यही रहा है. कांग्रेस के कई पुराने प्रबंधकों का मानना है कि पार्टी की आंतरिक खेमेबंदी का मकसद दबाव बनाकर चुनाव में अपनी सौदेबाजी की ताकत बढ़ाना भर है. बिहार में पिछले कई वर्षों से कांग्रेस में नए खून का प्रवेश लगभग बंद है. हालांकि, सदस्यता अभियान के बाद सदस्यों की संख्या बढ़ी है, पर उनमें युवाओं की संख्या काफी कम रही. हर खेमे का नेता चुनाव में अपना हिस्सा चाहता है, खुद के लिए भी और अपने खास लोगों के लिए भी. पार्टी के पुराने गुमनाम प्रबंधक आंतरिक खेमेबंदी तेज होने के लिए इसी चाहत को ज़िम्मेदार मानते हैं. क्या बिहार में कांग्रेस नेताओं की यह चाहत दिल्ली नहीं समझ पा रही है?■

feedback@chauthiduniya.com

महिलाओं की सुध सिर्फ़ दिवस विशेष पर!

अंशिका वाजपेयी

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (आठ मार्च), साल का एक ऐसा दिन, जब हर किसी को महिलाओं के प्रति विचार व्यक्त करना अपना कर्तव्य लगता है. ऐसा लगता है, जैसे श्रद्धांजलि दी जा रही हो. वह भी उन्हें, जो अभी जीवित हैं. सुनने में कुछ वैसा ही लगता है, जैसे कुछ तथाकथित भक्तगण मंगलवार और शनिवार को मुर्गा नहीं खाते, जैसे बाकी दिन खाने पर ऊपर वाला बड़ा प्रसन्न होगा. क्षमा चाहती हूं, अगर ये तेवर आपको रास न आए हों. आपकी सोच भी ग़लत नहीं है. इस दिन तो लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सानिया मिर्जा, कल्पना चावला और इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हैं. लेकिन चलिए, आज ढूंढते हैं उस महिला को, जो अपने आपको खुशनसीब समझती है कि अभी तक किसी ने एसिड (तेजाब) डालकर उसका चेहरा नहीं जलाया, उसके साथ बलात्कार नहीं किया और वह अब तक जीवित है. वह, जो अपनी तमाम प्रतिभा एवं मेधा के बावजूद केवल औरत जात रह गई. वह, जिसका साक्षरता प्रतिशत बढ़ा तो ज़रूर है, मगर जीवन में प्रयोग के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छी नौकरी में लगे लड़के की पात्रता अर्जित करने के उद्देश्य से. वह, जिसने बोर्ड परीक्षा में अपने विद्यालय के सभी लड़कों को पछाड़ा था, मगर जिसका विवाह गोरे रंग के अभाव में नहीं हो सका. वह, जिसने साहित्य में उच्च शिक्षा ग्रहण की है, जिसके घर में दुनिया की हर सुख-सुविधा उपलब्ध है, मगर किताब सिर्फ़ एक, भारतीय पाक प्रणाली. चाहे वह कितना भी पढ़ ले, है तो औरत जात ही. और, उसे यह ध्यान रखना पड़ेगा कि पति के दिल का रास्ता पेट से होकर गुज़रता है. लेकिन, इन सारी महिलाओं की याद हमें इस दिवस विशेष को ही क्यों आती है?

कोपेनहेगन में हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक ऐसे दिन की घोषणा की थी, जो प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति-धर्म-संप्रदाय की महिलाओं का महत्व पहचानने का दिन होगा और हमें उस वाकए की याद दिलाएगा, जब महिलाओं ने घर की चाहरदीवारी से निकल कर अपने अधिकारों के लिए पहली बार आवाज़ उठाई थी. जी हां, आठ मार्च, 1857 को अमेरिका की कपड़ा मिलों में काम करने वाली महिलाओं ने अपने साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध एक मुहिम छेड़ी थी. उनकी लड़ाई निरंतर चलती रही और उन्होंने संगठित होकर अपना लक्ष्य हासिल करने की दिशा में प्रयास किए, ताकि महिलाओं को कार्यक्षेत्र में सुविधाएं, वोट देने का अधिकार, शोषण से मुक्ति और बेहतर आय मिल सके. भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो नारी आदिकाल से ही अपने स्वतंत्र अस्तित्व की स्वामिनी रही है. प्राचीन काल में भी वह गार्गी, मैत्रेयी एवं विद्योतमा के रूप में याज्ञवल्क्य एवं मंडन मिश्र जैसे पंडितों से शास्त्रार्थ करती आई है. इसी आधार पर अर्द्धनारीश्वर की कल्पना भी की गई, मगर स्त्री और पुरुष का यह विवेकपूर्ण सामंजस्य टूटा मुगल काल में, जब मुगलों ने हमारे देश पर आक्रमण करके हमारी व्यवस्था छिन्न-भिन्न कर दी और सदा स्वछंद भारतीय नारी पर्दे की ओट में आने को विवश हो गई.

दरअसल यह दबाव, यह निरीहता किसी सभ्यता और काल सापेक्ष नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत संपत्ति के उदय के साथ ही पशुओं एवं पुत्रों के प्रति समाज के बढ़ते हुए मोह का मूर्त रूप है. आदिम समाज में इस बात की पुष्टि केवल एक स्त्री ही कर सकती थी कि उसकी संतान का पिता आख़िर है कौन? समय बदला, समाज बदला, व्यवस्थाएं बदलीं, मगर तबसे जो स्त्री कैद हुई, वह आज भी आज़ादी का मुंह नहीं देख पाई. आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, हमारा संविधान हमें अपनी भावनाएं व्यक्त करने, अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने एवं समानता जैसे कई अधिकार देता है, मगर व्यवहारिकता के स्तर पर ऐसे अधिकांश क़ानून मात्र काठ की तलवार ही सिद्ध होते हैं. प्रसिद्ध फ्रांसीसी नारीवादी लेखिका सिमोन द बोवार के अनुसार, महिलाएं पैदा नहीं होतीं, बल्कि बना दी जाती हैं. सामाजिक लिंग अर्थात जेंडर की अवधारणा समाज में महिलाओं के दोयम दर्जे की पक्षधर नज़र आती है. अच्छी लड़की व अच्छे लड़के से जुड़े सामाजिक अपेक्षाओं के खांचे जन्म से पहले ही खींच दिए जाते हैं और जीवन भर हमें प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि हम उनमें फिट बैठ सकें. विवाह जैसी घटना एक स्त्री व पुरुष, दोनों के जीवन में घटित होती है, मगर सुहागन का चिन्ह और विधवा का विषाद केवल औरत के हिस्से में आता है. महिलाओं का जन्म प्रभावित होता है, शिक्षा प्रभावित होती है, कामकाज भी प्रभावित होता है, क्योंकि एक दिन उन्हें मां बनना है.

दुनिया की 95 फ़ीसद कामकाजी महिलाएं कम वेतन, कम यात्रा और कम समय वाली नौकरियों में हैं, जिसका सीधा मतलब है, कम आय. एक ताजा अमेरिकी शोध के अनुसार, महिलाएं दुनिया का 60 फ़ीसद काम करती हैं, लेकिन दुनिया की 10 फ़ीसद उनके हिस्से आती है और वे दुनिया की केवल एक फ़ीसद संपत्ति की मालिक हैं. आज भी लड़कियों के छात्रावासों के दरवाजे शाम होते ही भेड़-बकरियों के बाड़ों की तरह बंद कर दिए जाते हैं. एक छात्र अपनी ज़रूरत के मुताबिक इधर-उधर जा सकता है, मगर एक छात्रा की ज़रूरत कोई मायने नहीं रखती. एक पुरुष अपनी रुचि, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कपड़े पहनेगा. जबकि एक स्त्री क्या पहनती है, इसका निर्धारण उसकी ज़रूरत या पसंद नहीं, बल्कि समाज करेगा. पिताओं की चिंताओं के बावजूद, ऋण लेकर दिए गए दहेज के बावजूद, शिक्षित एवं कमाऊ होने के बावजूद आज भी अक्सर महिलाओं की ज़िंदगी एक टीवी, फ्रिज, सोफा और कार में सिमट कर रह जाती है.

यह देश, यह आज़ादी और ये तमाम सड़कें, इन सब पर महिलाओं का उतना ही हक़ है, जितना पुरुषों का. अब समय आ गया है कि महिलाएं अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथ में लें. बेटियों की पोशाक पर ही नहीं, बेटों की मानसिकता पर भी ध्यान दें. संस्कारों को शिक्षा के तराजू में तौलें, आंचल में है दूध और आंखों में पानी वाली छवि तोड़कर बाहर निकलें. बेशक, ग़लतियां करें, मगर उनसे सीखें. समाज में लगातार निर्णायक हस्तक्षेप करके अपनी प्रतिभा-क्षमता का शंखनाद करें और डटकर ज़िंदगी से दो-दो हाथ करें. पीछे मुड़कर देखें, यह अनुभव करें कि हम कितनी लंबी यात्रा तय करके यहां तक पहुंचे हैं, कितनी लंबी यात्रा अभी और तय करनी है. कितने अन्याय, असमानता एवं शोषण के ख़िलाफ़ हमें हर दिन आवाज़ उठाने की आवश्यकता है. और, उस दिन बराबरी के अधिकार, बराबरी से मिले संसाधन यह सिद्ध कर देंगे कि समाज संवेदनशील है, विचारधारा स्वस्थ है और अब अलग से महिला दिवस मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. यानी अब तेरे बारे में नया इतिहास लिखा जाएगा, आंखों में पानी नहीं आग लिखा जाएगा...■

(लेखिका राष्ट्रीय महिला आयोग की कोआर्डिनेटर हैं)

दुनिया की 95 फ़ीसद कामकाजी महिलाएं कम वेतन, कम यात्रा और कम समय वाली नौकरियों में हैं, जिसका सीधा मतलब है, कम आय. एक ताजा अमेरिकी शोध के अनुसार, महिलाएं दुनिया का 60 फ़ीसद काम करती हैं, लेकिन दुनिया की 10 फ़ीसद उनके हिस्से आती है और वे दुनिया की केवल एक फ़ीसद संपत्ति की मालिक हैं.

यह देश, यह आज़ादी और ये तमाम सड़कें, इन सब पर महिलाओं का उतना ही हक़ है, जितना पुरुषों का. अब समय आ गया है कि महिलाएं अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथ में लें. बेटियों की पोशाक पर ही नहीं, बेटों की मानसिकता पर भी ध्यान दें. संस्कारों को शिक्षा के तराजू में तौलें, आंचल में है दूध और आंखों में पानी वाली छवि तोड़कर बाहर निकलें. बेशक, ग़लतियां करें, मगर उनसे सीखें. समाज में लगातार निर्णायक हस्तक्षेप करके अपनी प्रतिभा-क्षमता का शंखनाद करें और डटकर ज़िंदगी से दो-दो हाथ करें. पीछे मुड़कर देखें, यह अनुभव करें कि हम कितनी लंबी यात्रा तय करके यहां तक पहुंचे हैं, कितनी लंबी यात्रा अभी और तय करनी है. कितने अन्याय, असमानता एवं शोषण के ख़िलाफ़ हमें हर दिन आवाज़ उठाने की आवश्यकता है.

> न्यायालय में प्रस्तुत आरोप पत्र में मुख्य आरोपी पंकज त्रिवेदी ने बयान दिया था कि परीक्षा के पूर्व से समय–समय पर प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव आते रहे तथा पीएमटी 2012 में उन लोगों को चयनित कराने के लिए दबाव बनाया, जिनके अत्यधिक दबाव के कारण मैंने कंप्यूटर शाखा के प्रभारी नितिन महिंद्रा एवं चंद्रकांत मिश्रा से चर्चा करके अभ्यार्थियों को पास कराने के लिए योजना तैयार की. अन्य परीक्षाओं के संबंध में मुझे वरिष्ठ लोगों से, जिनमें अधिकारी नेता शामिल हैं, अलग अलग समय में लिस्ट दी थी.

स्टिंग वार : आम आदमी पार्टी में घमासान

चौथी दुनिया ब्यूरो

ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी और विवादों का जन्म–जन्मान्तर का रिश्ता है. अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस पार्टी को अप्रत्याशित जीत दिलाने वाले मतदाताओं की उंगलियों से मतदान के वक्त लगाई जाने वाली सियाही मधिम भी नहीं पड़ी थी कि पार्टी एक बार फिर अन्त:कलह और कई गंभीर आरोपों के घेरे में आ गई. भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन से उपजी और दूसरी अन्य पार्टीयों से अलग राजनीति करने का दावा करने वाली पार्टी अब खुद भी वैसे ही आरोपों के घेरे में नज़र आ रही है, जो आरोप यह दूसरी पार्टियों पर लगाती थी. हालांकि मौजूदा विवाद के संकेत लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिली करारी हार के बाद ही दिखाई देने लगे थे, लेकिन हाल ही में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी की संसदीय मामलों कि समिति (पीएसी) से छुट्टी के बाद अब यह मामला पार्टी से बहार आ गया है. पार्टी अभी योगेन्द्र यादव और प्रशांत भूषण की पीएसी से हटाए जाने से उत्पन्न हालात से निपट ही रही थी कि इस विवाद की अगली कड़ी के रूप में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग का स्टिंग सामने आ गया. उसके बाद तो जैसे स्टिंग का सिलसिला चल निकला और पार्टी के खिलाफ दो और स्टिंग की बात की गई.

बहरहाल, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारणी की 4 मार्च की मीटिंग के बाद योगेन्द्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएसी से हटा दिया गया. इन दोनों पार्टी के संस्थापक सदस्यों पर यह इलज़ाम लगाया गया कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी को हराने की कोशिश की. चंदा देने वालों को चंदा देने से रोका. बाहर से आने वाले वॉलनटीयर्स को दिल्ली आने से मना किया, अरविंद केजरीवाल की छवि को ख़राब करने के लिए योगेन्द्र यादव ने अखबारों में नेगेटिव ख़बरें छपवाईं. उदाहरण के लिए अगस्त 2014 में दी हिन्दू अख़बार में छपी खबर, जिसमें अरविंद और पार्टी की एक नकारातमक तस्वीर पेश किया गया. अवाम नामी संस्था के प्रशांत भूषण और शांति भूषण द्वारा खुलकर खुल कर समर्थन देने की बात की गई. यह वही संस्था थी, जिसने आम आदमी पार्टी पर गलत तरीके से चंदा इकट्ठा करने का आरोप लगाया था. शांति भूषण के उस बयान को, जिसमें उन्होंने भाजपा के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार किरण बेदी को केजरीवाल से बेहतर उम्मीदवार बताया था, एक कारण बताया गया. बहरहाल, प्रशांत भूषण और योगेन्द्र यादव के पीएसी से हटाए जाने पर मयंक गांधी ने एक ब्लॉग लिख कर राष्ट्रीय कार्यकारणी के फैसले पर अपनी आपत्ति जताई. बाद में प्रशांत भूषण और योगेन्द्र यादव ने कहा कि सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी. उसके बाद पार्टी नेता मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, पंकज गुप्ता और संजय सिंह ने अधिकारिक तौर पर इन दोनों लोगों पर आठ आरोपों की एक सूचि जारी की, जिसे फेसबुक, ट्विटर पर प्रकाशित किया गया. जवाब में योगेन्द्र यादव और प्रशांत भूषण ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम एक खुली चिट्ठी में इन आरोपों पर अपनी सफाई पेश की.

बहरहाल, जहां तक राजेश गर्ग के ऑडियो टेप का मामला है, तो इसके तार ऊपर के घटना से मिले हुए मालूम होते हैं, क्योंकि अगर राजेश गर्ग पार्टी को इस ऑडियो स्टिंग के ज़रिये नुकसान पहुंचाना चाहते तो वह उससे चुनावों के दौरान आम करके पार्टी को अधिक नुकसान पहुंचा सकते थे. इसलिए पार्टी द्वारा उन पर यह आरोप लगाना कि टिकट नहीं मिलने से आहत होकर उन्होंने इस स्टिंग को आम किया है, कुछ तर्कसंगत नहीं लगता है. राजेश गर्ग ने अपना पक्ष रखते हुए एक टीवी न्यूज़ शो में यह साफ किया कि वह ऑडियो लेकर मीडिया के पास नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने इस टेप को कुमार विश्वास को ईमेल किया था, ताकि वह इससे पीएसी या पार्टी लोकपाल की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाएं. अगर गर्ग की बातों को सच मान लिया जाए तो यह टेप पार्टी के किसी ज़िम्मेदार ने ही लीक किया है. और दूसरी तरफ योगेन्द्र यादव और प्रशांत भूषण जो यह कह रहे थे कि सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, तो कहीं वे इसी सच्चाई की बात तो नहीं कर रहे थे? क्योंकि इस स्टिंग के बाद दो और स्टिंग की बात चली, जिसमें से एक का सम्बन्ध खुद को आम आदमी पार्टी की अल्पसंख्यक इकाई का सेक्रेटरी कहने वाले शहीद आज़ाद से है. आज़ाद ने यह दावा किया है कि उनके पास एक ऑडियो है, जिसमें केजरीवाल कथित रूप से चुनाव में मुसलमानों को टिकट नहीं दिए जाने की बात करते सुनाई दे रहे हैं. उधर, कांग्रेस नेता और ओखला के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान यह दावा कर रहे हैं कि उनके पास भी आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का स्टिंग है, जिसमें संजय ने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए समर्थन के बदले उन्हें मंत्री पद का लालच दिया था. दरअसल, कुछ और तथ्य भी हैं, जो इन स्टिंग को संदेह के घेरे में डालते हैं. उनमें से एक है प्रशांत भूषण और योगेन्द्र यादव का कार्यकर्ताओं के नाम लिखा ख़त, जिसमें केजरीवाल द्वारा कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में दोबारा सरकार बनाने की कोशिश करने की बात की गई है.

दरअसल, इन सभी स्टिंग के केंद्र में दिल्ली चुनाव हैं. अब ज़रा ऑडियो टेप में कही गई बातों पर एक नज़र डालते हैं. राजेश गर्ग के टेप में केजरीवाल यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर समर्थन नहीं दे रही है तो वो 6 विधायक अपनी पार्टी तोड़ कर हमें बाहर से समर्थन दे दें. जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान ने कहा है कि उस समय उनकी पार्टी पॉलिटिकल रीअलाईन्मेंट (राजनीतक पुनर्गठन) का प्रयास कर रही थी. अब सवाल यह उठता है कि जो पार्टी दूसरी पार्टियों की इन्हीं गतिविधियों को बुनियाद बना कर वजूद में आई हो, वही ऐसा करने लगे तो इसको समर्थन देने वाले लोग खुद को ठगा हुआ नहीं महसूस करेंगे? हालांकि इस स्टिंग में पैसे की लेन–देन या खरीद–फरोख्त की बात नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस नेता आसिफ ने खरीद–फरोख्त का भी आरोप लगा दिया है. इन स्टिंग का एक दूसरा तथ्य यह भी है कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में इमाम बुखारी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की तो केजरीवाल द्वारा यह कह कर मना कर दिया गया कि वे इस तरह की सियासत नहीं करते, जिसमें धर्म गुरुओं से समर्थन मांगा जाए, लेकिन खुद केजरीवाल एक ऑडियो में यह कहते हुए सुने गए कि मुसलमान विधायक भाजपा में नहीं जाएंगे और उन्हें ही समर्थन दे देंगे. इससे उनका दोहरा मापदंड उजागर होता है कि एक तरफ तो वह मौलाना बुखारी का समर्थन यह कह कर लेने से मना कर देते हैं कि उनकी पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती. वहीं दूसरी तरफ वे मुसलमान विधायकों का समर्थन लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वे मुसलमान होने की वजह से भाजपा को समर्थन नहीं दे सकते.

दरअसल, अभी तक आम आदमी पार्टी में शुरू हुआ यह घमासान समाप्त नहीं हुआ है. जहां एक तरफ केजरीवाल समर्थक खेमा योगेन्द्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से निकाले जाने की जी–तोड़ कोशिश कर रहा है. वहीं, अब योगेन्द्र यादव का खेमा भी आस्तीने चढ़ा कर दो–दो हाथ करने की मुद्रा में आ गया है. अभी यह देखना बाकी है कि इस लड़ाई में बाजी इन दोनों पक्षों में से एक के हिस्से में आती है या कोई तीसरा पक्ष इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठा लेता है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की जो सबसे बड़ी विडम्बना है, वह यह है कि कल तक अरविन्द केजरीवाल जनता से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए स्टिंग करने और स्टिंग से बचने का प्रवचन दिया करते थे और आज वह खुद अपने ही एक सहयोगी द्वारा किए गए स्टिंग का शिकार हो गए. यानी ***उलझा है पांव यार के जुल्फ–ए–दराज़ में/लो आप अपने दाम (कैद) में सय्याद (शिकारी) आ गया.*** ■

feedback@chauthiduniya.com

व्यापमं घोटाला

बैकफुट पर शिवराज सरकार

नवीन चौहान

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल भर्ती मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार बैकफुट पर नज़र आने लगी है. दिन–ब–दिन यह मामला बड़ा होता जा रहा है. व्यापमं मामले की वजह से विधानसभा के बजट सत्र को समय से एक महीने पहले ही सरकार को खत्म करना पड़ा. इस मामले की आंच राजभवन तक पहुंचने से यह बात तो साबित हो गई है कि इस घोटाले को ऊंचे स्तर पर निर्देशित किया गया है. जब प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, तब उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर भी लोग हैं और उनकी तरफ से अनुशंसायें आईं थीं. अब इस मामले में प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. उनपर आरोप है कि उन्होंने तीन उम्मीदवारों को फर्जी तरीके से वन रक्षक भर्ती परीक्षा में अपने पद का दुरुपयोग कर पास करवाया. हालांकि उन्होंने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को अदालत में इस आधार पर चुनौती दी है कि वह संवैधानिक पद पर हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है, लेकिन इससे पहले राज्यपाल के ओएसडी और उनके बेटे शैलेश यादव का नाम इस घोटाले में आ चुका है. इस घोटाले के प्रमुख आरोपी पंकज त्रिवेदी डेढ़ साल में करीब छह बार राजभवन गया था. इस बात का खुलासा राजभवन की विजिटर्स लॉगबुक से हुआ है. इस लॉगबुक को एसटीएफ एफआईआर दर्ज करने से पहले ही जब्त कर चुकी है. यह राज्यपाल और उनके बेटे के खिलाफ सबसे अहम सबूत साबित हो सकता है.

न्यायालय में प्रस्तुत आरोप पत्र में मुख्य आरोपी पंकज त्रिवेदी ने बयान दिया था कि परीक्षा के पूर्व से समय–समय पर प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव आते रहे तथा पीएमटी 2012 में उन लोगों को चयनित कराने के लिए दबाव बनाया, जिनके अत्यधिक दबाव के कारण मैंने कंप्यूटर शाखा के प्रभारी नितिन महिंद्रा एवं चंद्रकांत मिश्रा से चर्चा करके अभ्यार्थियों को पास कराने के लिए योजना तैयार की. अन्य परीक्षाओं के संबंध में मुझे वरिष्ठ लोगों से, जिनमें अधिकारी नेता शामिल हैं, अलग अलग समय में लिस्ट दी थी. इसी तरह के घोटाले की वजह से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला अपने बेटे के साथ सजा काट रहे हैं. शिवराज सिंह चौहान पिछले साल विधानसभा में यह स्वीकार कर चुके हैं कि 1000 से ज्यादा अपात्र लोग इस घोटाले की वजह से प्रदेश में नौकरियां पा चुके हैं. कुल मिलाकर व्यापमं द्वारा आयोजित 13 परीक्षायें जांच के दायरे में आ चुकी हैं. 14 महीने की एसआईटी जांच के बाद लगभग 1500 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

यह मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं रह गया है. यदि किसी मुख्यमंत्री को देश के ईमानदार नेताओं में से एक माना जाता है तो उसके 10 साल के शासन काल में लंबे समय तक इस तरह की धांधली हो तो यहां बात नैतिकता की आ जाती है. भले ही अभी सबूत मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में इतने बड़े स्तर पर घोटाले को अंजाम दिया गया, तो इसे सीधे–सीधे उनके कर्तव्य निर्वहन में उनकी विफलता माना जाएगा. यह शिवराज के राज में सबसे बड़ा दाग है. इससे न जाने कितने युवाओं का भविष्य खराब हो गया. इसकी सीधी–सीधी जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री की है, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला यदि किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हो तो वह जवाबदेही से नहीं बच सकता है. इसी वजह से प्रदेश में विपक्ष आक्रामक है और प्रदेश की आम जनता के मन में राज्यपाल जैसे बड़े लोगों के इस मामले में फंसने से सवाल खड़े हो रहे हैं. इसलिए सरकार के लिए बेहतर होगा कि वह इस मामले से सभी लोगों के नाम सार्वजनिक करें और उन दस्तावेजों का खुलासा करें, जिस आधार पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 1000 लोगों के फर्जी तरीके से भर्ती होने की बात स्वीकार की थी. यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो आमजन का प्रदेश सरकार से विश्वास उठ जाएगा.

हालांकि कांग्रेस पार्टी काफी पहले से इस मामले की जांच कई बार सीबीआई से कराने की मांग कर चुकी है. राज्यपाल का नाम मामले में आने के बाद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस ने मामले की जांच कर रही एसआईटी को एक केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के एक केंद्रीय मंत्री और राज्य के कुछ आला अधिकारियों के खिलाफ दस्तावेज सौंपे हैं और एसआईटी से मांग की है कि वह इन दस्तावेजों की जांच कर उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करे.

दस्तावेज प्रस्तुत करते समय कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया और वकील केटीएस तुलसी मौजूद थे. इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि व्यापमं घोटाले में शिवराज सिंह और उनका परिवार शामिल है. कांग्रेस ने जांच में मुख्यमंत्री और उनके परिवार को बचाने एवं एसटीएफ के सीएम के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया है और कहा कि आरोपियों से सीज किए गए कंप्यूटर से प्राप्त दस्तावेजों से छेड़छाड़ की गई है. हालांकि कांग्रेस एक बार फिर इस मुद्दे के बल पर प्रदेश में अपनी खोई जमीन वापस पाना चाहती है.

व्यापमं घोटाला संघर्ष समिति के सदस्य मनीष काले ने बताया कि समिति ने 2 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन किया था. वे लोगों से लगातार मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनसे अपने बच्चों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ के लिए जिम्मेदार कौन, जैसे सवाल पूछ रहे हैं. लोग चाहते हैं कि इस घोटाले की जवाबदेही तय हो. वेटिंग लिस्ट के छात्रों को सभी आयामों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश दिया जाए. सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था निर्मित की जाए. फिलहाल इस मामले की जांच हाई कोर्ट की देखरेख में हो रही है. इसलिए अपेक्षा की जानी चाहिए कि इस मामले में सारा सच सामने आएगा. बावजूद इसके, इस कांड ने राज्य की भाजपा सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया है. इससे उसकी छवि प्रभावित हुई है. इसे लेकर विधानसभा में जो हंगामा हुआ है, उसके बाद शिवराज की दिल्ली यात्रा को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि व्यापमं मामले के संबंध में ही आलाकमान ने उन्हें दिल्ली बुलाया था, लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि आखिरकार सरकार व्यापमं के मुद्दे पर इस तरह का रवैया क्यों अपना रही है. यदि प्रदेश सरकार को मालूम है कि एक हजार नियुक्तियां गलत तरीके से हुई हैं तो उन्हें अब तक उन्हें रद्द क्यों नहीं किया गया? उन रिक्तियों में भर्ती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये सारे सवाल सरकार के लिए लगातार परेशानी का सबब बने हुए हैं. सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह इन सवालों के जवाब दे. अन्यथा शिवराज के राज को इतिहास में जंगलराज के नाम से जाना जाएगा.

जिस घोटाले को देश का अब तक का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला बताकर प्रचारित किया जा रहा हो, उसके बारे में उठ रही हर शंका का जवाब सरकार को प्रदेश की जनता को देना चाहिए था. सरकार के पास प्रदेश के 6 करोड़ लोगों के बीच अपनी बात रखने का विधानसभा से बड़ा कोई स्टेज नहीं हो सकता है. सरकार का व्यापमं मामले में विधानसभा सत्र को समय से पहले खत्म कर देने से यही जाहिर होता है कि सरकार बैकफुट पर है और अपने बचाव की राह तलाश रही है. ■

navinonline2003@gmail.com

पहले किसानों, मज़दूरों और ग़रीबों की बात हो

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

केएन गोविंदाचार्य को इस देश में भला कौन नहीं जानता. प्रसिद्ध चिंतक-विचारक, आरएसएस के पूर्व प्रचारक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महासचिव गोविंदाचार्य एक स्थायी क्रांतिकारी हैं. जेपी आंदोलन हो, गंगा बचाओ आंदोलन हो, स्वदेशी आंदोलन हो या फिर अन्ना हजारे के नेतृत्व में चल रहा भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन हो, गोविंदाचार्य हर जगह नज़र आए. पिछले दिनों चौथी दुनिया के संपादक समन्वय मनीष कुमार ने उनसे एक लंबी बातचीत की. पेश है, उसके प्रमुख अंश...

आरएसएस और भाजपा के साथ आपके क्या रिश्ते हैं?

मैं संघ का एक सामान्य स्वयंसेवक हूं. संघ की शाखा में जो भी एक बार जाता है, उसे ज़िंदगी भर के लिए संघ का स्वयंसेवक माना जाता है. देश के 40 लाख स्वयंसेवकों में से मैं भी एक हूं, लेकिन भाजपा का तो मैं प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूं.

अन्ना हजारे भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे हैं. आख़िर इस आंदोलन का ध्येय क्या है और वह क्या हासिल करना चाहते हैं?

पहली बात, आंदोलन करना मेरी हॉबी या शगल हो, ऐसा नहीं है. टकराव मेरा स्वभाव भी नहीं है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से आवाज़ उठाना और न कहना भी समाज की ताकत लिए ज़रूरी है. अभी जो स्थिति है, उसमें भूमि अधिग्रहण की बात तो कही जाती है, पर भइया, किसानों को ज़मीन देने की भी तो बात करो. जो ज़मीन अब तक सरकारों ने ली है, उसका हिसाब-किताब भी तो जनता के सामने पेश करो. कितनी ज़मीन ज़रूरी है और किस बात के लिए ज़रूरी है, यह तो बताओ. बिना यह सब किए ज़मीन लेकर जेब में भर लेना विकास का तरीका नहीं है. इसमें तो नीयत में ही गड़बड़ी है, ऐसी गंध आती है.

यह जो बिल अध्यादेश के रूप में लाया गया, इसमें ऐसी कौन-सी चीजे हैं, जिन पर आप कोई समझौता नहीं कर सकते?

अगर आप अखिल ग्रामसभा की अनुमति के बगैर ऐसा कर रहे हैं, तो देश के लोकतंत्र की सर्वोच्च इकाई की उपेक्षा कर रहे हैं, जो बहुत घातक है. इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूं. उसी प्रकार यदि ज़मीन की क़ीमत सिर्फ़ मुआवजे के नाते देते हैं, तो यह ग़लत है. ज़मीन भारत में जीवनशैली का हिस्सा है. पीढ़ी दर पीढ़ी का हिसाब है उसमें. आप मुआवजे से इसे कैसे पूरा कर सकते हैं. दूसरा सवाल है कि आपने इसमें इंडस्ट्रियल कॉरीडोर जोड़ दिया और पहले जो ज़मीन ली है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? सरकार मुआवजे की बात बार-बार करती है, चार गुना करने की बात करती है. एक जगह है मालचा. वहां के लोगों को सौ साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन मुआवजा नहीं मिला. दामोदर घाटी के निर्वासितों को पचास साल से मुआवजा नहीं मिला. इसके लिए एक फुलप्रूफ प्लान बताना होगा कि पहले ही पूरा भुगतान करेंगे या ज़मीन लेकर मुआवजा लटका दिया जाएगा. मान लीजिए आंध्र प्रदेश में नई राजधानी बन रही है, इसके लिए ज़रूरत से छह गुना ज़्यादा ज़मीन ली जा रही है. ये सब बाद में लैंड यूज में कन्वर्ट हो जाएगी और अंत में भू-माफियाओं के पास पहुंच जाएगी. सरकार भूमिधरों को ज़मीन से वंचित करे और भूमिहीनों के आवास की व्यवस्था भी न करे, तो फिर सरकार किस बात की? सरकार का गठन हुआ ही इसके लिए है कि वह उनका बचाव करे, जो खुद का बचाव नहीं कर सकते.

सरकार कह रही है कि गांवों में स्कूल बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत है...

अभी जो स्कूल हैं, पहले उनकी व्यवस्था तो ठीक कर लें. पहले से जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनकी क्या हालत है? बड़ी सड़क बना देंगे, तो उससे लड़के स्कूल पहुंच जाएंगे? बीमारी कुछ और इलाज कुछ बता रहे हैं. किसी को हुआ है मलेरिया और उसे दवा टीबी की दे रहे हैं.

सरकार कह रही कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत उसे इंडस्ट्री लगानी है. दुनिया के कई देशों से कंपनियां आएंगी. उसके लिए इंडस्ट्रियल कॉरीडोर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी...

उसके लिए क्या-क्या चाहिए, यह तय करे सरकार. क्या-क्या आया, यह भी तय करना होगा. एफडीआई जो अभी तक देश में आया है, उसका हिसाब होना चाहिए. जो देश में निवेश करेंगे, वे किस बात के लिए करेंगे? जो निवेश करेंगे, उसका फ़ायदा भी तो भारत को मिले. हमें थमा दें हाथ में चवन्नी और खुद खा जाएं पूरा रुपया. इस भिखमंगी वृत्ति के साथ देश नहीं चलाया जाता. मेक इन इंडिया के साथ-साथ मेक फॉर इंडिया और बाई इंडिया भी होना पड़ेगा.

लेकिन सरकार इसे बहुत सीरियसली ले रही है और कह रही है कि लोग इंडस्ट्री शब्द को ही एब्यूज (गाली देना) कर रहे हैं...

ऐसा इसलिए, क्योंकि ऐसी स्थिति बन गई. रोज़गार बढ़ने थे, वह तो मानक बना नहीं और जीडीपी को मानक बना दिया आपने. कितने बेरोज़गार हैं, इसका आपने कभी हिसाब लिया. उसके लिए आप स्किल इनहैंसमेंट कर रहे हैं. आज भी सबसे ज़्यादा बचत, रोज़गार और विदेशी मुद्रा का अर्जन देशी अर्थव्यवस्था के ज़रिये है. बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां तो कहती हैं कि हम इसके लिए हैं ही नहीं, हम सिर्फ़ आपका जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाएंगे. जहां 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि आधारित व्यवसायों पर आश्रित है और आप उसे जीडीपी का सिर्फ़ 19 प्रतिशत हिस्सा मान रहे हैं, तो उसकी बदहाली आप दूर कैसे करेंगे? कई आकलन कह रहे हैं कि 2050 में भी 50 प्रतिशत आबादी गांवों में रहेगी.

मगर सरकार कह रही है कि वह गांवों में भी घर बनाएगी, छोटे-छोटे शहर बसाएगी और सौ स्मार्ट सिटी बनेंगे.

एक स्मार्ट सिटी बसाने के लिए 70 हज़ार करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश चाहिए और वह सात सौ गांव लील जाएगा. और, आप सौ स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं! इस समय ज़रूरत है स्मार्ट विलेजेज की. उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि कुपोषण कैसे ख़त्म हो. देश के 47 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं.

क्या सरकार में कोई ऐसा आदमी नहीं है, जो यह सब उसे समझा सके? या फिर समझा जाना चाहिए कि सरकार आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के नियम लागू कर रही है?

मैं अभी नीयत पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन नीतियों और प्राथमिकताओं पर सवाल ज़रूर उठा रहा हूं. प्राथमिकता यहां पर डॉलर लाने की नहीं है, बल्कि प्राथमिकता है हर बच्चे को आधा लीटर दूध, आधा किलो सब्जी, आधा किलो फल कैसे मिले. सिर्फ़ इंडस्ट्री से बात नहीं बनती. खेती और उससे जुड़े छोटे-छोटे उद्योगों से रोज़गार आएगा और तभी खुशहाली आएगी.

आपने कहा कि आप नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, नीयत पर नहीं. आपका यह कहना है कि जो नीतियां बन रही हैं, वे बचकानी हैं और विश्व बैंक एवं आईएमएफ की नीतियां लागू की जा रही हैं?

अगर मर्ज की समझ न हो, तो इलाज मर्ज को बढ़ाता है या नए मर्ज पैदा कर देता है. इसलिए पहले मर्ज को समझिए, फिर उसके इलाज को समझिए. सबसे पहले ज़मीन और कृषि पर ध्यान हो. कृषि योग्य भूमि पहले साढ़े 12 करोड़ हेक्टेयर थी. दस साल में एक करोड़ 80 लाख हेक्टेयर कम हो गई. गोचर ज़मीन साफ़ हो गई है. कृषि और पशुपालन का मेल है. इन पर आपका ध्यान नहीं है. जो रहा-सहा है, उसे भी आप हड़पने की कोशिश कर रहे हैं. आप सीमेंट, बालू खाएंगे या रोटी? आपने एसईजेड के लिए जो ज़मीन दी और जो ज़मीन पहले अधिग्रहीत की जा चुकी है, उनका क्या हुआ, यह तो पता कर लीजिए. लैंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी लाइए. उसका लेखा-जोखा आपके मंत्रालय में पड़ा है, उसे पढ़ लीजिए.

क्या आप चाहते हैं कि पहले से अधिग्रहीत भूमि पर कोई श्वेतपत्र लाया जाए?

देश में इतना वेस्ट लैंड मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करके काम किया जा सकता है. इसके लिए अच्छे, हरे-भरे खेत हड़पने की कोई ज़रूरत नहीं है. शहर के आसपास सब्जी के खेत होते थे, उन सबको आपने कंक्रीट का जंगल बना दिया.

आपके कुछ पुराने स्वदेशी जागरण मंच के साथी सरकार के सुर में सुर मिला रहे हैं. आप अपने स्टैंड पर बने हुए हैं, ऐसा क्यों?

सत्ता के व्यामोह के भी शिकार हो जाते हैं लोग. एक एक्टर ने पूछा गया कि दौलत और शोहरत पाकर आप नहीं बदले, दूसरे लोग तो बदल जाते हैं. उसने कहा, मैं नहीं मानता कि कोई बदल जाता है, लोग दौलत-शोहरत पाकर ऑरिजिनल हो जाते हैं. इसलिए गिला-शिकवा रखने की कोई बात नहीं है. हां, संवाद और सुधार होने की गुंजाइश रहती है. किसी से गिला-शिकवा लड़ाई- झगड़ा नहीं है.

अन्ना हजारे के साथ कुछ संगठनों ने मिलकर आंदोलन किया, उसमें किसान नहीं थे, उसे जनसमर्थन नहीं मिला, और आपने एक कार्यक्रम बिजनौर भी किया, उसमें भी शायद ज़्यादा लोग नहीं आए. क्या वजह है? अगर आपके मुद्दे में लॉजिक है, सच्चाई है, आप किसान हितैषी बातें कर रहे हैं, तो लोग आ क्यों नहीं रहे?

एकता परिषद में छह हज़ार अधिकांशत: भूमिहीन किसान पैदल आए थे पलवल से दिल्ली तक. मुद्दे में ताकत है, बात पहुंचती है, लोग आते हैं, यह तो सिद्ध हुआ है. हम बात पहुंचाने और ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन विस्तार में कमजोर पड़े हैं.

एकता परिषद की भीड़ को लेकर कहा जा रहा है कि उसमें किसान नहीं, भूमिहीन किसान थे और भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले लोग नहीं थे.

जंतर-मंतर पर वीएम सिंह के बैनर के तले बड़ी मात्रा में किसान थे, लगभग डेढ़-दो हजार. किसान थे, इसलिए यह सिद्ध होता है कि बात पहुंचे, तो लोग आते हैं. हमारा संगठन बात पहुंचाने में कमजोर पड़ा है, उसे दुरुस्त करना पड़ेगा.

कहा जा रहा है कि यह आंदोलन देश भर में पहुंचाया जाएगा और वे अलग-अलग काम करेंगे, तो यह क्रिटिसिज्म आ रहा है कि एनजीओ वाले शायद किसी चीज को लेकर परेशान हैं, इसलिए उन्होंने एक नया पैतरा चला है कि किसी तरह से एनजीओ की गतिविधियां जारी रहें और धन मिलना बाधित न हो.

भारत में उपजे मजहब और भारत से बाहर उपजे मजहबों की तासीर में क्या कोई फ़र्क है, यह देखने की ज़रूरत है. जैसे ही संस्कृति और भी संस्कृति. मैं ही ठीक, मेरा ही रास्ता ठीक, मेरा ही भगवान, यह ही संस्कृति है. तुम भी ठीक, मैं भी ठीक, मेरा भगवान अपना-तुम्हारा भगवान अपना. अपने के प्रति अभिमान और दूसरे के प्रति सम्मान यह भी संस्कृति का हिस्सा है. कहां क्या कमी है, क्या आधार है, यह संवाद का विषय है. लेकिन, समय जब चुनाव का, जद्दोजहद का, कीचड़ फेंकने का रहता है, तब इन मुद्दों पर सही मानस से चर्चा या संवाद नहीं हो सकता. इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि चुनावी माहौल में ऐसे मुद्दे न उठें, तो बेहतर है.

इसका हमें पता नहीं है, लेकिन हमने तो यहां तक क्रिटिसिज्म सुना कि अन्ना हजारे चार्टेड फ्लाइट में आए, जिंदल की फ्लाइट में दिल्ली आए. सोशल मीडिया में यह बहुत चला, जबकि उन्होंने खुद बोर्डिंग पास दिखाया कि किस हवाई जहाज से आए. सच्चाई कुछ है और प्रचार कुछ. इससे साबित होता है कि आंदोलन के विरोधी स्वयं को कमजोर पा रहे हैं, इसलिए वे असत्य का सहारा ले रहे हैं. इसका मतलब है कि मुद्दे में दम है, नेतृत्व में साख है और उस साख को चोट पहुंचाना है, इसलिए ये तरीके अपनाए जा रहे हैं. एनजीओ वाला जो फैक्टर है, तो मैं अपनी बात करता हूं. मुझे तो नहीं मिलता और किन्हें कितना मिलता है, वह भी देख ले सरकार. हम तो मानते हैं कि मुद्दे में दम है, मुद्दों और मूल्यों के आधार पर हम चलें. जो कमजोर होंगे, वे खुद ही छंट जाएंगे.

आगे की क्या तैयारी है?

एक तो विभिन्न संगठन इलाके बांटकर ज़िलों में पदयात्रा करें. उसके बाद अगर बड़ी पदयात्रा निकलती है, तो उसकी पूरी भूमिका बन जाए और बात यहां तक आनी चाहिए कि जत्थे गिरफ्तारी देने के लिए तैयार रहें. यदि ऐसा होता है, तो हम अपना संदेश दूर तक ले जा सकेंगे. सोशल मीडिया एक हद तक इसमें उपयोगी हो सकता है, मगर ज़मीन पर चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है.

सरकार ने जो बजट पेश किया, उसे किस तरह देखते हैं आप? क्या ये वही लोग हैं, जो किसी विचारधारा से जुड़े होने का दावा करते थे? यह बजट कांग्रेस के बजट से अलग कैसे नज़र आ रहा है?

मैंने कुछ वर्षों से बजट सेशन टीवी पर देखना बंद कर दिया, क्योंकि बजट के अलावा के समय में ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, चाहे डीजल के दाम घटने-बढ़ने हों, मालभाड़ा बढ़ना हो. टिकट दर अभी नहीं बढ़ाएंगे, तो बाद में बढ़ाएंगे. निर्णय तो बजट के बाहर ही ज़्यादा होते हैं. दूसरा, तीन-चार सालों में इस बजट का प्रतिफलन क्या हुआ, यह आर्थिक सर्वेक्षण में मालूम पड़ता है. नज़रिया अमीरपरस्त है, प्रकृति विध्वंशक है. यह नज़रिया अमीर को और अमीर, ग़रीब को और ग़रीब बनाने वाला है. यह नज़रिया ट्रिकल डाउन थ्योरी में विश्वास करता है, जो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में फेल हो चुकी है. विगत 20 वर्षों में 65 करोड़ लोग थे, एक डॉलर से कम में जीने वाले. आज दुनिया में ऐसे लोग 130 करोड़ हैं. आज 80 प्रतिशत संपदा 20 प्रतिशत लोगों और 20 प्रतिशत संपदा 80 प्रतिशत लोगों के हाथ में है. महिलाओं की स्थिति दिनोंदिन कमजोर हो रही है, आतंकवाद बढ़ा है, राजनीतिक स्थिरता बढ़ी है, तनाव बढ़ा है. जब हम फेल हो चुकी थ्योरी से बजट के लिए दिशा-दृष्टि के बारे में सोचेंगे, तो परिणाम क्या होगा? भारत को अमेरिका बनाने चले और अफ्रीका बना डाला या फिर ब्राजीलीकरण कर डाला.

एक स्वयंसेवक के नेतृत्व में चलने वाली सरकार यह सब कर रही है और संघ चुपचाप बैठा है?

कई बार मैं मानता हूं कि संघ का दोष भी होता है. वह क्या जाने पीर पराई, जाके पैर न फटी बिवाई. अपनी जीवनशैली को अगर हम ग़रीबपरस्त नहीं बनाएंगे, तो हमारी सोच ग़रीबपरस्त नहीं बनेगी. हम एलीटिस्ट सोच के होंगे. वैसा ही होगा कि रोटी नहीं है, तो केक क्यों नहीं खा लेते. इससे अराजक ताकतों को मदद मिलेगी.

वाजपेयी जी की सरकार के समय संघ के कई लोगों की शिकायत थी कि सत्ता में आने के बाद ये लोग बदल गए, विचारधारा छोड़ दी, कांग्रेसी बन गए और इनका चाल, चरित्र, चेहरा यानी सब कुछ बदल गया. जब मोहन भागवत आए, तो उन्होंने कहा कि भाजपा का ऑपरेशन करने की ज़रूरत है. मुझे लगता है कि मोहन भागवत की पकड़ सिर्फ़ घर वापसी और लव जिहाद जैसे विवादित मसलों पर है, पर जो मूल तत्व है यानी आर्थिक नीतियों और किसानों-मज़दूरों-ग़रीबों की बात आदि में संघ कोई हस्तक्षेप नहीं करता. यह विरोधाभास समझ में नहीं आता.

इसका उत्तर आज नहीं, तो कल संघ को देना होगा. एक बात मुझे अच्छी लगी कि भूमि अधिग्रहण के मसले पर किसान संघ, मज़दूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच हमारे साथ हैं, बाकी सत्ता के साथ संवाद की अंतिम ज़िम्मेदारी तो जनता की है. संघ के लोग चाहें, तो सरकार से संवाद करें और अमीरपरस्त नीतियों के बजाय ग़रीबपरस्त नीतियों के पक्ष में दबाव डालें.

दो-तीन और चीजें हो रही हैं कि घर वापसी का मसला हो, चाहे लव जिहाद का मसला हो, देश में एक अजीब तरह का माहौल बन गया है यानी जबसे यह सरकार बनी है, तबसे माहौल में तल्खी-सी आ गई है...

भारत में उपजे मजहब और भारत से बाहर उपजे मजहबों की तासीर में क्या कोई फ़र्क है, यह देखने की ज़रूरत है. जैसे ***ही संस्कृति*** और ***भी संस्कृति***. मैं ही ठीक, मेरा ही रास्ता ठीक, मेरा ही भगवान, यह ***ही संस्कृति*** है. तुम भी ठीक, मैं भी ठीक, मेरा भगवान अपना-तुम्हारा भगवान अपना. अपने के प्रति अभिमान और दूसरे के प्रति सम्मान यह ***भी संस्कृति*** का हिस्सा है. कहां क्या कमी है, क्या आधार है, यह संवाद का विषय है. लेकिन, समय जब चुनाव का, जद्दोजहद का, कीचड़ फेंकने का रहता है, तब इन मुद्दों पर सही मानस से चर्चा या संवाद नहीं हो सकता. इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि चुनावी माहौल में ऐसे मुद्दे न उठें, तो बेहतर है. इससे वोट भले ही मिल जाएं, मगर समाज का नुक़सान हो जाता है.

जो ग़ैर राजनीतिक संगठन ऐसे कामों को बढ़ावा देते हैं, करते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे?

सही समय पर संवाद होने से वे समझते हैं कि कुछ खास मौक़ों पर ऐसे मसले उठाए जाएं, तो शायद सुनवाई हो जाए, लेकिन उससे नुक़सान होता है, लाभ नहीं होता समाज को. ■

manishbph244@gmail.com

बेहतर मुआवज़े तथा पुनर्वास व पुनर्स्थापना के सुझावों का किसानों को लालच देकर येन केन प्रकारेण उन्हें भूमि अधिग्रहण बिल पर सहमत कराने का सरकार भरसक प्रयास कर रही है. अब तक लागू होते रहे भूमि अधिग्रहण कानून से भी ये बात साफ़ है कि सरकार चाहे भाजपा की हो या किसी अन्य पार्टी या मोर्चे की, चाहे वह केंद्र की सरकार हो या फिर प्रांत की सरकार हो, वह कृषि भूमि अधिग्रहण पर अंकुश लगाने वाली नहीं है. पिछले 20 सालों से लागू हो रही इन्हीं नीतियों के तहत पूंजीपतियों के अधिकारों को बढ़ाया जा रहा है. किसान के पक्ष में हिमायती दिखने वाला किसी भी तरह का कानून क्यों न आ जाए, सरकार उसके जरिए व किसानों से जमीन का मालिकाना हक छुड़ाने, छीनने से बाज़ नहीं आ सकती.

भूमि अधिग्रहण बिल

किसानों के साथ अन्याय है

भारत में खेती किसानों की जीवनशैली का अटूट हिस्सा है. लहलहाती हुई फसलों में किसान अपना जीवन देखता है, लेकिन मोदी सरकार किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण कर उनके जीवन की डोर बीच में ही तोड़ने पर आमादा है. सरकार किसानों को मुआवजा चाहे जितना भी दे दे, लेकिन किसान को तो उसकी ज़मीन चाहिए. क्या ये संशोधन किसान परिवारों के युवा लोगों की आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप हैं? भूमि अधिग्रहण संशोधन किसानों के सामाजिक लक्ष्य की पूर्ति और अधिग्रहीत भूमि के मालिकों के हितों की रक्षा कर सकते हैं? ये ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है. भूमि अधिग्रहण के बहाने विकास की कोरी कल्पना से भला मोदी सरकार के अच्छे दिन आने से रहे. कहना ग़लत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार का यह बिल किसानों पर वज्रपात की तरह गिरेगा, जिसकी मार सहन कर पाना उनके वश की बात नहीं.

राजीव रंजन

भूमि अधिग्रहण बिल लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन राज्यसभा में कब पास होगा, पास होगा भी या नहीं या फिर इस बिल को अध्यादेश के माध्यम से लागू किया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी. इस बिल को लेकर मोदी सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि यह बिल किसान विरोधी और पूंजीपतियों का हितैषी है. पहली नज़र में यह साफ मालूम होता है कि सरकार इस बिल को शहरीकरण, औद्योगिकीकरण एवं बुनियादी ढांचे के विकास के नाम पर ज़मीन अधिग्रहण को बढ़ावा देने का काम करने जा रही है. मतलब अधिग्रहण तो हो, पर विवाद कम से कम हो. यही कारण है कि किसानों को अभी से ही लगने लगा है कि गैर कृषि क्षेत्र को होने वाला कोई भी लाभ चाहे वह स्कूल जाने वाले बच्चे हों, अस्पताल की तलाश कर रहे मरीज हों, सस्ते मकान की प्रतीक्षा कर रहे आम जन हों, छोटे कारोबारी या बड़े उद्यमी हों, यह सब हासिल होगा उनकी अधिग्रहित ज़मीन के बल पर.

बेहतर मुआवज़े तथा पुनर्वास व पुनर्स्थापना के सुझावों का किसानों को लालच देकर येन केन प्रकारेण उन्हें इस अधिग्रहण पर सहमत कराने का सरकार भरसक प्रयास कर रही है. अब तक लागू होते रहे भूमि अधिग्रहण कानून और अब उसके नए मसौदों से भी ये बात साफ़ है कि सरकार चाहे भाजपा की हो या किसी अन्य पार्टी या मोर्चे की, चाहे वह केंद्र की सरकार हो या फिर प्रांत की सरकार हो, वह कृषि भूमि अधिग्रहण पर अंकुश लगाने वाली नहीं है. पिछले 20 सालों से लागू हो रही इन्हीं नीतियों के तहत पूंजीपतियों के अधिकारों को बढ़ाया जा रहा है. किसान के पक्ष में हिमायती दिखने वाला किसी भी तरह का मसौदा क्यों ना आ जाए, सरकार उसके जरिए व किसानों से जमीन का मालिकाना हक छुड़ाने, छीनने से बाज़ नहीं आ सकती. सरकार यह भूल जाती है कि वो अपने मसौदे या संशोधनों के जरिये किसानों की जमीनों का अधिग्रहण ही करती है, उनकी जमीन उनके पास नहीं रहने देती. और यही किसानों की सबसे बड़ी चिंता है. किसान कहते हैं कि हमारी ज़मीन हमसे भला कोई जबरदस्ती कैसे ले सकता है? क्या सरकार के पास किसानों के इस सवाल का कोई जवाब है कि अगर उनकी ज़मीन अधिग्रहण में चली जाएगी, तो वे किस ज़मीन पर खेती करेंगे, वे क्या खाएंगे? आप मुआवज़े चाहे जितना दे दें, लेकिन क्या किसानों की ज़मीन उन्हें वापस मिल पाएगी? जब सरकार सार्वजनिक कंपनियों को निजी हाथों में सौंपती जा रही है तो इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले समय में सार्वजनिक हित के नाम पर किया जा रहा भूमि अधिग्रहण धनाढ्य कंपनियों के हित में नहीं किया जाएगा? निजी कंपनियों का कोई सामाजिक सरोकार या लोक कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं होता है. उनका उद्देश्य अधिक से अधिक निजी हित को साधते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट होता है. इसलिए इस दौर में सार्वजनिक हित के नाम पर शहरीकरण औद्योगिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास में ऊपर से थोड़ा बहुत सार्वजनिक हित भले ही दिखाई पड़ जाए, लेकिन उसके भीतर धनाढ्य कंपनियों का हित व मालिकाना अधिकार ही छिपा हुआ है. ज़रूरी है कि आम किसान व अन्य ग्रामीण इस बिल के झांसे में न आकर भूमि अधिग्रहण का निरंतर विरोध जारी रखें.

सवाल, जो बेहद अहम हैं

प्रस्तावित संशोधनों का आंकलन करते समय सरकार से यह सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि क्या ये संशोधन किसान परिवारों के युवा लोगों की आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप हैं और क्या जिस परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसके सामाजिक लक्ष्य की पूर्ति और अधिग्रहीत भूमि के मालिकों के हितों की रक्षा इन संशोधनों में शामिल है.

सरकार की नीयत में खोट

हर किसी का सपना है कि शहर में उसका एक मकान हो. उसके बच्चे भी कॉन्वेंट में पढ़ें. उन्हें बेहतर इलाज की सुविधा मिले, अच्छी नौकरी मिले, अगर ये सारी सुविधाएं उनके गांवों में या गांवों के आसपास मिलने लगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ग्रामीणों का शहरों की तरफ पलायन रुक जाएगा. आखिर क्यों नहीं सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है. ताकि ग्रामीणों को सारी सुविधाएं उनके गांवों के आसपास ही मिलें. अगर ये सुविधाएं किसानों या उनके बच्चों को पास में ही मिलती हैं तो वे भला क्यों शहरों में बसने जाएंगे. कहीं सरकार गांवों का विकास इसी उद्देश्य से तो नहीं करना चाहती कि किसानों की भूमि के अधिग्रहण जैसे मौके उसके हाथ से निकल जाएंगे. किसान स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल की सुविधाएं जरूर चाहता है, लेकिन अपनी ज़मीन के अधिग्रहण की शर्त पर नहीं.

हर तरफ विरोध के स्वर

सामाजिक कार्यकर्ता अण्णा हजारे हों या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सभी नये भूमि अधिग्रहण विधेयक के विरोध में हैं. उत्तर प्रदेश के नोएडा से महाराष्ट्र के रायगढ़ तक, पंजाब के लुधियाना से तमिलनाडु के तिरुवल्लूर तक हाल के वर्षों में भूमि अधिग्रहण का विरोध जमकर होता रहा है. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस संशोधन को किसान विरोधी करार देते हुए कहा था कि ज़मीन का मुद्दा दिल्ली में केंद्र के अधीन आता है, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार किसी की भी ज़मीन को जबरन अधिग्रहित नहीं होने देगी. हालांकि केजरीवाल यहां सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में खेती की जमीन है ही नहीं, लेकिन दूसरे राज्यों के मामले में केजरीवाल या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों का बयान तर्कसंगत है. कोई वजह नहीं दिखती कि नया क़ानून इन विरोधों को ध्वस्त कर देगा.

इसके विपरीत आशंका ये है कि ज़मीन मालिकों की सहमति की अनिवार्यता ख़त्म कर देने से विरोध और प्रबल होगा. ये क़ानून 2013 के उस क़ानून को रद्द करता है, जिसमें भूमि अधिग्रहण के लिए ज़मीन मालिकों की सहमति अनिवार्य की गई थी.

सत्ता पक्ष का दावा

मोदी सरकार इस विधेयक से बहुत उम्मीद लगाए हुए है. उसका कहना है कि यह विधेयक भूमि अधिग्रहण को आसान बनाएगा. इससे औद्योगिक विस्तार को मदद मिलेगी और देश में ताबड़तोड़ कारखाने खुलने लगेंगे. प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने ऐलान किया था कि वे भारत को चीन की तर्ज पर एक विशाल औद्योगिक मुल्क बनाएंगे. मोदी सरकार कहती है कि ये विधेयक ज़मीन के मालिकों को पहले से अधिक मुआवज़े का हक़ देता है. हालांकि विपक्ष के अलावा मोदी के कुछ सहयोगी दल भी इस विधेयक को जनविरोधी बता रहे हैं और आंदोलन छेड़ने की धमकी दे रहे हैं. दूसरी तरफ कम से कम दो दशकों का अनुभव भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक के प्रति अधिक उत्साह पैदा नहीं करता है. सरकार कहती है कि संशोधन इन कमियों को दूर करने का उद्देश्य रखता है. यह सरकार को समुचित अधिकार देता है कि वह पीपीपी और लोकहित में चलाई जा रही निजी परियोजनाओं को सहमति और सामाजिक प्रभाव आंकलन जैसे प्रावधानों से छूट मुहैया कराये. यह सुविधा भी पांच अहम क्षेत्रों यानी राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा और विद्युतीकरण, सस्ते मकान, औद्योगिक कॉरिडोर और पीपीपी आधारित बुनियादी तथा सामाजिक ढांचा योजनाएं, जिनमें भूमि का स्वामित्व सरकार के पास ही रहना है, के लिए ही दी गई है. अन्य प्रमुख संशोधन में प्रस्ताव रखा गया है कि वर्ष 2013 के अधिनियम के तहत हर्जाने और पुनर्वास के प्रावधानों के क्षेत्रों का विस्तार किया जाए, ताकि अधिकाधिक किसान और प्रभावित परिवार इसके दायरे में शामिल हो सकें. ये परिवार फिलहाल इस दायरे से बाहर हैं.

अधर में प्रोजेक्ट!

मोदी सरकार दावा करती रही है कि यूपीए के इस कानून के कारण कई प्रोजेक्ट फंस गए हैं. सवाल यह उठता है कि क्या वाकई भूमि अधिग्रहण के कारण विकास की योजनाएं अटकी पड़ी हैं. उनके पास ज़मीन नहीं है, लेकिन मीडिया में आई ख़बरों पर यकीन करें तो 67 ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से सिर्फ सात प्रोजेक्ट ही भूमि अधिग्रहण के कारण रुके पड़े हैं. इनकी साझा लागत 53,677 करोड़ ही है. सितंबर 2013 में भूमि विवाद के कारण सिर्फ 12 प्रोजेक्ट में ही बाधा आई थी. जो सात प्रोजक्ट रुके पड़े हैं, उनमें से छह सड़क परियोजनाएं हैं. 60 प्रोजेक्ट पूंजी की कमी से लेकर कई अन्य कारणों के कारण अटके हुए हैं.

कॉरपोरेट लॉबी बिल की समर्थक

कॉरपोरेट लॉबी इस बिल के समर्थन में हां में हां मिला रही है, लेकिन कॉरपोरेट जगत यह भूल जाता है कि ज़मीन आसानी से मिलने भी लगे तो भी देश भर में कारखाने लगाने के लिए बहुत बड़ी पूंजी चाहिए और भारत के पास उतनी पूंजी है नहीं. दूसरी तरफ 2008–09 के बाद अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की माली हालत के कारण विकसित देश निवेश की हालत में नहीं हैं. यानी कुल मिलाकर भूमि अधिग्रहण के बाद भी विकास कार्यों में गति धीमी रहने के आसार हैं.

चार अप्रैल तक इस संशोधित बिल का कानून बनाया जाना ज़रूरी है. अन्यथा अध्यादेश रद्द हो जाएगा. अब राज्यसभा में विपक्ष ने अगर बिल का विरोध जारी रखा तो सरकार को संयुक्त सत्र बुलाना होगा. और वहां बहुमत होने की वजह से सरकार आसानी से अपना काम कर लेगी. उधर, एक और बड़ी समस्या यह है कि किसान संगठन दिल्ली में होने वाली किसान पंचायत की तैयारी में जुटे हैं. सरकार संसद में विपक्ष से तो निपट लेगी, लेकिन किसानों से निपटना आसान नहीं होगा. कुल मिलाकर कहा जाए तो आनेवाले दिनों में सरकार के लिए यह बिल लोहे के चने चबाने के समान है. ■

feedback@chauthiduniya.com

भूमि अधिग्रहण पर बवाल

- वर्ष 2007–08 में पश्चिम बंगाल में भूमि अधिग्रहण विरोधी हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई थी.
- टाटा कंपनी को कार कारख़ाना लगाने की योजना रद्द करनी पड़ी थी.
- इंडोनेशिया के एक बड़े औद्योगिक समूह की योजनाओं पर भी अमल नहीं हो पाया था.
- जनविरोधों के चलते ही कई वर्षों से दक्षिण कोरियाई कंपनी पॉस्को ओडिशा में दुनिया का सबसे बड़ा स्टील कारख़ाना शुरू नहीं कर पाई है.
- नक्सली हिंसा की वजह से छत्तीसगढ़ में टाटा और एस्सार कंपनियों की योजनाएं भी अटकी हुई हैं.

मुख्य संशोधन

- मोदी सरकार बहुफसली भूमि का अधिग्रहण नहीं करेगी. इस प्रावधान से खेती योग्य ज़मीन अधिग्रहण के दायरे में नहीं आएगी. जबकि पहले खेती योग्य जमीन के अधिग्रहण करने की भी बात थी.
- इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के लिए सीमित जमीन लिए जाने का फैसला किया गया है.
- लोकसभा में पास किए गए बिल के मुताबिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए होने वाले अधिग्रहण में किसानों की मंजूरी भी जरूरी होगी.
- आदिवासी क्षेत्रों में अधिग्रहण के लिए पंचायत की सहमति जरूरी होगी.
- किसान अधिग्रहण के किसी भी मामले में अपील कर सकेंगे.
- पहले चले आ रहे भूमि अधिग्रहण कानून में प्रभावित किसानों को मुआवज़ा देने का प्रावधान था, लेकिन किसी को नौकरी नहीं दी जाती थी. संशोधन के बाद लोकसभा में पास हुए बिल में प्रभावित परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दिए जाने का प्रावधान किया गया है.
- सरकार ने फैसला कर लिया है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए अब रेलवे ट्रैक और हाईवे के दोनों तरफ एक किलोमीटर तक की जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है. संशोधित भूमि अधिग्रहण बिल के मुताबिक बंज़र ज़मीनों के लिए अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा.

58 दिन, 135 खुदकुशी

एक तरफ भूमि अधिग्रहणबिल और दूसरी तरफ प्रकृति की मार झेल रहे किसानों की खुदकुशी के आंकड़े देश में किसानों की दयनीय हालत की कहानी बयां कर रहे हैं. महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इस साल के शुरुआती 58 दिनों के भीतर ही 135 किसानों ने खुदकुशी कर ली है. यह जानकारी राज्यसभा में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री मोहनभाई कुंदरिया ने एक सवाल का जवाब देते हुए दी. पिछले तीन साल (2012, 2013, 2014) में ऐसे 662 किसानों ने आत्महत्या की, जो सरकारी नीति के मुताबिक एक लाख रुपये के मुआवजे के हकदार थे. नेशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक, साल 2012 में किसानी के जरिये जीवन-यापन कर रहे 13,754 और वर्ष 2013 में 11,772 लोगों ने आत्महत्या की. शर्म आनी चाहिए सरकार को कि जिस देश में अधिकांश लोग खेती पर निर्भर हैं, उस देश में किसानों को आत्महत्याएं करनी पड़ रही हैं. ■

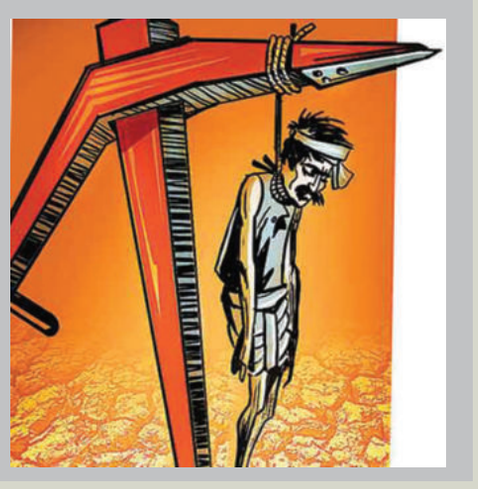

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

बजट सत्र में बजट मुख्य विषय होने के कारण संसद में कम काम होता है और जो बिल सरकार अध्यादेश के माध्यम से लाई थी, उनकी वजह से सरकार और विपक्ष के बीच अविश्वास बढ़ गया था. संसद में कुछ दिन नीरस थे, क्योंकि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री विदेश दौरे पर गए थे. लेकिन, किसी न किसी तरह कार्य संस्कृति सदन में बहाल करनी होगी, अन्यथा आने वाले चार साल देश के लिए अच्छे नहीं होंगे. सरकार यह कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि हमने तो बिल पेश किए थे, विपक्ष ने ही उन्हें पारित नहीं होने दिया. जनता को नतीजे चाहिए.

सभी पक्षों को ध्यान में रखकर काम होना चाहिए

संसद का सत्र अभी चल रहा है. भाजपा को अब जाकर एहसास हुआ है कि संसद को द्विपक्षीय तरीके से चलना चाहिए और यह कि विपक्ष के सहयोग के बिना लंबित पड़े बिल संसद में पारित कराना नामुमकिन है. दरअसल, उन्हें यह काम अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही शुरू कर देना चाहिए था. बहरहाल, उनके सहयोगी दलों ने भी भूमि अधिग्रहण जैसे बिलों का विरोध किया. इस वजह से उन्हें लगा कि यदि विपक्ष सहयोग के लिए तैयार नहीं है और उनके सहयोगी दल विरोध में हैं, तो ऐसे में संसद के संयुक्त सत्र में भी बिल पारित नहीं हो सकते. खैर जो भी हो, लोकसभा ने भूमि अधिग्रहण बिल नौ संशोधनों के साथ पारित कर दिया, लेकिन विपक्ष जैसा चाहता था, यह उससे थोड़ा कम है. कोयला और खनन से संबंधित दो बिल राज्यसभा की स्थायी समिति के पास भेज दिए गए हैं. हो सकता है कि भूमि अधिग्रहण बिल भी राज्यसभा की स्थायी समिति के पास भेज दिया जाए, ताकि उस पर आम सहमति का कोई फॉर्मूला बनाया जा सके. वास्तव में भूमि अधिग्रहण बिल को कुछ संशोधनों के साथ एक बार फिर लोकसभा भेजा जाएगा. लेकिन यह देशहित में है कि सभी बिल संसद में पारित हो जाएं और दोनों पक्ष आदान-प्रदान के आधार पर काम करें, क्योंकि इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है. यह देश के लिए है, इसलिए सभी पक्षों के विचारों को ध्यान में रखकर काम किया जाए.

दूसरी तरफ़ दिग्विजय सिंह ने एक सराहनीय बयान जारी किया कि विपक्ष को यह फ़ैसला करना चाहिए कि उसे किस बिल का विरोध करना है और किसका नहीं. बिना सोचे-समझे सभी बिलों का विरोध करने से कुछ हासिल नहीं होगा. यह एक ऑब्सट्रक्शनिस्ट (अवरोध उत्पन्न करने वाली) प्रवृत्ति है. लोकतंत्र में न तो ऑब्सट्रक्शनिज्म से काम चलता है और न विपक्ष को नज़रअंदाज़ करके अध्यादेश द्वारा शासन चलाने से. सही तरीका यह है कि बातचीत के ज़रिये समाधान तलाशा जाए. यहां संसदीय कार्यमंत्री के रूप में वेंकैया नायडू उपयुक्त नहीं हैं. उनकी भाव-भंगिमा (बॉडी लैंग्वेज) में सुलह के बजाय टकराव का पहलू नज़र आता है. एक ऐसे व्यक्ति को संसदीय कार्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, जिसकी पहुंच संसद के हर पक्ष तक हो. अभी संसद की सात-आठ बैठकें बाकी हैं. हमें आशा करनी चाहिए कि इनमें से कुछ ठोस परिणाम निकल कर सामने आएंगे.

उम्मीद के मुताबिक नीतीश कुमार ने बिहार में विश्वास मत हासिल कर लिया. दरअसल, विश्वास मत हासिल करने की यह पूरी क़वायद ख़त्म होनी चाहिए. जहां तक मुझे याद है, देवेगौड़ा सरकार के समय इसकी शुरुआत हुई थी, तब तत्कालीन राष्ट्रपति ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करते हुए विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा था. ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था. किसी को विश्वास मत हासिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी. इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता था. मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, पर लगता है कि यह वीपी सिंह के समय से शुरू हुआ था. लेकिन, यह ग़लत प्रक्रिया है. पहले ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी. एक बार अगर राष्ट्रपति संतुष्ट हो गए और किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया या राज्यपाल ने किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया, तो वह सदन का सामना करता था. अगर किसी को सरकार में विश्वास नहीं है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार गिरा सकता है. किसी पदस्थ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को विश्वास मत हासिल करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन, बदकिस्मती से यही प्रणाली कायम रहेगी. दरअसल, यह अच्छी बात है कि बिहार में न केवल नीतीश खेमे के विधायकों ने एक साथ मतदान किया, बल्कि उन्हें अतिरिक्त वोट भी मिले. इससे ज़ाहिर होता है कि बतौर नेता नीतीश कुमार की स्वीकार्यता हर जगह है. बेशक, बिहार चुनाव के रंग में आ रहा है और इसी साल सितंबर के आसपास राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी. इसका मतलब है कि विधानसभा के बाकी बचे पांच से छह महीनों में नीतीश सरकार को जनता को दिखाई पड़ने वाले कुछ ऐसे काम करने होंगे, जिनके सहारे उनकी पार्टी आत्मविश्वास के साथ चुनावी जंग लड़ सके.

नीतीश कुमार ने बिहार में विश्वास मत हासिल कर लिया. दरअसल, विश्वास मत हासिल करने की यह पूरी क़वायद ख़त्म होनी चाहिए. जहां तक मुझे याद है, देवेगौड़ा सरकार के समय इसकी शुरुआत हुई थी. तब तत्कालीन राष्ट्रपति ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करते हुए विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा था. ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था. किसी को विश्वास मत हासिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी. इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता था.

बजट सत्र में बजट मुख्य विषय होने के कारण संसद में कम काम होता है और जो बिल सरकार अध्यादेश के माध्यम से लाई थी, उनकी वजह से सरकार और विपक्ष के बीच अविश्वास बढ़ गया था. संसद में कुछ दिन नीरस थे, क्योंकि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री विदेश दौरे पर गए थे. लेकिन, किसी न किसी तरह कार्य संस्कृति सदन में बहाल करनी होगी, अन्यथा आने वाले चार साल देश के लिए अच्छे नहीं होंगे. सरकार यह कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि हमने तो बिल पेश किए थे, विपक्ष ने ही उन्हें पारित नहीं होने दिया. जनता को नतीजे चाहिए.

अब एक नज़र आम आदमी पार्टी में चल रहे ड्रामे पर डालते हैं. मैं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं के व्यवहार से हैरान हूं. आप इतने बेसब्र कैसे हो सकते हैं? अभी 10 फरवरी को दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी में भारी विश्वास जताया था. केजरीवाल को कुछ समय तो दीजिए. कम से कम एक साल के बाद देखिए कि वह अपनी घोषणाएं पूरी करने में सक्षम हैं या नहीं. अगर दिल्ली सरकार अपनी घोषणाओं के अनुकूल नहीं चलती है, तो उससे जनता में खुद-ब-खुद असंतोष पैदा होगा, लेकिन पार्टी की इस अंदरूनी कलह से कोई लाभ नहीं होगा. अब वे लोग केजरीवाल की पिछली गलतियां गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि वह कांग्रेस को तोड़कर सरकार बनाना चाहते थे. यह सब अब अप्रासंगिक हो गया है. पार्टी ने दिल्ली में 70 में से 67 सीटें जीतीं हैं. तो अब यह मामला कैसे प्रासंगिक हो सकता है कि वह कांग्रेस के छह विधायकों को तोड़ना चाहते थे या नहीं? जैसा कि बिल्कुल सही कहा गया है कि जब वह किसी को मंत्री बनाने का वादा नहीं कर रहे थे, किसी को रिश्वत की पेशकश नहीं कर रहे थे, तो दूसरी पार्टी के लोगों से समर्थन मांगने में क्या ग़लत है? अभी वह एक ऐसी पार्टी में हैं, जो दूसरी पार्टी के लोगों को समझा रही है कि वे अपनी पार्टी छोड़कर उसमें शामिल हो जाएं. अब इसमें ग़लत क्या है? मुझे पता नहीं कि प्रशांत भूषण किन सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, जिन पर यह पार्टी स्थापित हुई है. अगर ऊंचे सिद्धांतों का मतलब यह है कि आपको सरकार नहीं बनानी चाहिए, तो उस समय केजरीवाल सही थे, जब उन्होंने धरना वगैरह दिया था. जनता नाराज़ थी, क्योंकि केजरीवाल ने पद छोड़ा था. जनता ने इस बार उनका समर्थन इसलिए किया, क्योंकि उन्होंने उससे वादा किया कि यदि इस बार उन्हें बहुमत मिला, तो वह इस्तीफ़ा नहीं देंगे.

मुझे नहीं लगता है कि केजरीवाल के विरोधी ऐसा करके पार्टी या खुद के हक़ में कुछ अच्छा कर रहे हैं. दिल्ली सरकार को काम करने का मौक़ा दीजिए. यदि वह अपनी घोषणाओं के अनुरूप काम नहीं करती है, तो उसकी आलोचना कीजिए. अंदरूनी महत्वाकांक्षाएं तो हमेशा रहेंगी और विचारों में कई मुद्दों पर मतभेद भी होंगे. यह अफ़वाह है कि योगेंद्र यादव पूरे देश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि केजरीवाल सोचते हैं कि उन्हें केवल दिल्ली पर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए. लेकिन, इस तरह की बातें तो सभी पार्टियों में होती हैं. आप को एक जगह बैठकर इन मामलों को सुलझा लेना चाहिए. हर एक आदमी प्रेस में बयान दे रहा है, यह संस्कृति ठीक नहीं है. यह सिलसिला जितनी जल्दी ख़त्म होगा, आम आदमी पार्टी के लिए उतना ही अच्छा होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

विक्रम मल्लाह और फूलन देवी-3

यूं डकैत बन गई एक मासूम लड़की

उस समय तक फूलन 15 की हो चुकी थी. चूंकि ससुराल से अलग थी तथा ग़रीब भी, इसलिए गांव के शोहदों ने उसे अपने जाल में फंसाना चाहा. गांव के सरपंच बृजबिहारी के लड़के ने फूलन को छेड़ा, तो फूलन उससे झगड़ बैठी. सरपंच के लड़के ने महिपाल के लड़के को बुलाकर उससे फूलन को एक जूता लगवा दिया. तंग आकर फूलन अपनी बुआ की लड़की के यहां चली गई. एक बार सभापति किशना ने फूलन व उसकी बहन रामकली को बहुत मारा था, क्योंकि सभापति की लड़कियों व फूलन में कहा-सुनी हो गई थी. इसी बीच (नवंबर, 78 में) गांव में डकैती पड़ी, जिसमें डकैतों ने मैयादीन का घर भी लूटा. घटना शनिवार को हुई. फूलन इससे एक दिन पहले सरपंच वाले झगड़े के कारण बुआ के यहां जा चुकी थी. लेकिन मैयादीन ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि उसके यहां डकैती फूलन ने डलवाई है, दोनों परिवारों में ज़मीन को लेकर मुकदमा भी चल रहा था. दारोगा ने जब फूलन के बारे में पूछताछ की, तो उसकी मां ने पुलिस को बता दिया कि लड़की गुस्से में टेंगुआ चली गई है. उधर फूलन को टेंगुआ में किसी ने गुमनाम चिट्ठी डाली कि उसके मां-बाप को पुलिस मार रही है. फूलन ने कहा कि जब मेरी वजह से मार रहे हैं, तब मैं गांव जाती हूं. टेंगुआ के एक व्यक्ति के साथ वह अपने गांव वापस आ रही थी कि पुलिस ने छह जनवरी, 79 को उसे पकड़ लिया तथा कालपी थाने में बंद कर दिया. फूलन तीन दिन थाने में बंद रही, फिर उसे जेल भेज दिया गया.

जेल में फूलन 20-22 दिन रही. वहां वह लगातार रोती रही. देवीदीन नरिहान के फूलसिंह की खेती करता था. उसके आग्रह पर फूलसिंह के लड़के नरायन, जयकरन व उसके साले ने फूलन की जमानत दफा 412 में कराई. जमानत कालपी के बहुत संभ्रांत परिवार के संबंधी ने दी. नरिहान के कुछ लोगों ने, जिनका डकैतों से संबंध था, फूलन की मजबूरी का नाजायज फ़ायदा उठाया. अब फूलन लुट चुकी थी. फूलन अपने घर तो आ गई, पर चैन नहीं था. अदालत की तारीख पर वह अपने एकमात्र छोटे भाई के साथ उरई जाती थी. इस बीच उसे काफी तंग किया गया और उसके अपहरण की कोशिश भी हुई. पुलिस भी लगातार आकर फूलन व उसके परिवार को परेशान करती रही कि वह डाकुओं को खाना खिलाती है. दूसरी तरफ़ गांव व नरिहान के शोहदे फूलन को लगातार घेरने की कोशिश में लगे रहे. एक दिन जमुना पार खरका गांव के दो लड़के आए और उसे देखकर हंसने लगे. फूलन ने मना किया, तो वे रात में आने की धमकी देकर चले गए. फूलन को शक हुआ कि वे शायद विक्रम व बाबू गूजर के गिरोह के लोग हैं.

फूलन दरख्वास्त लेकर कालपी थाने गई. वहां उसने दारोगा से कहा कि वह बचा लें, अन्यथा या तो आज रात उसे विक्रम उठा ले जाएगा अथवा मार डालेगा. दारोगा ने उसे आश्वासन दिया कि वह कुछ सिपाही रात के लिए भेज देगा, पर वस्तुत: उसने कुछ किया नहीं. सावन की दूज की रात थी. पानी बरस रहा था. जोंधर तथा जमुना, दोनों में बाढ़ आई हुई थी. फूलन के घर के सब लोग रोटी खाकर लेट चुके थे. अचानक दरवाजे पर भड़भड़ाहट हुई. फूलन व उसका भाई, दोनों एक कमरे में लेटे थे. बरसात से भीगा दरवाजा एक धक्के से खुल गया. वे पांच थे और फूलन को लेने आए थे. उनमें विक्रम और बाबू गूजर भी थे. उन पांचों से फूलन की मां घिघियाने लगी. विक्रम ने फूलन से कहा, या तो सीधे चलो, नहीं तो थप्पड़ मारकर ले जाएंगे. फूलन के पिता को उसने पेड़ से बांधने का आदेश दिया. बाबू गूजर ने कहा कि इसके भाई को भी ले चलो. 10 साल के अपने एकमात्र भाई से फूलन बहुत प्यार करती थी. वह बोली, पहले भाई और पिता को छोड़ो. हम चलती हैं. हमें रांधो, पकाओ, खाओ. फूलन को वे लोग सिमरा गांव की तरफ़ ले गए तथा गांव के एक व्यक्ति के यहां से मंगाकर खाना खिलाया. सिमरा के ही शिव स्वरूप के यहां से मंगाकर बेलबॉटम व शर्ट उन्होंने फूलन को पहनाया तथा उसके कंधे पर 12 बोर की बंदूक टांग दी. कल की रोती-बिलखती फूलन अब बाकायदा डाकू दल में शामिल कर ली गई तथा उसे बाबू गूजर ने वहशियाने ढंग से अपने कब्जे में ले लिया. ■

क्रमशः

feedback@chauthiduniya.com

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं. नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

कोयला घोटाले का काला सच

मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिनके कोयला घोटाले संबंधी बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास नहीं किया और कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को शपथपत्र के साथ अपना बयान अदालत में दाखिल करना होगा. मनमोहन सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे, जिन्हें अपना बयान शपथपत्र के साथ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना पड़ा. मनमोहन सिंह सरकार के अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में बार-बार झूठ बोलते रहे. उनके क़ानून मंत्री बार-बार झूठ बोलते रहे. उनके न्याय सचिव और क़ानून सचिव सुप्रीम कोर्ट में ग़लत हलफनामे देते रहे.

हमने कोयला घोटाले पर सबसे ज़्यादा इसलिए ध्यान दिया, क्योंकि जब यह घोटाला हुआ था, तो इसकी पहली जानकारी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद को मिली थी. उन सांसद ने इस घोटाले का ज़िक्र अपनी पार्टी के अध्यक्ष और महामंत्री सहित कई लोगों से किया, लेकिन उन्होंने इस घोटाले को नहीं उठाया. फिर यह घोटाला एक पत्रकार के पास पहुंचा. पत्रकार के अख़बार ने इस घोटाले को उठाने से मना कर दिया. तब हमें लगा कि इसके पीछे ज़रूर कोई लंबा और गंभीर षड्यंत्र है. तो फिर हमने इसकी छानबीन शुरू की. हमारी छानबीन ने हमें बताया कि कोयला घोटाला ऑक्टोपस की तरह सत्ता चलाने वाले तमाम अंगों में फैला हुआ है, जिनमें राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स, कॉरपोरेट, अंडरवर्ल्ड और जर्नलिस्ट शामिल हैं. इनमें कुछ का सीधा रिश्ता है और कुछ का परोक्ष रिश्ता है.

जब हमारी जांच पूरी हो गई, तो हमने उसे हिम्मत के साथ दिखाया. हमारे ऊपर दबाव आए, प्रलोभन आए. हम यह नहीं कहते कि हम बहुत बहादुर हैं, लेकिन हमने उन सारे दबावों और प्रलोभनों को एक किनारे कर दिया और इस घोटाले पर सतत नज़र रखी, जांच भी जारी रखी और कई अंकों में फॉलोअप स्टोरियां कीं. एक कवर स्टोरी की हेडिंग थी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जेल जा सकते हैं. हमें इसकी तस्दीक मनमोहन सिंह के नज़दीकी वरिष्ठ क़ानूनी सलाहकारों द्वारा हुई और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जांच के ऊपर पैनी नज़र रखने वाले कुछ भूतपूर्व जजों की बातचीत से हमें लगा कि मनमोहन सिंह इस कोयला घोटाले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं.

और, जब सीबीआई के जज ने बीते 11 मार्च को भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी बनाने की बात की, तो हमें यकीन हो गया कि हमारी रिपोर्ट सही थी. हालांकि, हमारी रिपोर्ट सही होने का एक और प्रमाण हमारे पास था. हमने मनमोहन सिंह को लेकर एक और स्टोरी की थी, जिसमें उनकी पत्नी, बहन और तत्कालीन सेनाध्यक्ष पद पर दावा करने वाले जनरल विक्रम सिंह के रिश्ते की बात हमने की थी. स्टोरी बाज़ार में आई, उसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसका खंडन जारी कर दिया. पर मजे की बात यह कि खंडन हमें नहीं भेजा, बाकी सबको भेज दिया. यानी जिसने रिपोर्ट छापी, उसे खंडन नहीं भेजा. शायद उन्हें लगा कि हमारे पास इस संबंध में और जानकारी होगी और हम इसकी फॉलोअप स्टोरी करेंगे. कोयला घोटाले के ऊपर जब हमने लिखा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जेल जा सकते हैं, तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस रिपोर्ट के ऊपर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की. शायद तत्कालीन प्रधानमंत्री का कार्यालय इस विषय की गंभीरता को समझता था. इसीलिए उसने इसका कोई खंडन जारी नहीं किया.

मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिनके कोयला घोटाले संबंधी बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास नहीं किया और कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को शपथपत्र के साथ अपना बयान अदालत में दाखिल करना होगा. मनमोहन सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे, जिन्हें अपना बयान शपथपत्र के साथ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना पड़ा. मनमोहन सिंह सरकार के अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में बार-बार झूठ बोलते रहे, उनके क़ानून मंत्री बार-बार झूठ बोलते रहे. उनके न्याय सचिव और क़ानून सचिव सुप्रीम कोर्ट में ग़लत हलफनामे देते रहे. मनमोहन सिंह सरकार के सीबीआई के डायरेक्टर ऐसे डायरेक्टर बन गए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिखकर यह कहा कि रिपोर्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई और फिर दोबारा हलफनामा दिया कि रिपोर्ट में छेड़छाड़ हुई और फिर कहां-कहां छेड़छाड़ हुई, यह भी उन्होंने बताया. मनमोहन सिंह की सरकार को छोड़ दें, मनमोहन सिंह के बारे में बात करें. मनमोहन सिंह कोयला मंत्री थे. क्या मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे, जिसके न आंख थी, न कान थे? आख़िर वह सरकार चला कैसे रहे थे? जिस विषय पर तत्कालीन कोयला सचिव उन्हें बार-बार कह रहे हों कि यह प्रक्रिया ग़लत है और उसे मनमोहन सिंह अनदेखा कर रहे हों, तो क्या इसके लिए मनमोहन सिंह को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए?

जब यह कोयला घोटाला सामने आ गया, तब मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते उनके वरिष्ठ मंत्रियों ने, वकील मंत्रियों ने कहा कि यह जीरो लॉस है और सीएजी की रिपोर्ट ग़लत है, कोई नुक़सान हुआ ही नहीं, क्योंकि कोयला तो ज़मीन के अंदर ही दबा हुआ है. मनमोहन सिंह उन बयानों को सुनते रहे और शायद उन्हें अपनी टेबल से क्लियर भी करते रहे, क्योंकि यह घोटाला मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्वकाल में उनके कोयला मंत्री रहते हुआ था. इसलिए यह मानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी दलीलें दी जाती रहीं या राजनीतिक तौर पर उनके मंत्री जो रणनीति बनाते रहे, उनमें मनमोहन सिंह की सहमति अवश्य रही होगी.

अब मनमोहन सिंह को यह बयान देना चाहिए कि जिस नुक़सान की बात सीएजी ने कही थी यानी कि देश को 1.86 लाख करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ है, वह रकम अब दो लाख नौ हज़ार करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है, क्योंकि दो लाख नौ हज़ार करोड़ रुपये नीलामी के ज़रिये सरकार के पास आ चुके हैं. और, यह सिर्फ़ 33 कोल ब्लॉक्स की नीलामी में हुआ है. अभी दो सौ के आसपास कोल ब्लॉक्स की नीलामी होनी बाकी है. हम यहां याद दिला दें, हमने बार-बार कहा कि यह कोयला घोटाला 26 लाख करोड़ रुपये का है, यह 1.76 या 1.86 लाख करोड़ रुपये का घोटाला नहीं है. इसके ऊपर सीएजी भी खामोश रही और संसद भी. अब हमें लगता है कि यह कोयला घोटाला 26 लाख करोड़ रुपये से भी ज़्यादा बड़ा साबित होने जा रहा है, क्योंकि जब बाकी कोल ब्लॉक्स की नीलामी होगी और अभी जिस तरह से नीलामी में पैसा आ रहा है, उससे लगता है कि यह कोयला घोटाला 40 लाख करोड़ रुपये के आसपास पहुंचेगा.

हमें तो पिछली संसद के ऊपर भी थोड़ी हैरानी होती है. हमने राजनीतिक पार्टियों को कोयला घोटाले के बारे में अपनी छपी हुई रिपोर्ट्स भेजीं, सांसदों को भेजीं, लेकिन किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया. अगर सुप्रीम कोर्ट सजग न होता, तो कोयला घोटाला कभी देश के सामने आ नहीं सकता था, क्योंकि यह घोटाला इतनी सोच-समझ की रणनीति के साथ हुआ है कि इसके बारे में खुलासा होना असंभव था. इसका श्रेय सिर्फ़ और सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट को जाता है. पिछली संसद भी यह श्रेय ले सकती थी. यहां हम पिछली संसद की अवमानना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ यह बता रहे हैं कि पिछली संसद भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर थी ही नहीं, उसके लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा था ही नहीं और देश की व्यवस्था ठीक करने में उसकी रुचि ही नहीं थी. शायद इसीलिए उस संसद के ज़्यादातर सांसद हार गए और आज की संसद नए सांसदों की संसद है. पर हमें लगता है कि यह संसद भी भ्रष्टाचार को लेकर शायद उतनी गंभीर नहीं है.

कोयला घोटाला एक ऐसा घोटाला है, जो देश के लिए आईने का काम कर सकता है. कौन-सा ऐसा बड़ा कॉरपोरेट हाउस है, जो कोयला घोटाले में शामिल नहीं रहा? कुछ बड़े मीडिया समूहों ने भी कोल ब्लॉक्स पाने में सफलता हासिल की थी. कोल ब्लॉक एक ऐसा विषय है, जिस पर भविष्य में शोध होगा. पर सबसे ज़्यादा अफ़सोस अपने साथियों पर होता है कि इतना बड़ा मुद्दा सामने रहा, लेकिन किसी प्रिंट या टेलीविजन के पत्रकार ने इसकी परतें खोलने में रुचि नहीं दिखाई. अब कई टेलीविजन चैनल और पत्रकार दावा करते हैं कि उन्होंने सबसे पहले कोयला घोटाले को देश के सामने लाने में रोल प्ले किया. हम सबसे विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि आप दावे कीजिए, लेकिन झूठे दावे मत कीजिए, क्योंकि यह चीज हमने 2011 में ही 26 लाख करोड़ का महाघोटाला शीर्षक से छाप दी थी. और, 2013 में जब सारी बात सामने आने लगी और सुप्रीम कोर्ट का डंडा सीबीआई के ऊपर चलने लगा, तब जाकर आपको याद आया कि देश में कोई कोयला घोटाला भी हुआ है. हमें डर है कि आगे चलकर इस कोयला घोटाले में तत्कालीन बड़े राजनीतिक दलों के कुछ अध्यक्षों के भी नाम आ सकते हैं. और, जिन लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है, उन्होंने अपने उस फ़ायदे का हिस्सा कुछ राजनीतिक दलों के पास भी शायद पहुंचाया हो. हमें तो सोचते हुए भी डर लगता है कि अगर यह सच्चाई सामने आई, तो देश के लोगों का विश्वास राजनीतिक दलों की ईमानदारी से उठ जाएगा. अब तक राजनीतिक दल जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, लेकिन भ्रष्टाचार की इस महागंगा में राजनीतिक दल भी महान पुण्य एक समझौते के तहत कहीं कमा चुके हों और उसका खुलासा हो जाए, तो यह देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा अभिशाप साबित होगा. ■

editor@chauthiduniya.com

हम किस बात से डर रहे हैं

मेघनाद देसाई

भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य (मोटो) है, सत्यमेव जयते. सत्य हमें स्वतंत्रता देगा, गांधी जी अक्सर यह मंत्र पढ़ा करते थे. इसके बावजूद सरकार भारतीय वास्तविकता के कुछ पहलुओं की आलोचना पर बार-बार प्रतिबंध और निषेध लगा देती है. अब इसमें घबराने की क्या बात है, अगर ग्रीनपीस (जिसकी अधिकतर फंडिंग भारतीय दानकर्ताओं द्वारा होती है) से जुड़ा कोई भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता लंदन जाकर वहां के सांसदों की एक ग़ैर सरकारी समिति के समक्ष देश (भारत) के आदिवासियों की दुर्दशा बयान करना चाहता/चाहती है? सरकार अनावश्यक रूप से उसे वहां जाने से क्यों रोकना चाहती है? ऐसा करके क्या हासिल किया जा सकता है? इसका दुनिया में यह संदेश जाएगा कि भारत के पास कुछ रहस्य हैं, जिन्हें वह छिपाना चाहता है, जो उस विषय पर पहले से मौजूद जानकारियों से बदतर हैं.

भारत एक खुला और उदार समाज है. यहां नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी की गारंटी है और एक स्वतंत्र मीडिया है. क्या शासक वर्ग यह समझता है कि किसी एक कार्यकर्ता के विदेश दौरे पर पाबंदी लगाकर हम देश की छवि बेहतर बना सकते हैं? क्या यह गर्व करने लायक विषय न होता कि उस कार्यकर्ता को वहां जाकर अपनी बात रखने का मौक़ा दिया जाता? ऐसा करने से यह साबित हो जाता कि झूठ और दुष्प्रचार पर सच्चाई की जीत होती है. और, अब 16 दिसंबर, 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड के बारे में दस्तावेज़ी फिल्म (डाक्यूमेंट्री) पर प्रतिबंध! अब सवाल उठता है कि क्या यह बलात्कार नहीं हुआ था और क्या इसकी वजह से भारत और दुनिया के लोग सकते में नहीं आ गए थे? अगर अपराधियों में से एक शख्स किसी फिल्म निर्माता के सामने उक्त बलात्कार प्रकरण में अपना पक्ष रखता है, तो इसमें फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का क्या औचित्य है? क्या फिल्म पर प्रतिबंध लगा देने से उस अपराधी में सुधार आ जाएगा? क्या यह प्रतिबंध ऐसे लोगों के व्यवहार की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचने देगा? क्या भारत एवं दुनिया के लोग इस मामले और भारतीय नारी के साथ रोजाना होने वाले बलात्कार, छेड़छाड़ व उत्पीड़न की घटनाएं भूल जाएंगे?

इन दोनों घटनाओं में एक समानता है यानी विदेशियों से डर (जेनोफोबिया), जो कभी-कभी साम्राज्यवाद विरोध के नाम पर वामपंथ और देशभक्ति का लबादा ओढ़ लेता है. हम विदेशियों से नफ़रत क्यों करें या उनसे डरें क्यों? उत्तर कोरिया या क्यूबा की तरह अधिनायकवादी राष्ट्र सच्चाई दबा सकते हैं, लेकिन एक उदार लोकतंत्र ऐसा क्यों करे? क्या विदेशियों को केवल भारत का गुणगान करना चाहिए और जब वे एक सैलानी रूप में यहां आएं, तो उन्हें यहां की रोजाना की वास्तविक ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूम न हो? दरअसल, सरकारी अधिकारी समझते हैं कि किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाने से वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी. प्रभावशाली लोगों को भ्रम है कि वे आम जनता के दिलोदिमाग पर जिस तरह से चाहें, शासन कर सकते हैं और उसे अपनी रैयत समझ सकते हैं. उस पर इतना विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह अपने लिए सोच सके. एक ज़माना था, दुनिया के हर हिस्से में शक्तिशाली एवं प्रभावशाली लोगों की यही सोच थी. भला हो लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए सालों तक चलने वाले संघर्ष का, जिसके चलते लोगों को खुद सच्चाई जानने का अधिकार मिला. गांधी एवं टैगोर जैसे महापुरुष भी दृढ़ता से इस बात के पक्षधर थे कि बिना किसी डर के हर तरफ़ से अच्छे विचारों को आने देना चाहिए.

जब रिचर्ड ऐटनबरो गांधी पर अपनी फिल्म बना रहे थे, तो सरकारी अधिकारियों ने फिल्म की स्क्रिप्ट पर कई सवाल खड़े किए थे. किसी ने यहां तक सुझाया था कि गांधी की तस्वीर के बजाय एक जलते हुए दीपक को दिखाया जाए. ऐटनबरो ने यह कहकर इस विचार को खारिज कर दिया था कि वह टिंकर बेल पर कोई फिल्म नहीं बना रहे हैं! उनकी जिद की वजह से गांधी एक कभी न भुलाई जाने वाली क्लासिक फिल्म बन सकी. यह वह फिल्म थी, जिसने गांधी का परिचय उस नस्ल से कराया, जो उनकी मौत के दशकों बाद पैदा हुई थी. यह सच्चाई है कि नेहरू के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनी, क्योंकि परिवार को यह डर था कि उसमें एडविना माउंटबेटन के साथ उनका प्रेम प्रसंग दिखाया जाएगा, जो एक खुला राज़ था. जब सत्ता के वंशानुगत संरक्षक अपनी खामियां छिपाना चाहते हैं, तो वे आम जनता को बच्चा समझने लगते हैं.

जिन्ना के ऊपर बनी फिल्म पर भी तमाशा खड़ा किया गया था. मैं उन गिने-चुने लोगों में से था, जिन्होंने यह बेहतरीन फिल्म देखी थी. यह फिल्म भारत और पाकिस्तान में प्रतिबंधित थी! पाकिस्तान में इस फिल्म पर पाबंदी लगाने की वजह यह थी कि इसमें जिन्ना को धूम्रपान, मदिरापान और सूअर के मांस का सेवन करते हुए दिखाया गया था. भारत में प्रतिबंध की वजह यह थी कि उन्हें सींग वाले शैतान के बजाय एक सामान्य इंसान के रूप में दिखाया गया था. खुशकिस्मती से अब सेंसरशिप कारगर नहीं होती. दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरण पर बनी दस्तावेज़ी फिल्म (डाक्यूमेंट्री) इंटरनेट द्वारा दिखाई जाएगी. केवल मंत्री यह सोचते हैं कि वे सच्चाई पर पाबंदी लगा सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

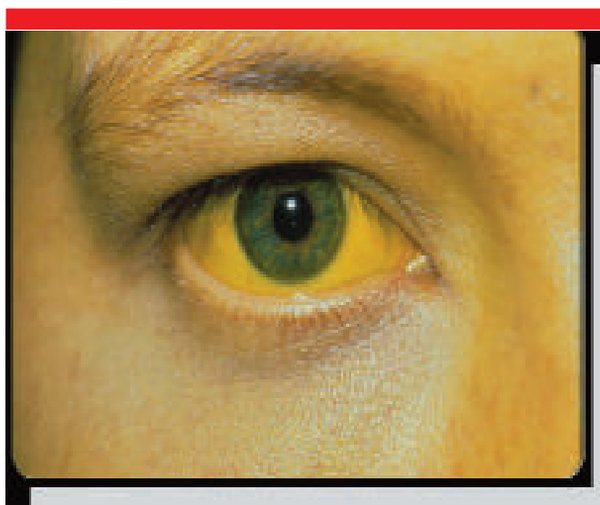

हेपेटाइटिस
वैक्सीनेशन है बचाव का तरीका

मोनिशा भटनागर

हेपेटाइटिस लीवर के सूजन की बीमारी है जो ज़्यादातर वायरल संक्रमण की वजह से होती है. हेपेटाइटिस वायरस के पांच मुख्य प्रकार हैं – ए, बी, सी, डी और ई. हेपेटाइटिस टाइप बी और सी खासकर लाखों लोगों में जीर्ण रोग का कारण बनते हैं और दोनों लीवर सिरोसिस और कैंसर का सबसे आम कारण हैं. हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस होने का सबसे बड़ा कारण होता है लेकिन अल्कोहल के लंबे समय तक ज़्यादा सेवन और कुछ विषैली दवाओं तथा ऑटोइम्यून डिजीज के कारण भी यह बीमारी हो सकती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, मध्य-पूर्व एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों में दो से पांच फीसदी लोग हेपेटाइटिस से पीड़ित हैं. इस बीमारी की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इसका पता जल्दी नहीं लगता और न ही कोई ख़ास लक्षण नज़र आते हैं.

हेपेटाइटिस की दो अवस्थाएं होती हैं, पहली, प्रारंभिक यानी कि एक्यूट और दूसरी पुरानी अर्थात क्रॉनिक. हेपेटाइटिस की प्रारंभिक अवस्था शुरू के तीन महीनों तक रहती है. लेकिन यदि छह महीनों तक इसका इलाज नहीं हो तो यह क्रॉनिक हेपेटाइटिस की रूप ले लेती है. शुरुआती दौर में यदि हेपेटाइटिस के साथ पीलिया हो जाए और इसका उपचार ठीक से न हो तो यह क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी या सी का रूप ले लेती है. इसके बाद भी इसका उचित इलाज न हो तो यह लिवरसिरोसिस में परिवर्तित हो जाती है जिसके कारण पूरा लीवर खराब हो जाता है और लीवर का कैंसर भी हो सकता है.

कैसे फैलता है हेपेटाइटिस

हेपेटाइटिस ए और ई आम तौर पर दूषित भोजन या पानी के सेवन की वजह से होतें हैं. साफ-सफाई से न रहने और कोई खाद्य पदार्थ को खाने से पहले कीटाणु नाशक साबुन से हाथ न धोने से इस रोग के जोख़िम बढ़ जाते हैं. हेपेटाइटिस बी, सी और डी आमतौर पर संक्रमित शरीर के तरल पदार्थ के साथ पैरेंटल संपर्क के परिणामस्वरूप होते हैं. इन वायरस के संचरण के आम साधन दूषित रक्त या रक्त उत्पादों की प्राप्ति, इनवेसिव चिकित्सा प्रक्रियाओं में दूषित उपकरण के प्रयोग और इंजेक्शन द्वारा ड्रग लेना हैं. हेपेटाइटिस बी जन्म के समय मां से बच्चे को या परिवार के किसी सदस्य से बच्चे को हो सकता है. इसके अलावा टैटू बनवाने से, किसी संक्रमित व्यक्ति का टूथब्रश और रेज़र इस्तेमाल करने से और असुरक्षित यौन संपर्क से भी हेपेटाइटिस बी और सी होने का खतरा बढ़ जाता है. हेपेटाइटिस बी और सी का वाइरस हाथ मिलाने, खाने के बर्तनों और पानी पीने के गिलासों का इस्तेमाल करने पर नहीं फैलता. इसी तरह यह वायरस छींकने, खांसने, गले मिलने या चूमने से भी नहीं फैलता. हेपेटाइटिस ए और बी की रोकथाम के लिए वैक्सीन उपलब्ध है. सभी नवजात बच्चों को इस वैक्सीन को लगवाना चाहिए.

हेपेटाइटिस ए

इसमें लीवर में सूजन हो जाती है और ऐसा इस बीमारी के विषाणु के कारण होता है. इसे वायरल हेपेटाइटिस भी कहते हैं. जब लीवर रक्त से बिलीरूबिन को छान नहीं पाता है तो हेपेटाइटिस होता है. हालांकि हेपेटाइटिस के सभी रूपों में हेपेटाइटिस ए सबसे कम गंभीर है. इसका वायरस दूषित पानी से सबसे ज्यादा फैलता है. इसके मुख्य लक्षण हैं, बुखार, झुरझुरी आना, भूख न लगना, खाने को देख जी मिचलाना, उल्टी, बदन दर्द और सिगरेट पीने वालों को तंबाकू से अरुचि. हैपेटाइटिस ए से बचाव के लिए साफ-सफाई का विशेष ख्याल रखें, दूषित भोजन व पानी से दूर रहें और हेपेटाइटिस ए का टीका ज़रूर लगवाएं.

हेपेटाइटिस बी

इसे सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं. इस टाइप का प्रभाव लीवर पर ऐसा पड़ता है कि अधिकांश रोगी सिरोसिस ऑफ लीवर के शिकार हो जाते हैं. इसके मुख्य लक्षण हैं त्वचा और आँखों का पीलापन, गहरे रंग का पेशाब, अत्यधिक थकान, उल्टी और पेट दर्द.

हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए घाव होने पर उसे खुला न छोड़ें, यदि त्वचा कट जाए तो उस हिस्से को डेटॉल से साफ करें. किसी के साथ अपने टूथब्रश, रेजर, सुई, सिरिंज, कैंची या अन्य ऐसी वस्तुएं जो आपके खून के संपर्क में आती हो शेयर न करें. सुरक्षित यौन संबंध बनाएं और शराब ना पिएं. नवजात बच्चों को टीका ज़रूर लगवाएं.

हेपेटाइटिस सी

यह जानलेवा वायरस कई सालों तक पकड़ में नहीं आता और इससे फिबरोसिस, क्रॉनिक सिरोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं. इस बीमारी से लीवर बुरी तरह प्रभावित होता है. यह बीमारी मुख्य तौर पर संक्रमित रक्त के माध्यम से फैलती है. हेपेटाइटिस सी से बचाव के लिए भी अपने घाव को खुला ना छोड़ें ,शराब पीना कम कर दें और दवाई के उपकरण को शेयर न करें. अगर पियर्सिंग या टैटू करवायें तो यह देख लें कि उपकरण अच्छे से साफ हों.

हेपेटाइटिस डी

हेपेटाइटिस डी का फिलहाल कोई इलाज मौजूद नहीं है. हेपेटाइटिस डी से बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा लें क्यों कि जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी होता है उन्हें ही यह बीमारी होने की आशंका रहती है. इसलिए हेपेटाइटिस डी के लिए हेपेटाइटिस बी के लिए दिए गए एहतियात ही बरतें.

हेपेटाइटिस ई

इस बीमारी का वायरस मुंह के जरिये प्रवेश कर सकता है. हेपेटाइटिस ई से संक्रमित पानी पीने से यह वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है. फिलहाल हेपेटाइटिस ई से बचाव के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है लेकिन इसका इलाज सम्भव है. हेपेटाइटिस ई से संक्रमित लोगों के लिए हेपेटाइटिस ए के लिए दिए गए बचाव के तरीके ही कारगर हैं.

हेपेटाइटिस ए के टीके के ज़्यादातर सब टीका प्राप्तकर्ताओं में, एंटीबॉडी पहली खुराक के बाद तुरंत विकसित होना शुरू हो जाते है, लेकिन 2 से 4 सप्ताह तक सुरक्षात्मक स्तर तक नहीं पहुंचते हैं. टीके की दूसरी खुराक लंबे समय तक संरक्षण प्रदान करने के लिए पहली खुराक के कम से कम छह महीने बाद लेनी चाहिए. हेपेटाइटिस बी के टीके सभी उम्र के लिए एचबीवी संक्रमण को रोकने के लिए उपलब्ध है. हेपेटाइटिस वायरस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है बीमारी होने से पहले ही टीकाकरण यानि वैक्सीनेशन करवा लेना. ■

feedback@chauthiduniya.com

मैं हिटलर को हारते देखना चाहती हूं-डायना

अरुण तिवारी

मैं हिटलर को हारते हुए देखना चाहती हूं....यही कहना था डायना रोडेन का. द्वितीय युद्ध के दौरान न जाने कितनी महिला जासूसों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था. उन्हें उनके बलिदान के लिए जाना जाता है. डायना ऐसी ही महिला जासूसों में शुमार की जाती हैं जिन्होंने हिटलर की तानाशाही के ख़िलाफ़ अपनी जिंदगी की बाज़ी लगाकर लड़ाई लड़ी. भले ही इस जंग में उनकी मौत हो गई हो लेकिन उनके जज्बे की जीत हुई और आख़िरकार जर्मन सेनाओं को हार का स्वाद चखना पड़ा. आइए महिला जासूसों की अपनी श्रृंखला में इस बार आपको रूबरू कराते हैं बहादुर जासूस डायना रोडेन से...

डायना रोडेन का जन्म 31 जनवरी 1915 को ब्रिटेन में हुआ था. उनके पिता मेजर एलड्रेड ब्रिटिश सेना में अधिकारी थे. उनकी मां का नाम मुरियल क्रिस्चियन था. वे अपने मां बाप की पहली संतान थीं लेकिन उनके मां बाप के बीच रिश्ते बेहतर न होने के कारण शादी ज्यादा दिनों तक टिक न सकी और जब डायना बहुत छोटी उम्र की थीं तभी दोनों अलग हो गए. डायना की मां उन्हें लेकर फ्रांस चली गईं.

अपनी शिक्षा की शुरुआत डायना ने वहीं से की लेकिन कुछ सालों बाद उनकी मां एक बार फिर रहने के लिए ब्रिटेन वापस आ गईं. यहां उनका दाखिला मैनर हाउस स्कूल में कराया गया. यहीं पर उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की. इसके बाद वे फिर फ्रांस चली गईं और एक पत्रकार के रूप में नौकरी में कदम रखा. बातचीत के दौरान लोगों के मन से बातें उगलवा लेने की ट्रेनिंग की शुरुआत यहीं से हुई. डायना ने अपने पेशे में महारत हासिल करना शुरू कर दिया. वे बड़े-बड़े लोगों के साक्षात्कार लिया करती थीं. साक्षात्कार के दौरान वे उन लोगों से वह बातें भी उगलवा लिया करती थीं जो साधारणतया वे लोग किसी और को बताने से गुरेज किया करते थे.

जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो उन्होंने फ्रेंच रेड क्रॉस संस्था ज्वाइन कर ली. उन्हें एंग्लो अमेरिकन एंबुलेंस कॉर्प में रखा गया. मई 1940 में मित्र राष्ट्र की सेना जर्मनी के हाथों हार गई. लेकिन डायना को फ्रांस से बाहर निकल पाने का मौका नहीं मिला. वे फ्रांस के भीतर ही फंस कर रह गईं. डायना हार मानने वालों में से नहीं थीं, वे काफी दिनों तक इस बात का इंतज़ार करती रहीं कि कब उन्हें एक मौका हाथ लगे और वह वहां से भाग निकलें. ऐसा मौका उन्हें जल्दी ही मिला जब उनके रेड क्रॉस के ही एक सहयोगी के जरिए वहां से भागने में सफलता हाथ लगी. वे पहले फ्रांस से छिपते-छिपाते स्पेन पहुंचीं और फिर पुर्तगाल के रास्ते ब्रिटेन पहुंचने में कामयाब रहीं.

सितंबर 1941 में उन्होंने ब्रिटेन की ऑक्जिलरी विमेन एयर फोर्स ज्वाइन कर ली. यह महिलाओं का एक ऐसा दस्ता था जो मुश्किल में फंसे लोगों की मदद किया करता था. उन्होंने वहां ब्रिटेन के लिए बेहतरीन सेवाएं देना शुरू दिया जिसकी वजह से कुछ ही दिनों बाद उनका प्रमोशन कर दिया गया.

उसी दौरान डायना की तबियत खराब हो गई और उन्हें अस्प ताल

जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो उन्होंने रेड क्रॉस संस्था ज्वाइन कर ली. मई 1940 में मित्र राष्ट्र की सेना जर्मनी के हाथों हार गई. डायना फ्रांस के भीतर ही फंस कर रह गईं. वे काफी दिनों तक इंतज़ार करती रहीं कि कब उन्हें एक मौका हाथ लगे और वह भाग निकलें. ऐसा मौका उन्हें जल्दी ही मिला जब उनके रेड क्रॉस के ही एक सहयोगी के जरिए वहां से भागने में सफलता हाथ लगी. वे पहले फ्रांस से छिपते-छिपाते स्पेन पहुंचीं और फिर पुर्तगाल के रास्ते ब्रिटेन पहुंचने में कामयाब रहीं.

में भर्ती होना पड़ा. बीमारी के दौरान उनकी मुलाकात एक ब्रिटिश अधिकारी हैरी स्पोंबर्ग से हुई जो उनके बगल की एक मरीज को देखने आए हुए थे. हैरी ने डायना से यह इच्छा ज़ाहिर की कि वे उनकी सेक्रटरी बनें. इसके बाद पहले से एयर फोर्स की महिला शाखा में तैनात डायना ने मिलिट्री ट्रेनिंग भी लेनी शुरू कर दी. ट्रेनिंग में जब उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा था तो उनके कई अधिकारियों के साथ मुधर रिश्ते बन गए. ऐसे ही एक अधिकारी विलियम सिंपसन से एक मुलाकात के दौरान अपनी यह इच्छा जाहिर की कि उन्हे फिर लौटकर फ्रांस जाना है और नाजियों के खिलाफ काम करना है. उन्होंछने सिंपसन से कहा था कि मैं हिटलर की सेनाओं को हारते हुए देखना चाहती हूं. उनकी इच्छा थी कि वे ब्रिटेन में रहकर फ्रांस की मदद न करें बल्कि वहां जाकर जर्मन सैनिकों के साथ लोहा लें. इसके लिए वह फ्रांस में जर्मनी के विरोध के लिए बने फ्रेंच रजिस्टेंस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती थीं.

उन्हें इसका मौका भी जल्दी ही मिला और उन्हें अपनी दो महिला साथियों, नूर इनायत खान और लॉयर वैली, के साथ जर्मनी अधिकृत फ्रांस में उतारा गया. वहां पर उन्होंने अपने साथियों के साथ जर्मन सेना की कई गोपनीय जानकारियां ब्रिटेन तक पहुंचाई. डायना आसानी से जर्मन अधिकारियों को अपने जाल में फांस लिया करती थीं. कई जर्मन अधिकारी उनके काफी करीब आ गए थे और उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगती थी कि उनकी सारी जानकारियां विरोधियों तक पहुंचाई जा रही हैं.

उनकी गिरफ्तारी भी बहुत ही नाटकीय अंदाज में हुई. नवंबर 1943 के मध्य में जासूसों को वायरलेस के जरिये यह जानकारी दी गई 18 नवंबर को ब्रिटेन की ओर से एक और नया जासूस भेजा जा रहा है. सभी महिला जासूस उसकी मदद के लिए तैयार हो चुकी थीं. लेकिन 18 नवंबर को ब्रिटिश एजेंट की बजाये एक जर्मन एजेंट वहां पहुंचा जिसने वहां मौजूद ब्रिटिश जासूसों की गिरफ्तारी करवा दी. डायना भी अन्य जासूसों के साथ गिरफ्तार कर ली गईं. डायना को अन्य साथियों साथ जर्मन प्रताड़ना गृह ले जाया गया. जहां उन्हें तरह-तरह से प्रताड़ना दी गई. बाद में जहरीले इंजेक्शन के जरिये उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया.

डायना को ब्रिटिश जासूसों के इतिहास में काफी इज्जत से याद किया जाता है. उन्होंने ब्रिटेन की ओर से फ्रांस को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी. मौत के बाद उन्हें ब्रिटिश सरकार की ओर से कई पुरस्कार दिए गए. जिस जर्मन प्रताड़ना गृह में उन्हें यातनाएं दी गई थीं अब वह फ्रांस का हिस्सा है. वह अब एक ऐतिहासिक जगह बन चुकी है. यहां पर डायना की याद में उनके नाम का मेमोरियल भी बनाया गया है. ■

पाकिस्तानी तालिबान से जुड़ी एक सच्चाई यह भी है कि अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों में कुछ आतंकवादी घटनाएं ऐसी हुई हैं, जिनके तार तालिबान से जुड़े हुए हैं. इन घटनाओं से पश्चिमी देश पाकिस्तान से नाराज़ हैं कि वह तालिबान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और आतंकवाद के प्रति उसका रवैया सख्त नहीं है. बहरहाल, अमेरिका के ड्रोन हमलों और अमेरिकी–नाटो सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तानी सैनिकों की मौत ने जहां देश की संप्रभुता का उल्लंघन किया, वहीं ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में पाया जाना अंतरराष्ट्रीय समुदाय में देश की किरकिरी का कारण बना.

पाकिस्तानी राजनीति का भविष्य

पाकिस्तान के सभी जातीय समूहों में केवल पंजाबी और मुहाजिर (1947 के विभाजन के बाद भारत से गए लोग) ही ऐसे हैं, जो बुनियादी तौर पर यूनाइटेड पाकिस्तान के हक़ में हैं. कुल मिलाकर पाकिस्तान एक ऐसे दलदल में फंसा हुआ नज़र आ रहा है, जहां से केवल कोई करिश्माई नेतृत्व ही उसे बाहर निकाल सकता है. पाकिस्तान को अभी ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है, जो अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के साथ-साथ देश के शक्तिशाली शासक वर्ग से भी निपट सकने में सक्षम हो.

शफ़ीक आलम

ऐसा लगता है कि एक आधुनिक नेशन स्टेट के तौर पर पाकिस्तान द्वारा उठाया गया कोई भी क़दम उसके लिए कारगर नहीं साबित हुआ है. हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि पाकिस्तान की राजनीति पर नज़र रखने वाले टिप्पणीकारों को हैरानी होती है कि यह देश अभी तक कैसे बचा हुआ है. जहां एक तरफ़ पाकिस्तान की राजनीति पर तीन विवादित किताबें लिख चुके तारिक अली जैसे राजनीतिक आलोचक हैं, जो पिछले चार दशकों से पाकिस्तान के टूटने की भविष्यवाणी करते चले आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ़ अनाटोल लिवेन एवं यान तोल्बट जैसे समीक्षक भी हैं, जो पाकिस्तान के भविष्य को लेकर अभी भी आशांवित हैं.

पाकिस्तान के बिखराव की भविष्यवाणी के पीछे कई कारण हैं. सबसे पहला कारण यह है कि पाकिस्तान में एक के बाद एक आने वाली लोकतांत्रिक और फौजी हुकूमतें शासन व्यवस्था के हर मोर्चे पर असफल नज़र आती हैं. ये सरकारें देश के नागरिकों के लिए साफ़ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बिजली जैसी सुविधाएं मुहैया कराने में नाकाम रहीं. देश में महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है, उद्योग-धंधों की हालत खराब है और विदेशी निवेश न के बराबर है. क़ानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि कराची एवं लाहौर जैसे बड़े शहर भी आम नागरिकों के लिए सुरक्षित नहीं हैं. पाकिस्तानी तालिबान न केवल पाकिस्तान-अफ़ग़ानिस्तान सीमा पर अपने सुरक्षित ठिकानों पर सक्रिय हैं, बल्कि वे जब चाहते हैं, देश के किसी भी सुरक्षा घेरे को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं. कराची हवाई अड्डे पर उनका हमला हो या रावलपिंडी के आर्मी स्कूल में उनकी दरिंदगी या फिर देश के दूसरे हिस्सों में होने वाले आत्मघाती हमले, तालिबान के हमलों ने दरअसल पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियां बेनकाब कर दी हैं. इसके अलावा पाकिस्तान की विदेश नीति भी असफल नज़र आती है. दरअसल, पाकिस्तान अपने ही जाल में फंसता जा रहा है.

पाकिस्तानी तालिबान से जुड़ी एक सच्चाई यह भी है कि अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों में कुछ आतंकवादी घटनाएं ऐसी हुई हैं, जिनके तार तालिबान से जुड़े हुए हैं. इन घटनाओं से पश्चिमी देश पाकिस्तान से नाराज़ हैं कि वह तालिबान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और आतंकवाद के प्रति उसका रवैया सख्त नहीं है. बहरहाल, अमेरिका के ड्रोन हमलों और अमेरिकी-नाटो सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तानी सैनिकों की मौत ने जहां देश की संप्रभुता का उल्लंघन किया, वहीं ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में पाया जाना अंतरराष्ट्रीय समुदाय में देश की किरकिरी का कारण बना. इसके चलते अमेरिका में यह सवाल उठने लगा कि अमेरिकी करदाता ओसामा की रक्षा के लिए पाकिस्तान को पैसा क्यों दें? इसके अलावा ब्लूचिस्तान प्रांत में एक पृथकतावादी आंदोलन चल रहा है. पाकिस्तान इसके लिए हमेशा भारत और अफ़ग़ानिस्तान को दोषी करार देता रहा है. वहीं पाकिस्तानी अख़बारों में छपी रिपोर्टें पाकिस्तान सरकार को इसके लिए दोषी करार देती हैं. इसी प्रकरण का ज़िक्र करते हुए पाकिस्तानी लेखक मोहसिन हामिद लिखते हैं कि ब्लूचिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ असंतोष पाकिस्तान द्वारा वहां के लोगों के प्रति दुर्व्यवहार की वजह से है. वहीं अफ़ग़ानिस्तान भी पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता स्वीकार करने से इंकार करता रहा है. सिंध प्रांत में भी केंद्रीय सत्ता को लेकर असंतोष है.

दरअसल, पाकिस्तान के सभी जातीय समूहों में केवल पंजाबी और मुहाजिर (1947 के विभाजन के बाद भारत से गए लोग) ही ऐसे हैं, जो बुनियादी तौर पर यूनाइटेड पाकिस्तान के हक़ में हैं. कुल मिलाकर पाकिस्तान एक ऐसे दलदल में फंसा हुआ नज़र आ रहा है, जहां से केवल कोई करिश्माई नेतृत्व ही उसे बाहर निकाल सकता है. पाकिस्तान को अभी ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है, जो अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के साथ-साथ देश के शक्तिशाली शासक वर्ग से भी निपट सकने में सक्षम हो. 1947 में भारतीय मुसलमानों के लिए दुनिया के मानचित्र पर एक पृथक लोकतांत्रिक देश के रूप में पाकिस्तान का उदय हुआ था. तबसे अब तक इस देश में चार बार सेना ने निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट कर सत्ता पर क़ब्ज़ा किया है और अपने 68 वर्ष के इतिहास में यह देश ने 33 साल तक सैन्य शासन में रहा. इस बीच तीन बार संविधान बदला गया और कई बार संविधान को ताख पर रख दिया गया. कहने का आशय यह कि सेना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश की सत्ता पर काबिज़ रही. अपने शुरुआती दिनों से ही पाकिस्तान ने ऐसी नीति अपनाई, जो उसके लिए घातक और विघटनकारी साबित हुई. पाकिस्तान ने अपना जो पहला बड़ा फ़ैसला लिया था, वह था कश्मीर में कबायलियों का हमला कराना. उसके बाद कश्मीर एक ऐसा मसला बन गया, जिसे लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच चार युद्ध हुए. पाकिस्तान दो हिस्सों में विभाजित हो गया, लेकिन कश्मीर का मसला अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है.

शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी बन गया. अफ़ग़ानिस्तान पर सोवियत संघ के हमले के ख़िलाफ़ कार्रवाई के दौरान अमेरिका की मदद से अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर बहुत सारे मदरसे खोले गए और इस्लामीकरण का दौर शुरू हुआ. यह वही दौर था, जब पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल जिया-उल-हक़ ने देश में शरिया क़ानून लागू किया, जो अब तक जारी है. पाकिस्तान ने दूसरे देशों में विद्रोह और आतंकवाद को बढ़ावा-सहयोग देना अपनी नीति बना ली, चाहे वह अफ़ग़ानिस्तान में मुजाहिदीन का मामला हो या कश्मीर में आतंकवाद. अफ़ग़ानिस्तान में सोवियत संघ की पराजय और शीत युद्ध के ख़ात्मे के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया. नतीजे में पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान में गृहयुद्ध के दौरान तालिबान को देश पर क़ब्ज़ा दिलाने में मदद पहुंचाई, लेकिन न्यूयॉर्क के 9/ 11 के हमलों के बाद उपजे हालात में पाकिस्तान को न चाहते हुए भी एक बार फिर अमेरिका के युद्ध में भागीदार बनना पड़ा और अपने ही द्वारा तैयार किए गए लड़ाकों से लड़ना पड़ा. आतंकवाद के ख़िलाफ़ इस अमेरिकी लड़ाई ने नवाज़ शरीफ की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर सत्ता पर काबिज़ हुए जनरल मुशर्रफ के सैन्य शासन को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान की थी.

पाकिस्तानी राजनीति की एक और विशेषता यह रही है कि यहां लोकतंत्र को कभी फलने-फूलने नहीं दिया गया. नतीजा यह हुआ कि सत्ता में आम लोगों की भागीदारी नहीं हो पाई, जैसे भारत या विभाजन के बाद बांग्लादेश में है. पाकिस्तान की विदेश नीति सेना तय करती है. अगर चीन से रिश्ते की बात करनी होती है, तो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जाते हैं. अगर अफ़ग़ानिस्तान से रिश्तों की बात होती है, तो सेना के नुमाइंदे पहले जाते हैं, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जाते हैं. पाकिस्तान की अफ़ग़ान नीति का उल्टा असर हुआ है. अफ़ग़ानिस्तान से नाटो फौजों की वापसी की वार्ता में पाकिस्तान अफ़ग़ानी तालिबान को भी शामिल करने के लिए कोशिश करता रहा. दरअसल, हामिद करज़ई के कार्यकाल में पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के रिश्तों में खटास बनी रही. वजह थी, पाकिस्तान द्वारा तालिबान की मदद करना. तालिबान के समर्थन के पीछे पाकिस्तान की सोच यह है कि भारत के साथ युद्ध की स्थिति में वह उसकी मदद करेगा. लेकिन, इसका नतीजा यह हुआ कि तालिबान पाकिस्तान की अनदेखी करके अमेरिका से ख़ुफ़िया शांति वार्ता करते रहे, जो पाकिस्तान की विदेश नीति की नाकामी दर्शाने के लिए काफी है. इसी तरह पाकिस्तान ब्लूचिस्तान में विद्रोह के लिए भारत को ज़िम्मेदार ठहराता है.

अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के रिश्तों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है. पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर हमले के बाद पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान में नाटो सप्लाई कई दिनों तक बाधित रखी. अमेरिका यह जानता था कि अफ़ग़ानिस्तान में नाटो सप्लाई पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ही एकमात्र रास्ता था. लेकिन, भारत द्वारा ईरान-अफ़ग़ानिस्तान को सड़क से जोड़े जाने और भारत की मदद से विकसित किए गए रूट नंबर 606 के निर्माण के बाद अब अमेरिका अपनी सप्लाई इस रास्ते से भी कर सकता है. यही नहीं, अफ़ग़ानिस्तान से नाटो फौजों की वापसी के बाद यह रूट व्यवसायिक दृष्टि से पाकिस्तान को अलग-थलग कर सकता है. पाकिस्तान ने भारत से कथित ख़तरे के मद्देनज़र परमाणु हथियारों का निर्माण किया और पूरी मुस्लिम दुनिया की कयादत का दावा किया, खास तौर पर जनरल मुशर्रफ ने अपने कार्यकाल में मुस्लिम उम्मा की बात की. लेकिन, सबसे सकारात्मक बात यह है कि पाकिस्तानी जनता इस यथास्थिति से ऊब गई है और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करने लगी है. जस्टिस इफ्तिख़ार चौधरी का जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन और इमरान खान का नवाज़ शरीफ सरकार के ख़िलाफ़ धरना इसी ओर इशारा करते हैं. पाकिस्तान के लोकतंत्र या राजनीति की सबसे बड़ी नाकामी यह रही कि यहां एक प्रभावशाली मध्यम वर्ग नहीं बन सका. जिसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान एक आधुनिक नेशन स्टेट के तौर पर खुद को स्थापित नहीं कर पाया. देश की जातीय विविधता को एक धागे में पिरोने के लिए मज़हब के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है. लेकिन, पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद यह अवधारणा भी ग़लत साबित हो गई.

भ्रष्टाचार के मामले में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों और सैन्य शासकों का हाल एक जैसा रहा है. आयशा जलाल ने अपनी किताब-मिलिट्री इंक में पाकिस्तानी सेना का भ्रष्टाचार उजागर किया है. वहीं भूतपूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी को उनके भ्रष्टाचार की वजह से मिस्टर टेन पर्सेंट के नाम से जाना जाता है. देश की राजनीति में वंशवाद और भाई-भतीजावाद का बोलबाला है. हकीकत में देश पर या तो सेना का शासन होता है या फिर शरीफ अथवा भुट्टो परिवार का. हालांकि, आज भी पाकिस्तान की राजनीति पर सेना का वर्चस्व कायम है और देश को परिवारवाद से भी इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलने वाली, लेकिन लोग अब दूसरे विकल्पों की तरफ़ भी देखने लगे हैं, जो लोकतांत्रिक पाकिस्तान के लिए एक सकारात्मक क़दम है. देश अब अपनी पुरानी विदेश नीति छोड़कर नई संभावनाएं तलाश रहा है. भूमि सुधार शायद पहली बार सार्वजनिक बहस का हिस्सा बना है. धार्मिक अतिवाद के ख़िलाफ़ आम लोग खुलकर अपनी राय रखने लगे हैं. पाकिस्तान में ऐसे लोगों की अच्छी-खासी संख्या है, जो धार्मिक अल्पसंख्यकों की दुर्दशा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने लगे हैं. पाकिस्तान में अपनी हर कमी को भारत अमेरिका या इजरायल की साजिश करार देकर टाल दिया जाता था. अब लोग इस थ्योरी का भी मज़ाक उड़ाने लगे हैं. कुल मिलाकर देखा जाए, तो कहा जा सकता है कि सेना कभी भी सत्ता पर अपनी पकड़ कमज़ोर नहीं करना चाहेगी, लेकिन यह भी हकीकत है कि निकट भविष्य में वह लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई किसी सरकार का तख्ता नहीं पलट पाएगी.■

feedback@chauthiduniya.com

भ्रष्टाचार के मामले में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों और सैन्य शासकों का हाल एक जैसा रहा है. आयशा जलाल ने अपनी किताब-मिलिट्री इंक में पाकिस्तानी सेना का भ्रष्टाचार उजागर किया है. वहीं भूतपूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी को उनके भ्रष्टाचार की वजह से मिस्टर टेन पर्सेंट के नाम से जाना जाता है. देश की राजनीति में वंशवाद और भाई-भतीजावाद का बोलबाला है. हकीकत में देश पर या तो सेना का शासन होता है या फिर शरीफ अथवा भुट्टो परिवार का. हालांकि, आज भी पाकिस्तान की राजनीति पर सेना का वर्चस्व कायम है और देश को परिवारवाद से भी इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलने वाली, लेकिन लोग अब दूसरे विकल्पों की तरफ़ भी देखने लगे हैं, जो लोकतांत्रिक पाकिस्तान के लिए एक सकारात्मक क़दम है.

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
CHAUTHI DUNIYA
چوتھی دنیا
First International Urdu Weekly
Chauthi Duniya
Santosh Bhartiya
चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

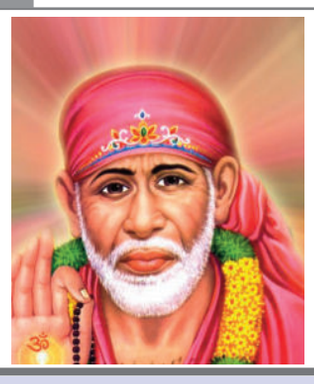

एक समय तात्या कोते पाटील तांगे में बैठकर कोपरगांव बाजार जा रहे थे. वे शीघ्रता से मजिस्द में आये और बाबा को नमन किया और कहा कि मैं कोपरगांव बाजार जा रहा हूं. बाबा ने कहा, शीघ्रता न करो, थोड़ा ठहरो. बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर न जाओ. उनकी उतावलापन देखकर साई बाबा ने कहा कि अच्छा, कम से कम शामा को साथ लेते जाओ. बाबा की आज्ञा की अवहेलना करके उन्होंने तुरन्त तांगा आगे बढ़ाया. तांगे के दो घोड़ो में से एक घोड़ा जिसका मूल्य उस समय लगभग तीन सौ रुपये था, अति चंचल और द्रुतगामी था. रास्ते में सावली विहीर गांव पार करते ही वह अधिक तेजी से दौड़ने लगा. अचानक उसकी कमर में मोच आ गई.

शिरडी यात्रा की विशेषता

चौथी दुनिया ब्यूरो

शिरडी यात्रा की एक विशेषता यह थी कि बाबा की आज्ञा के बिना कोई भी शिरडी से प्रस्थान नहीं कर सकता था और यदि किसी ने किया भी, तो मानो उसने अनेक कष्टों को निमंत्रण दे दिया. परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई तो फिर वहां उसका ठहरना भी नहीं हो सकता था. जब भक्तगण लौटते समय बाबा को प्रणाम करने जाते थे, तब बाबा उन्हें कुछ आदेश दिया करते थे, जिनका पालन अतिआवश्यक था. यदि इन आदेशों की अवज्ञा कर कोई लौट गया तो निश्चय ही उसे किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता था. ऐसे ही कुछ उदाहरण यहां प्रस्तुत हैं.

एक समय तात्या कोते पाटिल तांगे में बैठकर कोपरगांव बाजार जा रहे थे. वे शीघ्रता से मजिस्द में आये और बाबा का नमन किया और कहा कि मैं कोपरगांव बाजार जा रहा हूं. बाबा ने कहा, शीघ्रता न करो, थोड़ा ठहरो. बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर न जाओ. उनका उतावलापन देखकर साई बाबा ने कहा कि यदि जाना जरूरी है तो कम से कम शामा को साथ लेते जाओ. बाबा की आज्ञा की अवहेलना करके उन्होंने तुरन्त तांगा आगे बढ़ाया. तांगे के दो घोड़ों में से एक जिसका मूल्य उस समय लगभग तीन सौ रुपये था, अति चंचल और द्रुतगामी था. रास्ते में सावली विहीर गांव पार करते ही वह अधिक तेजी से दौड़ने लगा. अचानक उसकी कमर में मोच आ गई. वह वहीं गिर पड़ा. हालांकि तात्या को अधिक चोट नहीं आई लेकिन उन्हें साई के आदेशों की स्मृति अवश्य हो आई. एक अन्य अवसर पर कोल्हार गांव जाते हुए भी उन्होंने बाबा के आदेशों की अवज्ञा की थी. तब भी ऊपर वर्णित घटना के समान ही उन्हें दुर्घटना का सामना करना पड़ा था.

इसी तरह एक बार बंबई के एक यूरोपियन महाशय, नानासाहेब चांदोरकर से परिचय–पत्र प्राप्त कर किसी विशेष कार्य से शिरडी आये. उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहराया गया था. वे बाबा के समक्ष नतमस्तक होकर उनके करकमलों का चुंबन करना चाहते थे. इसी उद्देश्य से उन्होंने तीन बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परन्तु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने से रोक दिया. उन्हें आंगन में ही ठहरने और वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली. इस विचित्र स्वागत से अप्रसन्न होकर उन्होंने शीघ्र ही शिरडी से प्रस्थान करने का विचार किया और विदा लेने के हेतु वे बाबा के पास आये. बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने और शीघ्रता न करने की राय दी. अन्य भक्तों ने भी उनसे बाबा के आदेश का पालन करने की प्रार्थना की. परंतु वह सबकी उपेक्षा कर तांगे में बैठकर रवाना हो गये. कुछ दूर तक तो घोड़े ठीक–ठीक चलते रहे, लेकिन सावली विहीर नामक गांव पार करने पर एक सायकिल सामने से आई, जिसे देखकर घोड़े भयभीत हो गये और ज्यादा गति से दौड़ने लगे. फलस्वरुप तांगा उलट गया और महाशय नीचे लुढ़क गये, और कुछ दूर तक तांगे के साथ–साथ घिसटते चले गये. लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया. इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि जो बाबा के आदेशों की अवहेलना करते हैं, उन्हें किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार होना ही पड़ता है और जो आज्ञा का पालन करते हैं, वे सकुशल और सुखपूर्वक अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं.

भिक्षावृत्ति की आवश्यकता

कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि जब बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष थे तो फिर उन्होंने आजीवन भिक्षावृत्ति पर ही जीवन निर्वाह क्यों किया. इस प्रश्न को दो दृष्टिकोण समक्ष रख कर हल किया जा सकता है. पहला दृष्टिकोण यह कि भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने का कौन अधिकारी है? शास्त्रानुसार वे व्यक्ति, जिन्होंने तीन मुख्य आसक्तियों कामिनी, कांचन और कीर्ति का त्याग कर आसक्ति –मुक्त होकर संन्यास ग्रहण कर लिया हो वे ही भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी हैं, क्योंकि वे अपने गृह में भोजन तैयार करने का प्रबंध नहीं कर सकते. अतः उन्हें भोजन कराने का भार गृहस्थों पर ही है. श्री साईबाबा न तो गृहस्थ थे और न वानप्रस्थी. वे तो बालब्रम्हचारी थे. उनकी यह दृढ़ भावना थी कि विश्व ही मेरा घर है. वे तो स्वयं ही भगवान वासुदेव, विश्वपालनकर्ता तथा परब्रहमा थे. इसलिए वे भिक्षा–उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे. दूसरा दृष्टिकोण, पंचसूना (पांच पाप और उनका प्रायश्चित) सब को यह ज्ञात है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिये गृहस्थाश्रमियों को पांच प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, कंडणी (पीसना),पेषणी (दलना), उदकुंभी (बर्तन मलना), मार्जनी (मांजना और धोना), चूली (चूल्हा सुलगाना) इन क्रियाओं के परिणामस्वरुप अनेक कीटाणुओं और जीवों का नाश होता है और इस प्रकार गृहस्थाश्रमियों को पाप लगता है. इन पापों के प्रायश्चित स्वरुप शास्त्रों ने पांच प्रकार के योग (यज्ञ) करने की आज्ञा दी है, अर्थात ब्रहमयज्ञ अर्थात वेदाध्ययन – ब्रहम को अर्पण करना या वेद का अध्ययन करना, पितृयज्ञ– पूर्वजों को दान, देवयज्ञ–देवताओं को बलि, भूतयज्ञ– प्राणियों को दान, मनुष्य (अतिथि) यज्ञ – मनुष्यों (अतिथियों) को दान. यदि ये कर्म विधिपूर्वक शास्त्रानुसार किये जायें तो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्मानुभूति की प्राप्त सुलभ हो जाती है. बाबा द्वार–द्वार जाकर गृहस्थाश्रमियों को इस पवित्र कर्तव्य की स्मृति दिलाते रहते थे और वे लोग अत्यन्त भाग्यशाली थे, जिन्हें घर बैठे ही बाबा से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाता था. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

भाजपा के लिए गले की हड्डी बनी जम्मू–कश्मीर सरकार

काफी दिनों से जम्मू कश्मीर के सियासी चुनाव को लेकर खबरें चल रही थीं. इसी बीच 1 मार्च को भाजपा व पीडीपी ने मिलकर जम्मू कश्मीर में बेमेल सरकार बनाई. मगर इस सियासी खेल में इतनी जल्दी अड़चने आने लगेंगी जिसका किसी को भी अंदाज़ा भी नहीं था. पहले मोहम्मद मुफ्ती सईद ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अलगाववादियों और पाकिस्तान के संबंध में विवादास्पद बयान दिया. इसके बाद पीडीपी के विधायकों ने संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु के शव की मांग की. कहीं इसके पीछे पीडीपी की कोई बड़ी रणनीति तो नहीं है? जम्मू–कश्मीर की नवगठित साझा सरकार भाजपा के लिए गले की हड्डी बन गई है. भाजपा को पीडीपी के इस रवैये का पुरजोर विरोध करना होगा, अन्यथा देश की जनता का भाजपा के ऊपर से विश्वास उठ जायेगा. जम्मू–कश्मीर में भाजपा के सहयोग से सत्ता में आई पीडीपी ये भूल रही है कि जिस राज्य में वो शासन कर रही है वह भारत का अभिन्न अंग है इसलिए खुद को पाकिस्तान परस्त दिखाकर उसे कुछ हासिल नहीं होगा.

–तेजस्विनी श्रीवास्तव, कानपुर

आधार को लागू करना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना

पिछले वर्ष दिसंबर के दूसरे सप्ताह का चौथी दुनिया का अंक यूआईडी कार्ड खतरनाक है के शार्षक को पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने यूआईडी को लेकर तीन आदेश दिए थे, जिसकी सरकार ने अनदेखी की है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना जाए तो स्पष्ट है कि इस कार्ड को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है. यह एक स्वैच्छिक योजना है, फिर भी हमारी केंद्र की मोदी सरकार ने इसे हरी झंडी दे रखी है. यह योजना देश के ऊपर यूपीए सरकार द्वारा थोपी गई थी जो शुरू से ही कानून एवं सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारे सवालों के घेरे में रही. यूपीए सरकार के वक्त भाजपा ने खुद इस कार्ड पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि कल तक जो योजना खतरनाक थी वह आज सही हो गई. देश के नागरिकों की प्राइवेसी ऐसी कंपनी के हाथों में है जो जासूसी के लिए पूर्वविदित है. अब मंत्रालयों में आधार कार्ड के जरिये उपस्थिति दर्ज कराने का प्रावधान किया जाने लगा है. देश के आवाम को आधार का सच मालूम होना चाहिए. आखिर इसे किस आधार पर पूरे देश में पुनः मोदी सरकार द्वारा लागू किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का क्या हुआ, यह यक्ष प्रश्न है, जिसका जवाब सरकार को देना ही चाहिए. चौथी दुनिया आधार को लेकर कई बार सवाल उठाता रहा है उन तीन कंपनियों पर अगर गौर किया जाए जिन्हें आधार बनाने की जिम्मेदारी दी गई है उनका रिश्ता किन–किन देशों के साथ है. देश के कानून एवं सुरक्षा के मद्देनज़र मोदी जी को इसे स्पष्ट करना ही चाहिए, चौथी दुनिया की पहल को मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने इस मामले को लेकर पूरे देश को सावधान किया. सत्यमेव जयते.

–अशोक निर्मोही मुन्नाजी, लहरिया सराय, दरभंगा

क्या हमारी सभ्यता हमें यही सिखाती है

दिल्ली में हुए निर्भया हत्याकांड पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद उसके माता–पिता के बारे में सोच कर दिल दहल जाता है. अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना लिए उस पिता ने काफी संघर्ष करके उसका देहरादून के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाया था लेकिन उस पिता को क्या मालूम था जिस बेटी के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे थे उन्हें एक दिन अपनी बेटी को खोना पड़ेगा. अपने सपने को लेकर दिन रात एक कर देना वाली उनकी बेटी डॉक्टर बनने को लेकर काफी सजग थी. लेकिन जब आरोपी मुकेश का बयान को सुनता हूं तो इंसानियत शब्द शर्मशार सा लगता है. आखिर क्यों आज भी लोगों की सोच नारी के प्रति इतनी अलग है. आज के तारीख में युवा लड़के न जाने क्यों राह चलती लड़कियों को छेड़कर अपने को नवाब समझते हैं. इसी तरह के कुछ लोगों की वजह से एक बेगुनाह लड़की की इज्जत तारतार हो गई और न जाने कितनों की हो जाती है. लेकिन उसके देहांत के बाद भी उस लड़की के ऊपर ऊंगली उठाने वालों की कमी नहीं है, लड़कियों को रात में नहीं निकलना चाहिए, लड़कियों को ऐसे कपड़े नही पहनने चाहिए. आखिर हर बार लड़कियों पर ही ऊंगली क्यों उठती है? उन लड़कों के ऊपर उंगलियां क्यों नहीं उठतीं हैं? क्या हमारी सभ्यता हमें यही सिखाती है?

–कार्तिकेय शुक्ला , कानपुर

भूमि अधिग्रहण पर सरकार की राह आसान नहीं

भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में पास हो गया है. बिल को पास कराने के लिए सरकार को नौ संशोधन पेश करने पड़े. लेकिन इससे भी सरकार की राह आसान नहीं होने जा रही है और न ही किसानों की मुश्किलें कम होती नज़र आ रही हैं. अब बिल राज्यसभा में पेश होना है जहां सरकार के पास बहुमत नहीं है. सरकार के पास लोकसभा में तो बहुमत था और उसने विपक्ष के किसी भी बदलाव को शामिल नहीं किया, लिहाज़ा आगे की राह उसके लिए आसान नहीं दिख रही है. यानि कि सरकार का मौजूदा भूमि अधिग्रहण बिल छह महीने के लिए लटक गया है. सरकार के सामने एक और दिक्कत है कि राज्यसभा में यह बिल पहले से ही लंबित है, और लोकसभा से पारित बिल को राज्यसभा में लाने के लिए पहले पुराने बिल को वापिस लेना होगा, जो विपक्ष करने नहीं दे रहा है. विपक्ष एकजुट होकर राज्यसभा में सरकार को मजा चखाने पर उतारू है. सरकार ने विस्थापित परिवारों में से एक को नौकरी देने की बात कहकर मुलायम सिंह को खुश करने की कोशिश की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का प्रावधान है भूमि अधिग्रहण बिल से पहले सरकार भूमि अध्यादेश लाई थी, जिसमें कई बड़े बदलाव किए गए थे. सरकार की दलील थी कि कई बड़े प्रोजेक्ट भूमि अधिग्रहण पर विवाद की वजह से अटके हैं लिहाज़ा उसे अध्यादेश लाना पड़ा. लेकिन जिस तरह विपक्ष और सामाजिक संगठन विरोध कर रहे हैं उससे सरकार के लिए अध्यादेश को कानून का रूप देना आसान नहीं है. वह ऐसा सिर्फ ज्वाइंट सेशन आयोजित करके ही कर सकती है. और उसका यह फैसला जनहित में नहीं है.

–आमिर पुंडीर ,ग्रेटर नोएडा

लघु कथा

एक अधूरा घड़ा

बहुत समय पहले की बात है एक भिश्ती था. उसके पास दो घड़े थे. उन घड़ों को उसने एक लम्बे डंडे के दो किनारों से बांधा हुआ था. एक घड़ा साबुत और सुन्दर था, परन्तु दूसरे घड़े में दरार थी. भिश्ती हर सुबह नदी तट पर जाकर दोनों घड़ों में पानी भरता और फिर शुरू होता उसका लंबा सफर. वह ऊंची पहाड़ी चढ़कर मालिक के घर जब तक पहुंचता, टूटे हुए घड़े से आधा पानी रास्ते में ही बह चुका होता, जबकि साबुत घड़े में पूरा पानी होता. बहुत समय तक ऐसा ही चलता रहा. मालिक के घर तक डेढ़ घड़ा पानी ही पहुंचता. साबुत घड़े को अपने पर बहुत घमंड था. उसकी बनावट बहुत सुन्दर थी और वह काम में भी पूरा आता था. टूटे हुए घड़े को अपनी बेबसी पर दुःख होता. वह उदास और दुखी रहता क्योंकि वह अधूरा था. उसे अपनी कमी का एहसास था. वह जानता था कि जितना काम उसे करना चाहिये वह उससे आधा ही कर पाता है. एक दिन टूटा हुआ घड़ा अपनी नाकामयाबी को और सहन नहीं कर पाया. वह भिश्ती से बोला मुझे अपने पर शर्म आती है. मैं अधूरा हूं. मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं. भिश्ती ने उससे पूछा तुम्हें किस बात की शर्म है. आप इतनी मेहनत से पानी लाते हैं और मैं उसे पूरा नहीं रोक पाता हूं, आधा रास्ते में ही बह जाता है. मेरी कमी के कारण मालिक को आप पूरा पानी नहीं दे पाते हैं, दरार वाला घड़ा बोला.

भिश्ती को टूटे हुए घड़े पर बहुत तरस आया. उसके हृदय में दया और करूणा थी. उसने प्यार से टूटे हुए घड़े से कहा, आज जब हम पानी लेकर वापस आयेंगे तब तुम रास्ते में खुबसूरत फूलों को ध्यान से देखना. चढ़ते सूरज की रोशनी में वो फूल कितने अच्छे लगते हैं और उस दिन टूटे हुए घड़े ने देखा कि सारे रास्ते के किनारे बहुत ही सुन्दर रंगबिरंगे फूल खिले हुए थे. उन लाल, नीले, पीले फूलों को देखकर उसका दुखी मन कुछ समय के लिये अपना दुख भूल गया. परन्तु मालिक के घर पहुंचते ही वह फिर उदास हो गया. उसे बुरा लगा कि फिर इतना पानी टपक गया था. नम्रतापूर्वक टूटे हुए घड़े ने फिर भिश्ती से माफी मांगी. तब वह भिश्ती टूटे हुए घड़े से बोला क्या तुमने ध्यान दिया कि रास्ते में वह सुन्दर फूल केवल तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर ही खिले हुए थे. मैं तुम्हारी इस कमजोरी के बारे में जानता था और मैने इसका फायदा उठाया. मैंने फूलों के बीज केवल तुम्हारी तरफ ही बोये थे और हर सुबह जब हम इस रास्ते से गुजरते, तो तुम इन पौधों को पानी देते थे. पिछले दो सालों से ये फूल मालिक के घर की शोभा बढाते हैं. तुम जैसे भी हो बहुत काम के हो, अगर तुम न होते तो मालिक का घर इन सुन्दर फूलों से सुसज्जित न होता.

ईश्वर ने हम सब में कुछ कमियां दी हैं. हम सब उस टूटे अधूरे घड़े जैसे हैं. पर हम चाहें तो हम इन कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं. हमें कभी भी अपनी कमियों से घबराना नहीं चाहिये. हमें एहसास होना चाहिये कि हममें क्या कमियां हैं और फिर उन कमजोरियों के बावजूद हम अपने चारों तरफ खूबसूरती फैला सकते हैं खुशियां बांट सकते हैं. अपनी कमी में ही अपनी मजबूती ढूंढ सकते हैं. ■

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर–11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन–201301

बॉलीवुड सेल्फी की अंतर्कथा

अनंत विजय

पिछले साल दिसंबर की किसी सर्द शाम को मैं, मेरे मित्र यतींद्र मिश्र और अरुण माहेश्वरी दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के बाहर लॉन में खड़े होकर बातें कर रहे थे. पता नहीं, बात कहां से शुरू हुई और कहां–कहां से होती हुई फिल्मों तक पहुंच गई. बातों–बातों में मैंने अरुण जी से कहा कि एक किताब तैयार करने की सोच रहा हूं, जो फिल्मी सुपरस्टार्स पर होगी, फिल्मी सितारों की ज़िंदगी के इर्द–गिर्द. अरुण जी ने फौरन अपने अंदाज़ में कहा, लाइए न जी, छापते हैं और विश्व पुस्तक मेले में उसे रिलीज भी करते हैं. जब मैं उनसे फिल्म पर किताब लिखने की बात कर रहा था, तो अवचेतन मन में दफ्तर में साथ बैठने वाले मेरे दोस्त इकबाल रिजवी को मज़ाक–मज़ाक में दी गई चुनौती भी थी. इकबाल रिजवी हिंदी फिल्मों के चलते–फिरते कोश हैं. उनके पास फिल्मों, फिल्मी सितारों एवं फिल्मी प्रसंगों से जुड़े विषयों का खजाना है. हम उन्हें लगातार फिल्म पर एक किताब लिखने को उकसाते रहे हैं. वह हमेशा कहते हैं कि लिख रहे हैं, बस पूरी होने वाली है. जैसे अभिनेता अजीत पर उन्होंने एक किताब पूरी की है, लेकिन आख़िरी दौर में न जाने कहां और क्यों रुकी हुई है.

एक दिन बातों–बातों में मैंने इकबाल जी से कहा था कि उनसे पहले फिल्मों पर मेरी किताब आ जाएगी. उन्होंने शुभकामनाएं देकर मेरी चुनौती की हवा निकाल दी. लेकिन, मैंने सोचा कि फिल्म पर एक किताब तो आनी ही चाहिए और इकबाल जी की शुभकामना का सम्मान भी होना चाहिए. मज़ाक में कही उस बात के पूरा होने का वक्त था. दरअसल, फिल्मों पर मेरी जानकारी बहुत कम थी. बिहार के कस्बाई शहर जमालपुर में बचपन गुज़रा. उस वक्त का माहौल यह था कि अच्छे बच्चों को फिल्में नहीं देखनी चाहिए या फिर बड़ों के साथ जाकर देखनी चाहिए. वहां दो सिनेमा हॉल हुआ करते थे, अवंतिका सिनेमा और रेलवे सिनेमा. अवंतिका सिनेमा हमारे स्कूल के पास था. मेरे दोस्त स्कूल से भागकर नून शो देखा करते थे. इच्छा तो मेरी भी खूब होती थी, लेकिन पकड़े जाने के भय से जा नहीं पाता था. स्कूल जाते वक्त ज़रूर अवंतिका सिनेमा के सामने खड़े होकर और उसकी लॉबी में जाकर फिल्मों के पोस्टर देखा करता था. उस वक्त जालीदार शो–केस में फिल्मों के कई सीक्वेंसियल पोस्टर लगे होते थे, जिन्हें देखने के बाद मैं ललचाता था, अंदाज़ा लगाता था कि फिल्म कैसी होगी.

उन्हीं दिनों मेरे एक दोस्त ने अवंतिका सिनेमा हॉल के गेटकीपर से दोस्ती कर ली थी. उसने गेटकीपर से यह डील की थी कि वह नई फिल्मों के गाने दिखा दिया करे, बगैर टिकट लिए. यह सौदा संभवत: चार आने में तय हुआ था. वह हमें गाने का तय वक्त बता देता था और हम स्कूल से पंद्रह–बीस मिनट के लिए किसी बहाने से भागकर वहां पहुंच जाते थे. फिर चवन्नी देने के बाद वह गेटकीपर हमें चोरी–छिपे दरवाजे के पास ही खड़ा कर देता. हम वहीं खड़े होकर गाने देखते और अभिभूत होकर वापस स्कूल लौट जाते. मजे की यह कि वह हमें उधारी पर भी गाने दिखाया करता था यानी अगर पैसे न हों, तो भी दिखा देता और अपनी पॉकेट डायरी में तारीख और वक्त लिख लेता था. यह क्रम सालों तक चला, कम से कम दसवीं की बोर्ड परीक्षा के फाइनल पेपर तक. मेरी स्मृति में जो पहला फिल्मी गाना है, वह है देवानंद की फिल्म काला बाज़ार का, खोया–खोया चांद, खुला आसमान. यह गाना मैंने अवंतिका सिनेमा में चार आने में देखा था. दसवीं तक पर्व–त्योहार या कुछ विशेष मौक़ों पर ही फिल्म देखा करता था.

पहली पूरी फिल्म कौन–सी देखी, कुछ भी याद नहीं. दसवीं की परीक्षा का आख़िरी पर्चा देकर जब घर लौटा, तो रवि भैया आए हुए थे. उन्होंने मुझसे परीक्षा आदि के विषय में बात करने के बाद पूछा कि अवंतिका में कौन–सी फिल्म लगी है. मैंने छूटते ही कहा, हिम्मतवाला. इस फिल्म के लगभग सारे गाने चवन्नी स्कीम से कई बार देख चुका था. फिर भैया ने दस रुपये दिए और कहा, जाओ, फिल्म हिम्मतवाला देखकर आओ. मैं खुश. फौरन अवंतिका सिनेमा पहुंचा. अपना गेटकीपर दोस्त वहां मौजूद था. उसे लगा कि मुझे फिर से गाने देखने हैं, तो उसने कहा कि अभी गाना आने में वक्त है. अभी तो फिल्म शुरू ही होने वाली है. मैंने उसे कहा कि आज मैं पूरी फिल्म देखूंगा, गाने नहीं. उसने मेरी मदद की और मुझे बॉलकनी का टिकट लाकर दिया. फिर मैंने शान से बालकनी में बैठकर हिम्मतवाला देखी, चिनिया बादाम (बिहार में मूंगफली को चिनिया बादाम कहते हैं) भी खाया. हिम्मतवाला देखने के बाद श्रीदेवी का फैन हो गया. यहीं से मेरी फिल्मों से दोस्ती शुरू हो गई. यह दोस्ती परवान चढ़ी, जब मैं भागलपुर के मशहूर टीएनबी कॉलेज पहुंचा. दसवीं तक घर में रहकर पढ़ाई करने के बाद जब अचानक हॉस्टल पहुंचा, तो लगा कि अब तो सारा आकाश हमारा है. किसी का भय नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई बंधन नहीं. अपनी मर्जी के मालिक, अपने फ़ैसले खुद लेने हैं.

हॉस्टल में सात दोस्त इकट्ठे रहने लगे. कॉलेज के अन्य छात्रों ने हमारे इस गैंग को नाम दिया था, सेवन स्टार. हम सबके गले में सफेद सिल्क का मफलर हुआ करता था और सातों एक साथ साइकिल पर चला करते थे. वह टशन था. ग्रुप की पहचान थी सफेद मफलर और साइकिल. हॉस्टल में रहते हुए शुरू हुआ नाइट शो देखने का दौर. दो सिनेमा हॉल के शहर से पांच–छह सिनेमा हॉल वाले शहर में पहुंचा था. फिल्म देखने का ऐसा चस्का लगा कि हमने हॉस्टल के अपने कमरे की खिड़की का एक रॉड निकाल दिया था, ताकि जब नाइट शो देखकर लौटें, तो हॉस्टल में घुसने में दिक्कत न हो. हॉस्टल का मेन गेट तो रात दस बजे बंद हो जाता था. फिर जब हमारे कमरे की वह खिड़की सार्वजनिक रास्ते में तब्दील होने लगी, तो उसे बंद करना पड़ा, क्योंकि शिकायत वॉर्डन से होते हुए प्रिंसिपल तक पहुंचने का अंदेशा था. भागलपुर में रहने के दौरान कितनी फिल्में देखीं, कह नहीं सकता. कई– कई दिन तो लगातार चार शो देखने का रिकॉर्ड सेवन स्टार ग्रुप के नाम बना था. एक सिनेमा हॉल से दूसरे सिनेमा हॉल तक जाकर एक शो से दूसरे शो को पकड़ना एक ऐसा खेल था, जिसके रोमांच में हम सब पागल थे.

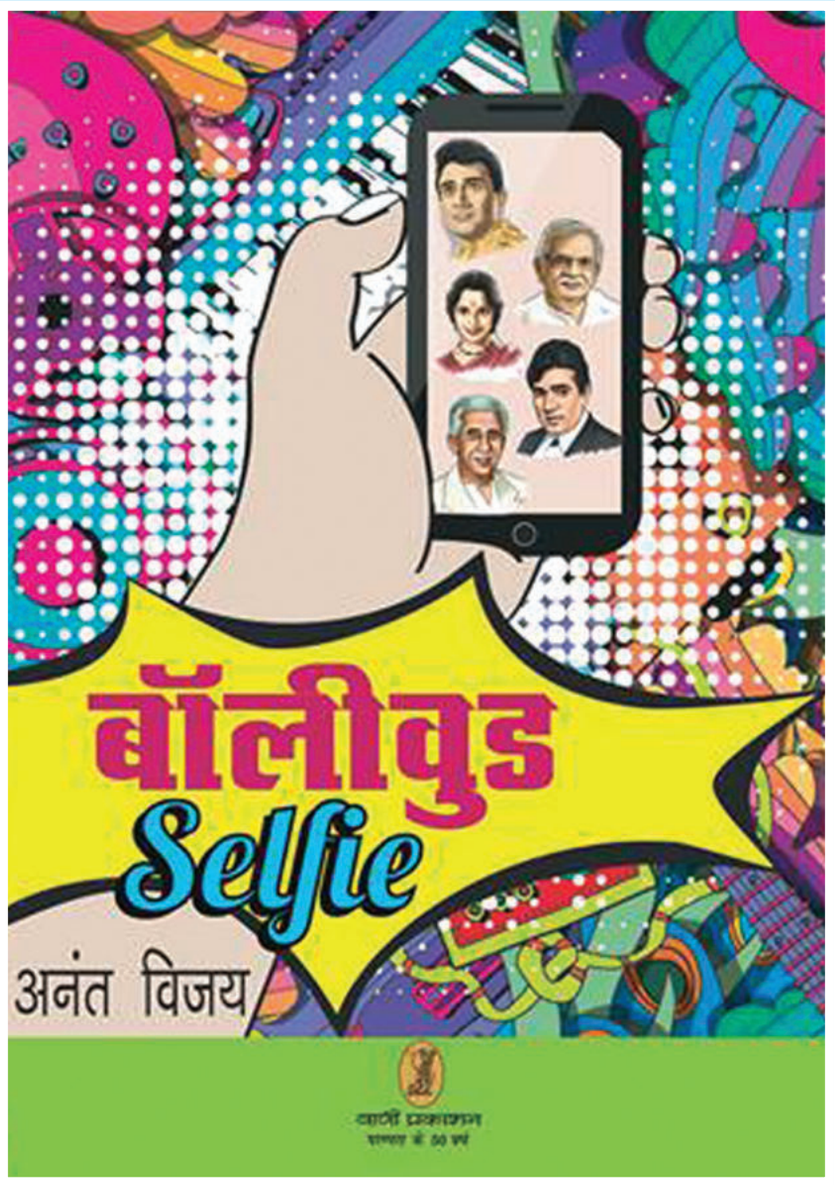

किताब : बॉलीवुड सेल्फी
प्रकाशक : वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
मूल्य : 150 रुपये

उस दौर में अच्छी, बुरी, औसत सभी फिल्में देख डालीं. सुबह तय हो जाता था कि आज चार शो देखने हैं. एक–दो बार टर्मिनल एक्जाम के दौरान भी शर्त लगाकर हम लोग बाहर आ जाते थे कि कौन सबसे पहले सिनेमा हॉल पहुंचता है. इस चक्कर में हमारा नुक़सान भी हुआ था. पर उम्र के उस दौर में नफा–नुक़सान की परवाह कहां हो पाती है! उस वक्त तो लगता है कि जो हम कर रहे हैं, वह सही है. भागलपुर से जब वापस जमालपुर आया, तो फिल्मों का साथ फिर छूटा. कह सकते हैं कि इतनी फिल्में देख डाली थीं कि मन भर गया था. जमालपुर से जब दिल्ली आया, तो मैनेजमेंट की पढ़ाई के दौरान दोस्तों के साथ कुछ फिल्में देख लिया करता था, पर ज़्यादातर मना ही कर देता था. फिल्मों से ऐसा मोहभंग हुआ कि शादी होने के कई सालों बाद हम और वंदना ओमकारा देखने गए थे. संभवत: शादी के सात साल बाद हम दोनों ने साथ जाकर फिल्म देखी थी. शादी के सात साल तक न तो अकेले और न साथ फिल्म देखी. ओमकारा के बाद फिर से फिल्म देखने के सिलसिले ने जोर पकड़ा था. जितनी बेफिक्री भागलपुर के हॉस्टल के दौर में थी, उतनी ही फिक्र पहली नौकरी के बाद खुद को स्थापित करने को लेकर थी. स्वयं के चक्कर में फिल्मों से दूर होता चला गया.

पत्रकारिता में जब आया, तो कई दोस्त फिल्मों और उनके प्रसंगों पर बात करते थे, तो मैं हमेशा खामोश हो जाता था, क्योंकि फिल्में तो देखीं, लेकिन यह कभी ध्यान नहीं दिया कि कौन डायरेक्टर था, किसने संगीत दिया था, कौन गायक था आदि. फिल्मी प्रसंगों पर होने वाली बातें सुनने में मजा बहुत आता था. उन बातों को सुनते हुए यह भी लगता था कि काश! मुझे भी इन प्रसंगों का पता होता. मैं भी उसी तरह से फिल्मों के इतिहास और रोचक प्रसंगों पर बातें कर सकता. इसी चाहत में फिल्मी सितारों से जुड़ी किताबें पढ़ने लगा. आत्मकथा और जीवनी पढ़ना मेरा शुरू से शौक रहा है, लिहाजा मैंने अपनी इस रुचि को फिल्मी हस्तियों की ओर मोड़ दिया. यह वही दौर था, जब मैं नया ज्ञानोदय में नियमित लिखने लगा था. जब फिल्मों से जुड़ी किताबें ही पढ़ने लगा, तो उन्हीं किताबों पर लिखने भी लगा. किसी भी फिल्मी शख्सियत पर लिखा मेरा पहला लेख शौकत कैफी की किताब–यादों की रहगुज़र के हवाले से साहित्यिक पत्रिका तद्भव में छपा था. उसके बाद ज्ञानोदय में कई सितारों पर लिखा. फिल्मों पर लेखन शुरू करने का भी दिलचस्प किस्सा है.

फिल्मी हस्तियों से जुड़ी किताबें पढ़ने के पीछे सबसे बड़ा लोभ यह था कि मुझे बॉलीवुड के दिलचस्प किस्से जानने में मदद मिले. ख्वाहिश यह भी होती थी कि फिल्मों पर होने वाली बहस में मैं भी हिस्सा ले सकूं. इकबाल रिजवी ने फिल्मी सितारों से जुड़ी मुझे कई दुर्लभ सामग्री दी, जिनमें उनके दिलचस्प प्रसंग हैं. उसके अलावा मैंने कई किताबें पढ़ डालीं, जिससे उन प्रसंगों को जानने–समझने का मौक़ा मिला. यह अलहदा बात है कि इन फिल्मी सितारों से जुड़े एक ही प्रसंग को अलग–अलग लोगों ने अलग–अलग ढंग से कहा है. हिंदी फिल्मों की दुनिया से जुड़े अल्प अध्ययन के आधार पर मुझे लगता है कि मीना कुमारी से जुड़े किस्से काफी दिलचस्प हैं और उनके बारे में किस्से गढ़े भी गए हैं. एक ही प्रसंग पर अलग–अलग जगहों पर मीना कुमारी के बारे में अलग–अलग बातें पढ़ने को मिलती हैं. मीना कुमारी के फिल्म के सेट पर मशहूर झगड़े को भी अलग–अलग लोगों ने अलग–अलग तरीके से लिखा है. यह समझा जा सकता है कि सुपर स्टारों से जुड़ी कहानियों में लोग मिर्च–मसाला लगा ही देते हैं. हर लेखक अपने हिसाब से उसे रोचक बनाने के चक्कर में एक अलग मसाला इस्तेमाल करता है, किस्से गढ़ता है. मीना कुमारी का व्यक्तित्व ऐसा है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा किस्से बॉलीवुड में मौजूद हैं.

इन सितारों पर लिखते हुए मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि किसी जमाने में नायकों के बराबर रुतबा रखने वाले गीतकार और संगीतकार भी होते थे. साहिर लुधियानवी ने इस बात तो इंश्योर कराया था कि फिल्मों के पोस्टर पर शायर का नाम जाए. पचास के दशक में नौशाद एक फिल्म के लिए एक लाख दस हज़ार रुपये लिया करते थे, जबकि उन दिनों अच्छे से अच्छे डायरेक्टर को भी तीस–चालीस हज़ार रुपये ही मिलते थे. नौशाद और साहिर ने नायकों से बड़ा कद हासिल किया था. मेरी इस किताब में बॉलीवुड से जुड़ी ग्यारह हस्तियों के बारे में उनकी या उन पर लिखी गई किताबों के बहाने से दिलचस्प प्रसंग लिखे गए हैं. मैंने अपनी इस किताब में फिल्म पाकीजा को भी शामिल किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि मीना कुमारी की पर्सनैलिटी पाकीजा के बिना पूरी नहीं होती है. पाकीजा का निर्माण और उससे जुड़े प्रसंग मीना कुमारी की ज़िंदगी को पूरी तरह से पाठकों के सामने खोलकर रख देते हैं. उनके कमाल अमरोही से संबंधों या उस दौर में उनके अन्य प्रेम संबंधों का गहरा असर पाकीजा पर पड़ा. पाकीजा ने अगर मीना कुमारी को अमर किया, तो उन्हें कई गम भी दिए. मुफलिसी की शुरुआत का दर्द भी दिया. इन्हीं विषयों का कोलाज है बॉलीवुड सेल्फी. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

श्रद्धांजलि

जीवन भर लिखते रहे राष्ट्रबंधु

महेंद्र अवधेश

साहित्य की प्रत्येक विधा का अपना मिजाज है, अपना एक अलग रंग है. यदि कोई विधा कठिन नहीं है, तो इसके साथ एक सच यह भी जुड़ा है कि वह इतनी सरल भी नहीं है. बच्चों के लिए साहित्य रचना स्वयं में एक चुनौती भरा कार्य है. और, इस चुनौती को जीवनपर्यंत बखूबी निभाते रहे डॉ. राष्ट्रबंधु. बीते दो मार्च को उन्होंने उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली. वह 82 वर्ष के थे. 1950 में अपनी पुस्तक–बाल भूषण से चर्चा में आए डॉ. राष्ट्रबंधु ने फिर कभी मुड़कर नहीं देखा. दो अक्टूबर, 1933 को सहारनपुर में पिता डॉ. देवी प्रसाद एवं माता भगवती देवी के घर में जन्मे राष्ट्रबंधु का असली नाम डॉ. श्रीकृष्ण चंद्र तिवारी था. अंग्रेजी एवं हिंदी में परास्नातक डिग्री हासिल करने वाले राष्ट्रबंधु ने हिंदी में बाल साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन विषय पर पीएचडी की. उन्होंने संस्कृत विशारद एवं साहित्य रत्न जैसी उपाधियां भी हासिल कीं. बाल भूषण के अलावा उन्होंने नाचो–गाओ, कंतक थैयां घुनूं मनइयां, लाक्षागृह, टेसूजी की भारत यात्रा, अब्बा की खांसी, मकरंदी, विक्रमादित्य का सिंहासन, बावन गांव इनाम में, भारतीय प्रतिभाएं, चप्पा–चप्पा मध्य प्रदेश जैसी 60 से ज़्यादा कृतियां रचीं. दुर्गा सप्तशती का हिंदी में अनुवाद के लिए राष्ट्रबंधु ने जबरदस्त प्रशंसा हासिल की.

साहित्य में योगदान के लिए उन्हें सूर पुरस्कार, बाल साहित्य भारती (उत्तर प्रदेश संस्थान) , देवपुत्र सम्मान एवं हरिकृष्ण तैलंग

1950 में अपनी पुस्तक–बाल भूषण से चर्चा में आए डॉ. राष्ट्रबंधु ने फिर कभी मुड़कर नहीं देखा. दो अक्टूबर, 1933 को सहारनपुर में पिता डॉ. देवी प्रसाद एवं माता भगवती देवी के घर में जन्मे राष्ट्रबंधु का असली नाम डॉ. श्रीकृष्ण चंद्र तिवारी था. अंग्रेजी एवं हिंदी में परास्नातक डिग्री हासिल करने वाले राष्ट्रबंधु ने हिंदी में बाल साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन विषय पर पीएचडी की. उन्होंने संस्कृत विशारद एवं साहित्य रत्न जैसी उपाधियां भी हासिल कीं.

अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. राष्ट्रबंधु ने आकाशवाणी, दूरदर्शन, एनसीआरटी, चिल्ड्रेंस बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट, प्रकाशन विभाग (भारत सरकार) के अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. वह भारतीय बाल कल्याण संस्थान कानपुर के संस्थापक–संरक्षक और बाल साहित्य समीक्षा मासिक के संपादक थे. लेखन के प्रति उनका रुझान बचपन से ही था. जीवकोपार्जन के लिए उन्होंने कई काम किए, मसलन पोस्टमैन की नौकरी की, मध्य प्रदेश में अध्यापन किया. 1980 में कानपुर में भारतीय बाल कल्याण संस्थान की स्थापना करने के बाद रामकृष्ण नगर स्थित अपने आवास पर उन्होंने प्रिंटिंग का काम शुरू किया, लेकिन लेखक मन बेचैन था, सो सारे काम छोड़कर वह साहित्य साधना में जी–जान से जुट गए. बताते हैं कि राष्ट्रबंधु की उपाधि उन्हें 1960 में कानपुर से प्रकाशित होने वाले हिंदी दैनिक विश्वमित्र के एक पत्रकार ने यह कहते हुए दी कि तुम तो राष्ट्रवादी हो, तुम्हारे लिए जाति का कोई मतलब नहीं है. तो आज से तुम्हारा नाम राष्ट्रबंधु है. तबसे लोग उन्हें डॉ. राष्ट्रबंधु कहने और इसी नाम से जानने लगे.

विधाता के विधान के आगे भला किसकी चली है. इस नश्वर में विद्यमान हर जड़–चेतन की विदाई निश्चित है. तो राष्ट्रबंधु इसके अपवाद कैसे हो सकते थे! लेकिन, उनकी कमी साहित्य जगत हमेशा–हमेशा महसूस करेगा और उनकी रचनाएं बच्चों समेत सभी का मार्गदर्शन करती रहेंगी. ■

mahendra.awdhesh@gmail.com

जीएसएक्स सीरीज के फ्रंट डिजाइन के अलावा नई बाइक में वे सारे फीचर्स मौजूद हैं, जो पिछले जिक्सर मॉडल में दिए गए थे. कंपनी ने इस बाइक में कई स्पेशल फीचर्स जैसे स्पॉर्टी डुअल मफ्लर और ट्रेंडी स्मार्टफोन जैसे डिजिटल स्पीडोमीटर का इस्तेमाल किया है. कंपनी ने इस बाइक में एंडवास सिंगल सिलेडर इंजन का इस्तेमाल किया है. जिसमें कंपनी ने SEP (सुजुकी ईको परफॉर्मेंस) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है.

NOKIA

नोकिया 1100 का नया अवतार

भले ही अपने नोकिया के सेलफोन्स का इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन आपने नोकिया 1100 का नाम जरूर सुना होगा. ग्रीन लाइट डिस्प्ले वाले नोकिया 1100 को कंपनी ने साल 2003 में लॉन्च किया था. इस फोन को भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया गया था. इस फोन में टॉर्च भी थी जिसका जादू भारतीय उपभोक्ताओं के सिर चढ़कर बोला था. उस फोन का बैटरी बैकअप आज भी लोगों के जहन में है. स्मार्टफोन के इस युग में नोकिया कहीं पीछे छूट गया, लेकिन एक बार फिर नोकिया 1100 स्मार्टफोन को टक्कर देने आ रहा है. नोकिया 1100 को लेकर चर्चायें काफी तेज हैं, इन चर्चाओं की मानें तो नोकिया 1100 एंड्रायड के लेटेस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम 5.0 लॉलीपॉप के साथ आने वाला है. नोकिया का यह लोकप्रिय फोन एंड्रायड 5.0 ओएस और 1.3 गीगाहर्टज के कॉर्डकोर मीडियाटेक प्रोसेसर, 512 एमबी रैम और 1280 गुणा 720 रेजल्यूशन से लैस होगा. रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुए करार की वजह से कंपनी 2016 की चौथी तिमाही के बाद अपना यह फोन लॉन्च कर सकती है. इस फोन के स्क्रीन साइज, कैमरा व अन्य फीचर्स के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है. लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस फोन में वाई-फाई, ब्लूटूथ, जीपीएस और एफएम जैसे फीचर्स मौजूद होंगे. 2003 में लॉन्च हुए इस फोन के दुनियाभर में 25 करोड़ से ज्यादा यूजर्स थे. दुनिया का सबसे लोकप्रिय और बेस्ट सेलर नोकिया 1100 एक बार फिर स्मार्टफोन का खेल बदल सकता है. ■

भारतीय रेल की शिकायत दर्ज करने वाला ऐप्प

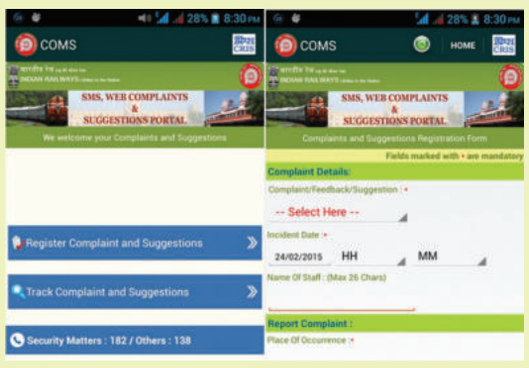

का उंटर पर टिकट मिलने में दिक्कत हुई, टीटीई ने चेकिंग के दौरान दुर्व्यवहार किया. एसी कोचों के बेड रोल गंदे हैं. ट्रेनों के संबंध में स्टेशन पर सही सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं. रेलवे में पार्सल, लगेज, खानपान सेवा, सफाई, पानी की अनुपलब्धता, टिकट वापसी में भ्रष्टाचार या किसी भी तरह की गड़बड़ी हो तो उसकी शिकायत के लिए यात्रियों को अब अफसरों या कर्मचारियों के सामने शिकायत पुस्तिका के लिए गड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा. अब आप घर बैठे रेलवे से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके साथ शिकायत पर की गई कार्रवाई की स्थिति की जानकारी भी आप अपने फोन पर भी ले सकते हैं. साल 2015–16 के रेल बजट में रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने इस ऐप्प को लॉन्च करने की घोषणा की थी. घोषणा के दो दिन बाद यानि 1 मार्च 2015 को रेलवे ने नया एप्लीकेशन Complaint Management System (COMS) लॉन्च कर दिया है. एस ऐप्प को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. अब ज्यादातर युवक–युवतियों के हाथ में स्मार्ट फोन है. ऐसे में ऐसी प्रणाली की जरूरत थी जिससे लोग आसानी से शिकायत दर्ज करा सकें. रेल मंत्रालय भी चाहता है कि शिकायत की प्रक्रिया आसान और ज्यादातर लोगों की पहुंच में होने पर कर्मचारी और अफसर जिम्मेदारी समझेंगे. साथ ही यह डर भी बना रहेगा कि गड़बड़ी होने पर कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है. इसमें शिकायतकर्ता को मोबाइल नंबर, ई–मेल आईडी भी देना होगा. रेलवे के दोनों नए नंबर 182 और 138 को भी इस ऐप्प के जरिए जोड़ा गया है, खबर लिखे जाने तक इस ऐप्प को 10 हजार से ज्यादा उपभोक्ता डाउनलोड कर चुके हैं. इसके अलावा यूजस www.indianrailways.gov.in पर भी अपनी शिकायत और सुझाव दर्ज करा सकते हैं. यात्री 9717630982 नंबर पर मैसेज के जरिए भी शिकायत एसएमएस कर सकते हैं. ■

सुजुकी का आकर्षक मॉडल जिक्सर एसएलके

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड अपनी दमदार 155 सीसी बाइक जिक्सर का फुल फेयर्ड वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी में है. कंपनी ने बाइक की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है. बाइक का नाम जिक्सर एसएलके हो सकता है. कंपनी इस बाइक को इस साल की पहली तिमाही में लॉन्च कर सकती है, इसकी कीमत तकरीबन 80,000 रुपये हो सकती है. जीएसएक्स सीरीज के फ्रंट डिजाइन के अलावा नई बाइक में वे सारे फीचर्स मौजूद हैं जो पिछले जिक्सर मॉडल में दिए गए थे. कंपनी ने इस बाइक में कई स्पेशल फीचर्स जैसे स्पॉर्टी डुअल मफ्लर और ट्रेंडी स्मार्टफोन जैसे डिजिटल स्पीडोमीटर का इस्तेमाल किया है. कंपनी ने इस बाइक में एंडवास सिंगल सिलेडर इंजन का इस्तेमाल किया है. जिसमें कंपनी ने SEP (सुजुकी ईको परफॉर्मेंस) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. ये फ्यूज इफिशियंसी और परफॉर्मेंस बढ़ाने का काम करती है. इसमें 155 सीसी, 4 स्ट्रोक वाला एयर कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया गया है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

एप्पल की स्मार्टवॉच

एप्पल ने अपनी पहली स्मार्टवॉच से पर्दा उठा दिया है, लेकिन भारत में अभी इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा. 10 अप्रैल को इसे अमेरिका सहित चीन, जापान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में प्रदर्शित किया जाएगा. इन देशों में इसकी बिक्री 24 अप्रैल से शुरू हो जाएगी. हालांकि कंपनी ने स्मार्टवॉच का प्रीव्यू फिलहाल भारत में नहीं करने का फैसला किया है. लेकिन माना जा रहा है कि भारत में यह वॉच जून तक आ सकती है. एप्पल ने स्मार्टवॉच के अलावा अपनी मैक बुक रेंज का नया वेरिएंट और स्वास्थ्य से जुड़ी सिसर्च किट भी लॉन्च की है. कंपनी ने इसे एप्पल वॉच स्पोर्ट, एप्पल वॉच और एप्पल वॉच एडिशन नाम से तीन

वेरिएंट में लॉन्च किया है. इसकी शुरुआती कीमत 349 डॉलर (21,800 रुपये) और 17 हज़ार डॉलर 10.66 लाख रुपये है. एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा कि यह स्मार्टवॉच तकनीक के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करेगी. हमारे ग्राहक इसे ज़रूर पसंद करेंगे. यह एक नई शुरुआत है. हम चाहते हैं कि लोग जल्द से जल्द इसे अपनाएं और इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय बाज़ार के हिसाब से यह घड़ी बहुत ही महंगी है. भारतीय बाज़ार स्मार्टफोन की नज़र से तो काफ़ी बड़ा है लेकिन स्मार्टवॉच के नज़रिए से यह बहुत ही छोटा है. ऐसे में कंपनी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी. इसलिए फिलहाल इसे भारत में लॉन्च नहीं किया गया है.■

व्हाट्सऐप्प कॉलिंग फीचर के नाम पर धोखा

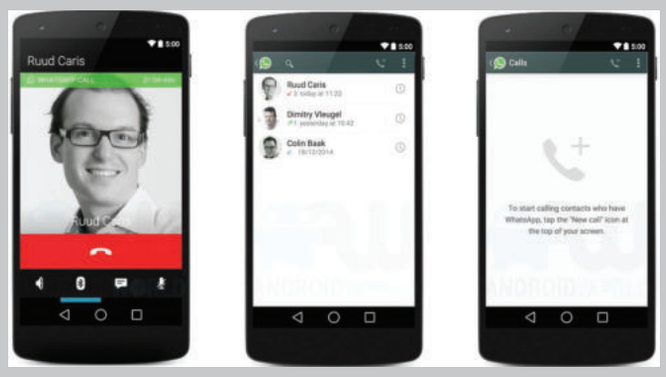

एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर यूजर ऐसे किसी लिंक पर क्लिक करता है तो यह लिंक व्हाट्सऐप्प के नाम पर दूसरी किसी साइट पर लेकर जाती है. यहां यूजर से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है. इस सॉफ्टवेयर में ही मालवेयर है. यह मालवेयर यूजर्स के डिवाइस में आ जाता है. इस मालवेयर से यूजर्स की पर्सनल जानकारी हैक हो सकती है.

व्हाट्सऐप्प कॉलिंग फीचर का आपको भी बेसब्री से इंतजार होगा. चुनिंदा एंड्रॉयड यूजर्स को व्हाट्सऐप्प वॉयस कॉलिंग फीचर मिलने के बाद से सभी यूजर्स व्हाट्सऐप्प वॉयस कॉलिंग का लिंक तलाशने में लगे हैं. साइबर स्कैमर्स ने इसका फायदा उठने के लिए व्हाट्सऐप्प वॉयस कॉलिंग फीचर के नाम पर यूजर्स को मालवेयर (वायरस) भेजना शुरू कर दिया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर यूजर ऐसी किसी लिंक पर क्लिक करता है तो यह लिंक व्हाट्स ऐप्प के नाम पर दूसरी किसी साइट पर लेकर जाती है. यहां यूजर से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है. इस सॉफ्टवेयर में ही मालवेयर है. यह मालवेयर यूजर की डिवाइस में आ जाता है. इस मालवेयर से यूजर की पर्सनल जानकारी हैक हो सकती है. फिलहाल व्हाट्स ऐप्प ने अब तक आधिकारिक तौर पर अपने कॉलिंग फीचर घोषणा नहीं की है. इसलिए सावधान रहें. ■

निसान की अंधेरे में चमकने वाली कार

आज बाजार में अंधेरे में चमकने वाले कार कवर पहले से मौजूद हैं, लेकिन निसान लीफ पर इस्तेमाल किया गया यह अल्ट्रावॉयलेट–एनर्जी पेंट कई मायनों में अलग है.

कार इनोवेशन के लिए जानी जाने वाली कार कंपनी निसान दुनिया की पहली ऐसी कार कंपनी बन चुकी है जिसने अपनी कार में ग्लो–इन–द–डार्क पेंट का इस्तेमाल किया है. कंपनी ने अपनी निसान लीफ इलेक्ट्रॉनिक कार को एक यूनिक अल्ट्रावॉयलेट–अब्जॉर्बिंग पेंट तकनीक से पेंट किया है. जिससे यह कार अंधेरे में भी चमकती हुई नजर आती है. कंपनी ने इस कार को हैमिश स्कॉट के साथ मिलकर डिजाइन किया है. हैमिश स्कॉट स्टारपथ के लिए जाने जाते हैं, इसमें सड़क और फुटपाथ पर ग्लो–इन–डार्क कोटिंग का इस्तेमाल किया गया है. हालांकि आज बाजार में अंधेरे में चमकने वाले कार कवर पहले से मौजूद हैं, लेकिन निसान लीफ पर इस्तेमाल किया गया यह अल्ट्रावॉयलेट–एनर्जी पेंट कई मायनों में अलग है. दरअसल स्प्रे–अप्लाइड कोटिंग के जरिए यह पेंट अल्ट्रावॉयलेट किरणों को सूर्य से दिन भर इकट्ठा करता है. इसके बाद अंधेरे में यह पेंट लगातार 8 से 10 घंटे तक चमकता रहता है. कंपनी के अधिकारी पॉल ओ पील के मुताबिक यह अल्ट्रावॉयलेट पेंट पूरी तरह से ऑर्गेनिक मैटीरियल से तैयार किया गया है. और इसकी लाइफ 25 साल है. ■

क्रिकेट विश्वकप 2015

विश्वकप के बाद संन्यास ले सकते हैं धोनी!

हम किसी भी कीमत पर वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं. चार साल पहले टीम ने सचिन तेंदुलकर के लिए विश्वकप जीता था.

विश्वकप क्रिकेट के बाद टीम इंडिया के कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी के संन्यास लेने की संभावनाएं हैं. धोनी टेस्ट को पहले ही अलविदा कह चुके हैं और अब उनके एकदिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की अटकलें लगने लगी हैं. धोनी के संन्यास की अटकलें लगनी तब शुरू हुईं जब टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया कि हम सभी मैचों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, हम अपना विजय अभियान जारी रखना चाहते हैं, हम किसी भी कीमत पर वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं. चार साल पहले टीम ने सचिन तेंदुलकर के लिए विश्वकप जीता था. इस बार हमें नहीं पता कि अगले विश्वकप तक कौन से खिलाड़ी खेलते रहेंगे, इसलिए हम इस बार उनके लिए विश्वकप जीतना चाहते हैं. इसके तुरंत बाद शमी ने कहा, धोनी शानदार कप्तान हैं. धोनी ने बतौर कप्तान टीम इंडिया को कई जीत दिलाईं और कई रिकॉर्ड्स भी बनाए. धोनी दुनिया के एकमात्र कप्तान हैं जिसने दुनिया के सभी बड़े आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं.■

संगकारा ने इतिहास रचा

विश्वकप में श्रीलंका और स्कॉटलैंड के बीच खेले गए मुकाबले में श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज कुमार संगकारा ने शतक जड़कर इतिहास रच दिया. संगकारा वन-डे क्रिकेट इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज हो गए हैं जिसने लगातार चार मैचों में शतक जड़ा है. इसके अलावा संगकारा ने एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. एक ही विश्वकप में लगातार चार शतक जमाने वाले संगकारा पहले बल्लेबाज बन गए हैं. संगकारा ने मैच में 95 गेंदों में 124 रनों की पारी खेली. उनकी शतकीय पारी में चार छक्के और 13 चौके शामिल रहे. संगकारा ने अपना

संगकारा वनडे क्रिकेट इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज हो गए हैं जिसने लगातार चार मैचों में शतक जड़ा है. इसके अलावा संगकारा ने एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.

शतक 86 गेंदो में पूरा किया. वन-डे में ये संगकारा का 25 वां शतक था. विश्वकप में इससे पहले संगकारा बांग्लादेश के ख़िलाफ 105 रन, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 117 और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 104 रनों की पारी खेल चुके हैं. वन-डे क्रिकेट में लगातार तीन सेंचुरी अब तक छह बल्लेबाज बना चुके हैं लेकिन इनमें से कोई भी लगातार चौथा सैकड़ा नहीं जड़ सका. इस सूची में दक्षिण अफ्रीकी के तीन बल्लेबाजों के अलावा दो पाकिस्तानी और न्यूजीलैंड का एक बल्लेबाज शामिल है. पाकिस्तानी बल्लेबाज जहीर अब्बास ने सबसे पहले यह कारनामा किया था. उन्होंने साल 1982-83 में भारत के खिलाफ लगातार तीन शतक जड़े थे. इसके अलावा सईद अनवर (पाकिस्तान), हर्शल गिब्स (द. अफ्रीका), एबी डिविलियर्स (द. अफ्रीका), क्विंटन डि कॉक (द. अफ्रीका), रॉस टेलर (न्यूजीलैंड) यह कारनाम कर चुके हैं. वर्ल्ड कप में तीन सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में मार्क वॉ, मैथ्यू हेडन और सौरव गांगुली शामिल हैं. इस सेंचुरी के साथ वर्ल्ड कप में संगकारा की 5 सेंचुरी हो गई हैं. वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है उन्होंने 6 वर्ल्ड कप में 6 शतक जड़े थे.■

लंबी अवधि तक कप्तानी नहीं मिलना बहुत बड़ी निराशा: सचिन

टीम के खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें 1997 में कप्तानी से हटा दिया गया. इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में सचिन ने कहा कि मेरे लिये क्रिकेट व्यक्तिगत नहीं बल्कि टीम गेम है. ऐसा समय आता है, जब कप्तान अपनी भूमिका निभाता है. वह मैदान पर महत्वपूर्ण फैसले करता है, लेकिन आखिर में बल्लेबाजों को ही रन बनाने होते हैं और गेंदबाजों को ही सही क्षेत्र में गेंद करनी पड़ती है.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने खुलासा किया है कि भारतीय क्रिकेट कप्तान के रूप में लंबा कार्यकाल नहीं मिलना उनके लिये बहुत बड़ी निराशा थी. इससे उबरना उनके लिये बहुत मुश्किल रहा. तेंदुलकर को अपने 24 साल के चमकदार करियर में दो बार भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गयी लेकिन वह इसमें खास सफल नहीं रहे. वह पहली बार 1996 में कप्तान बने लेकिन टीम के खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें 1997 में कप्तानी से हटा दिया गया. इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में सचिन ने कहा कि मेरे लिये क्रिकेट व्यक्तिगत नहीं बल्कि टीम गेम है. ऐसा समय आता है, जब कप्तान अपनी भूमिका निभाता है. वह मैदान पर महत्वपूर्ण फैसले करता है, लेकिन आखिर में बल्लेबाजों को ही रन बनाने होते हैं और गेंदबाजों को ही सही क्षेत्र में गेंद करनी होती है. उन्होंने कहा कि मुझे कप्तानी के पहले कार्यकाल में 12-13 महीने बाद ही पद से हटा दिया गया. यह निराशाजनक था क्योंकि आपको यह सोचकर कप्तान बनाया गया था कि आप टीम को आगे बढ़ाएंगे और यदि आपका कार्यकाल लंबा नहीं रहता है तो सफलता की दर शून्य हो जाती है. यदि आप चार मैच खेलते हैं और उनमें से दो में जीत दर्ज करते हैं तो आपकी सफलता की दर 50 प्रतिशत ही रहती है. उन्होंने कहा कि मेरी कप्तानी के दौरान हमने जो दौरे किये उनमें भी ऐसा हुआ. हमने बहुत अधिक रन नहीं बनाये और हम 20 विकेट भी नहीं ले पाये.■

कर्नाटक ने जीती रणजी ट्रॉफी

कर्नाटक की जीत के नायक 23 वर्षीय करुण रहे, उन्हें प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनके पहले तिहरे शतक के लिये मैन ऑफ द मैच चुना गया.

गत विजेता कर्नाटक ने तमिलनाडु को एक पारी और 217 रनों से हराकर आठवीं बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया है. विनय कुमार की अगुवाई वाली कर्नाटक ने पांच दिवसीय फाइनल में पहले दिन से ही दबदबा बनाये रखा. उसने पहली पारी में तमिलनाडु को 134 रन पर आउट कर दिया. जवाब में कर्नाटक ने करुण नायर (338) के तिहरे शतक और के एल राहुल (188) और विनय कुमार (105) की शतकीय पारियों की मदद से 762 रन बनाये. जीत के लिये 628 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए तमिलनाडु की टीम 107.5 ओवर में 411 रन पर ढेर हो गई. तमिलनाडु के लिये विजय शंकर (103) और दिनेश कार्तिक(120) ने शतक जमाये लेकिन वे हार को नहीं टाल सके. कर्नाटक के लेग स्पिनर श्रेयस गोपाल ने 126 रन देकर चार विकेट लिये. वहीं कप्तान विनय कुमार और श्रीनाथ अरविंद ने दो-दो विकेट हासिल किए. कर्नाटक की जीत के नायक 23 वर्षीय करुण रहे, उन्हें प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनके पहले तिहरे शतक के लिये मैन ऑफ द मैच चुना गया.■

डियागो फोरलान का संन्यास

उरुग्वे की तरफ से सर्वाधिक मैच खेलने वाले डियागो फोरलान ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है. 35 वर्षीय इस खिलाड़ी ने उरुग्वे की ओर से 112 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और 36 गोल किए. उन्होंने तीन विश्वकप में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया. साथ ही साल 2011 में उरुग्वे को कोपा अमेरिका ट्रॉफी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए विश्वकप में उन्होंने 5 गोल किए थे. उन्हें विश्वकप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के गोल्डन बॉल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. संन्यास का ऐलान करते हुए फोरलान ने कहा कि यह बहुत ही मुश्किल फैसला था, लेकिन मुझे लगता है कि यह सही समय है. हर चीज की शुरूआत और अंत होता है. मुझे लगता है कि यह नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए जगह छोड़ने का वक्त है. यह राष्ट्रीय टीम के लिए नई दिशा में आगे बढ़ने का समय है.■

मेसी का नया रिकॉर्ड

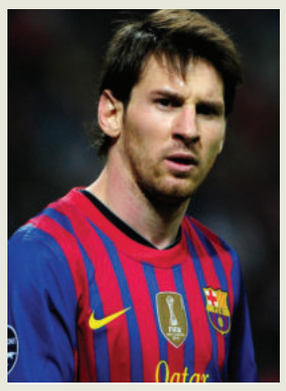

लॉयोनेल मेसी ने स्पेनिश लीग में सर्वाधिक हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.मेसी ने एथलेटिक बिल्बाओ के खिलाड़ी तेल्मे जारा के 31 हैट्रिक के रिकॉर्ड को तोडा. अब उनके नाम स्पेनिश लीग में 32 हैट्रिक हो गई हैं. यह रिकॉर्ड उन्होंने फुटबॉल क्लब रायो बालेकानो के खिलाफ बनाया. बार्सिलोना ने इस मुकाबले में 6-1 से जीत हासिल की. मेसी ने हाफ टाइम के बाद अपनी टीम के लिए 3 गोल किए. लुई सुआरेज ने इस मुकाबले में बार्सिलोना की ओर से दो गोल किए. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सायना विश्व रैंकिंग में दूसरे नंबर पर

सायना ने कहा कि मैं पूरी मेहनत करके नंबर एक बनने की कोशिश करूंगी. चीन की लि शूरूइ विश्व रैंकिंग में नंबर एक पर बनी हुई हैं ,जबकि उनके बाद साइना दूसरे और चीन की ही शिशियान वांग तीसरे स्थान पर हैं.

आॅल इंग्लैंड चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की स्टार शटलर सायना नेहवाल विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं. सायना करियर में दूसरी बार विश्व रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंची हैं, साइना ने इस खास मौके पर कहा कि फिर से विश्व रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त करके वह बहुत खुश हैं. मैं पूरी मेहनत करके नंबर एक बनने की कोशिश करूंगी. चीन की लि शूरूइ विश्व रैंकिंग में नंबर एक पर बनी हुई हैं, जबकि उनके बाद साइना दूसरे और चीन की ही शिशियान वांग तीसरे स्थान पर हैं. इससे पहले जुलाई 2010 में सायना विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंची थीं. ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचकर सायना की रैंकिंग में सुधार हुआ है. युवा पीवी सिंधू नौवे नंबर पर बरकरार हैं जो चोट के कारण ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग नहीं ले सकीं थीं.■

जब सलमान-रितिक शर्ट उतार सकते हैं तो हम क्यों नहीं: सोफिया

हाल ही में हॉट फोटोशूट कर सनसनी फैलाने वाली एक्ट्रेस सोफिया हयात एक बार फिर सुर्खियों में हैं. टीवी शो बिग बॉस से सुर्खियों में आईं ब्रिटिश अभिनेत्री सोफिया हयात ने बेबाक बयान देकर सनसनी मचा दी है. सोफिया ने अपने बयान में कहा है कि जब हिन्दी फिल्मों के हीरो सलमान खान और रितिक रोशन अपने जिस्म का प्रदर्शन कर सकते हैं, तो हीरोइन भी क्यों न करें? फिल्म प्रमोशन के लिए बिकनी का सहारा लेने के सवाल पर सोफिया ने कहा, इस साल मैंने सबसे ज्यादा वर्कआउट किया है और पूरी लाइफ में मैं इतनी फिट कभी नहीं रही हूं. मैं अपने लुक्स को लेकर काफी खुश हूं. सोफिया ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि लड़कियों को खुद को ढंक कर रखना चाहिए, आदमी और औरत एक ही हैं, हमारी आत्मा एक है, एनर्जी एक है, सिर्फ जिस्म अलग-अलग है. कहा जा रहा है कि सोफिया का यह बोल्ड बयान पुरुषवादी मानसिकता वाली फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों को चुभ सकता है. सोफिया जल्द ही चंद्रकांत सिंह निर्देशित फिल्म सिक्स एक्स में नजर आएंगी. ■

इस साल मैंने सबसे ज्यादा वर्कआउट किया है और पूरी लाइफ में मैं इतनी फिट कभी नहीं रही हूं. मैं अपने लुक्स को लेकर काफी खुश हूं. सोफिया ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि लड़कियों को खुद को ढंक कर रखना चाहिए.

अभिनय में हिट, पढ़ाई में सुपरहिट

राजलक्ष्मी मल्ल

बॉलीवुड में अपनी अदाकारी और खूबसूरती के बल पर सफलता के शिखर पर पहुंचने वाली कई अभिनेत्रियां हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अभिनय और पढ़ाई दोनों को महत्व दिया. कई अभिनेत्रियों ने पढ़ाई के क्षेत्र में भी सफलता के नए झंडे गाड़े. बॉलीवुड की फैशन अइकन मानी जाने वाली और अपने जुनून के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री सोनम कपूर को इस बात का मलाल है कि वह अभी तक अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाईं हैं. इसलिए सोनम ने ग्रेजुएशन करने की ठानी है. आईए बॉलीवुड की कुछ टॉप एक्ट्रेस कितनी पढ़ी-लिखी अभिनेत्रियों पर नज़र डालते हैं.

परिणीति चोपड़ा: परिणीति चोपड़ा का पढ़ाई में कोई जवाब नहीं. परिणीति ने स्कूली शिक्षा अंबाला में हासिल की. इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन के मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल चली गईं. यहां से उन्होंने बिजनेस, फाइनेंस और इकॉनॉमिक्स में ट्रिपल ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की. एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के बाद वह भारत लौटीं, इसके बाद परिणीति ने मुंबई में यशराज फिल्मस में मार्केटिंग एण्ड पीआर कन्सलटेंट के पद पर तीन साल काम किया. इसी दौरान यशराज बैनर्स की फिल्म लेडीज वर्सेज रिकी बहल के लिए ऑडीशन चल रहे थे तो परिणीति ने भी उसमें हिस्सा लिया और उन्हें रोल के लिए चुन लिया गया. इस तरह परिणिती ने बॉलीवुड में कदम रखा और अपने एक नये करियर की सफल शुरुआत की.

प्रिटी जिंटा: डिंपल गर्ल प्रिटी जिंटा बॉलीवुड की खूबसूरत, चर्चित और सफलतम अभिनेत्रियों में से एक हैं. फिल्मों में आने से पहले प्रिटी ने साइकॉलॉजी में स्नातक की डिग्री हासिल की, इसके बाद शिमला के सेंट बीड कॉलेज से अंग्रेजी (ऑनर्स) की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने अपराधिक मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री भी हासिल की. लिरिल सोप के एड से प्रिटी को नई पहचान मिली. जिंटा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1998 में आई फिल्म दिल से की. प्रिटी ने फिल्मों में अभिनय करने के आलावा बीबीसी न्यूज के लिए भी कई लेख लिखे हैं.

अमीषा पटेल: अमीषा ने मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा हासिल की. इसके बाद वह साल 1992 में आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्थित टफ्ट्स विश्वविद्यालय चली गईं. यहीं अमीषा ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया. ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बतौर इकॉनोमिक एनालिस्ट खंडवाला सिक्योरिटी लिमिटेड से अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्हें मॉर्गन स्टेनले में काम करने का ऑफर भी मिला था. लेकिन अमीषा की दिलचस्पी अभिनय में थी, इसलिए उन्होंने अपने करियर को अभिनय की ओर मोड़ लिया. कुछ दिनों बाद ही वो भारत लौट आईं और सत्यदेव दुबे का थियेटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया और बॉलीवुड में एंट्री मारी और साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म कहो ना प्यार है से रातों रात स्टार बन गईं.

विद्या बालन: विद्या बालन को आज के दौर में कौन नही जानता. वह अपने सशक्त अभिनय के बल पर लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं. विद्या बालन ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट एंथोनी कॉन्वेंट स्कूल से हासिल की. इसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज से सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन किया. ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी में एमए में दाखिला लिया. इसी दौरान उन्हें फिल्म चकरम (मलयालम) में काम करने का ऑफर मिला, लेकिन इस फिल्म के बाद विद्या के फिल्मी करियर ने जोर नहीं पकड़ा. इसके बाद विद्या ने एड फिल्मों की ओर रुख किया. विद्या अशिक्षा के खिलाफ है. उन्होंने मिर्जापुर के थानेपुर गांव में एक कार्यक्रम में शिक्षा पर जोर दिया और देश में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा की घटनाओं के लिए अशिक्षा को जिम्मेदार ठहराया.

ऐश्वर्या रॉय बच्चन : मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या रॉय एक उत्कृष्ट अभिनेत्री होने के साथ-साथ सुशिक्षित भी हैं, ऐश्वर्या की प्रारंभिक शिक्षा आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में हुई. इसके बाद उन्होंने मुंबई के शांता-क्रूज स्थित आर्य विद्या मंदिर और बाद में डी जी रुपारेल कॉलेज माटूंगा में पढ़ाई की. पढ़ाई के साथ-साथ उन्हें मॉडलिंग के भी प्रस्ताव आते रहे. मॉडलिंग के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इतिहास में डिग्री हासिल की. ऐश्वर्या रॉय बच्चन ने एचएससी बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत अंक हासिल किए. इसके अलावा ऐश्वर्या ने आर्किटेक्चर में भी डिग्री हासिल की है.■

आमिर के बाद अब रितिक होंगे न्यूड

फिल्म पीके का पोस्टर रिलीज़ होते ही आमिर खान के अनोखे अंदाज़ ने धूम मचा दी थी, जिसमें आमिर खान न्यूड नज़र आए थे. अब कुछ ऐसे ही अंदाज़ में नज़र आनेवाले हैं बॉलीवुड के दूसरे सुपरस्टार रितिक रोशन.

वैसे पीके के लिए आमिर को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, बावजूद इसके रितिक को आमिर की राह पर चलने से परहेज नहीं है. खबर है कि आशुतोष गोवारिकर की अगली फिल्म मोहनजोदड़ो के ओपनिंग सीन में रितिक आमिर के अंदाज़ में नज़र आएंगे. फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग गुजरात के भुज में चल रही है. बताया जाता है कि इस फिल्म में रितिक को बहुत ज्यादा मस्क्युलर दिखने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें बेहद फुर्तीला नज़र आना है. तो इसके लिए तैयारी भी हुई होगी. सुनने में आया है कि यूके के एक ट्रेनर से उन्होंने तीन महीने ट्रेनिंग भी ली है. इस फिल्म से साउथ की ऐक्ट्रेस पूजा हेगड़े बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं. वैसे, अब देखना यह है कि जहां फिल्मों में आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगने की खबरों ने तूल पकड़ा हुआ है, वहां रितिक के इस न्यूड सीन को कैसे सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिलेगी.■

धर्म संकट में फंसे परेश

फिल्म ओह माय गॉड की सफलता के बाद एक बार फिर परेश रावल धर्म में फंसे दिखने वाले हैं. फिल्म का टीजर लॉन्च कर दिया गया है. फिल्म में परेश रावल के साथ नसीरूद्दीन शाह और अन्नू कपूर जैसे दिग्गज अभिनेता नजर आयेंगे. वहीं, इस फिल्म की कहानी अंग्रेजी फिल्म 'The Infidel' से प्रभावित है. फिल्म में हमेशा की तरह परेश रावल कॉमिक लेकिन प्रभावशाली भूमिका में नज़र आएंगे. जो पैदा तो मुसलमान हुआ था, लेकिन उसकी परवरिश हिन्दूओं की तरह होती है. अब ऐसा कैसे होता और इसके पीछे की क्या कहानी है, यह तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा. फिल्म में एक इंसान के धर्म संकट के बारे में बताया गया है, जिसे कई सालों बाद पता चलता है कि वो किसी और धार्मिक आस्था वाले परिवार में पैदा हुआ था. फिल्म धर्म संकट 10 अप्रैल को रिलीज होगी.■

आलिया को मिल गया बचपन का प्यार !

बचपन में हर किसी का कोई न कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस होती है. वह उससे एक बार जरूर मिलना चाहता है. ऐसा ही कुछ हुआ बॉलीवुड की चुलबुली गर्ल आलिया भट्ट के साथ. जी हां उन्हें भी बचपन से एक फिल्म स्टार का क्रश था. आलिया की बचपन की पसंद अभिनेता शाहिद कपूर थे. आलिया ने ऐसा एक वेबसाइट को दिये इंटरव्यू में बताया कि शाहिद कपूर उनके बचपन के क्रश हैं. उन्होंने आगे बताया कि जब वह 10 साल की थीं तब उन्होंने शाहिद कपूर की फिल्म इश्क विश्क देखी थी. इस फिल्म को देखने के बाद से शाहिद उन्हें अच्छे लगने लगे थे. आलिया इस मामले में लकी हैं क्योंकि उनका अपने फेवरेट एक्टर के साथ काम करने का सपना पूरा हो गया है. आलिया और शाहिद जल्द ही फिल्म शानदार में नज़र आयेंगे. आलिया ने वर्ष 2012 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. दर्शकों ने उनकी एक्टिंग को काफी सराहा था. इसके बाद उन्होंने हाईवे, हंप्टी शर्मा की दुल्हानियां और 2 स्टेट्स जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया है. वहीं शाहिद हाल ही में फिल्म हैदर में नज़र आये थे. इस फिल्म में उन्होंने चॉकलेटी बॉय से हटकर भूमिका निभाई थी. इस फिल्म में दर्शकों ने उनके रफ लुक और उनकी दमदार एक्टिंग को खूब पसंद किया. अब आलिया और शाहिद की जोड़ी पहली बार एकसाथ सिल्वर स्क्रीन पर रोमांस करती नजर आयेगी. दोनों के फैंस के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है. वहीं आलिया और शाहिद इस फिल्मों के अलावा उड़ता पंजाब में भी मुख्य भूमिका निभायेंगे. फिल्म में इन दोनों के अलावा करीना कपूर भी हैं. अब देखना होगा कि आलिया और शाहिद की जोड़ी दर्शकों को कितना पसंद आती है.■

कैट की जगह दीपिका को बनाएंगी नीतू अपनी बहू!

कपूर खानदान के चिराग और बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को लेकर आए दिन तरह-तरह की चर्चा होती रहती है. सुनने में आया है कि ये दोनों पिछले काफी समय से लिव-इन में रह रहे हैं. रणबीर कैट के साथ अपने रिश्ते को शादी का नाम तक दे सकते हैं. लेकिन लगता है कि रणबीर की मां नीतू सिंह को कैटरीना बहू के रुप में पसंद ही नहीं हैं. अब ऐसा लग रहा है कि नीतू कैट की जगह दीपिका पादुकोण को पसंद करती हैं. दरअसल नीतू सिंह ने हाल ही में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली है जिसने कई तरह की अफवाहों को जन्म दिया है. ये तस्वीर रणबीर की मां नीतू सिंह ने होली के मौके पर बधाई देने के लिए फिल्म ये जवानी है दीवानी के गाने बलम पिचकारी गाने से रणबीर-दीपिका की एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी. इसके बाद यह फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो गई. नीतू के फोटो को इस तरह से पोस्ट करने से लोगों को लगने लगा कि रणबीर और दीपिका को एक साथ करने का शायद नीतू का ये इशारा है. हालांकि शुरूआत में खबर आई थी कि शायद नीतू इस रिश्ते से खुश नहीं थी. और यही वजह थी कि रणबीर दीपिका के साथ अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सके. लेकिन अब जब रणबीर कैट साथ हैं तो ऐसे में इस फोटो को कई तरह का रुप दिया जा रहा है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

23 मार्च –29 मार्च 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

ऐसे में कैसे लड़ेंगे मांझी

नीतीश कुमार के खिलाफ आर–पार की लड़ाई लड़ने का शंखनाद करने वाले मांझी गुट के विधायकों द्वारा विश्वास मत के पक्ष में मतदान कर देने से उनके समर्थक हतप्रभ और निराश हैं. समर्थकों का कहना है कि इतनी डरी हुई सेना नीतीश कुमार से कैसे लड़ेगी? ये लोग बिहार के सम्मान और नीतीश कुमार के कुशासन की बात करते हैं और अपनी विधायकी बचाने के लिए नीतीश कुमार के आगे घुटने टेक देते हैं. मतलब साफ है कि बिहार के विकास और नीतीश को हटाने से कहीं ज्यादा मांझी गुट के नेता अपनी विधायकी बचाने और अपनी स्वार्थ सिद्धी को तवज्जो दे रहे हैं.

सरोज सिंह

जैसा की अनुमान था नीतीश कुमार ने बड़ी ही आसानी से अपनी सरकार का विश्वास मत हासिल कर लिया. सरकार के पक्ष में 140 वोट पड़े जबकि विपक्ष में किसी ने वोट ही नहीं डाला. बड़े ही परंपरागत तरीके से भाजपा ने विश्वास मत पर सरकार या बेहतर कहें तो नीतीश कुमार को घेरने की दोस्ताना कोशिश की और बाद में नीतीश कुमार ने इसका जवाब देकर विश्वासमत प्रस्ताव में मतदान कराने की औपचारिकता पूरी कर दी. नेता प्रतिपक्ष बातें कभी–कभी गंभीर कर रहे थे पर उनके चेहरे की भाव भंगिमा बता रही थी कि वह सही मायनों में सरकार को घेरने में गंभीर नहीं थे. खैर जैसे–तैसे समय पूरा हुआ और सरकार ने बहुत ही आसानी से विश्वास मत हासिल किया. लेकिन इस विश्वास मत में जो सबसे गंभीर सवाल उभर कर सामने आया है वह यह है कि आखिर जीतन राम मांझी खेमे ने नीतीश सरकार के पक्ष में वोट क्यों डाला. सदन के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि खुद सत्ता पक्ष ने वोटिंग की मांग की. स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने दो बार ध्वनि मत से विश्वास प्रस्ताव पास कराने की कोशिश की लेकिन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने लॉबी डिवीजन की मांग रख दी.

राजद के अब्दुल बारी सिद्दकी ने भी उनकी मांग का समर्थन किया. इसके बाद स्पीकर ने लॉबी डिवीजन का फैसला किया. विधायकी बचाने को मजबूर मांझी गुट के दस विधायकों ने भी विश्वास मत के पक्ष में वोट दिया. इन विधायकों में वृषिण पटेल, नीतीश मिश्रा, अनिल कुमार, शाहिद अली खान, राजीव रंजन, अजय प्रताप, सुमित कुमार सिंह, सुनील कुमार, राजेश्वर राज, और दिनेश कुशवाहा शामिल हैं. नीतीश कुमार के ख़िलाफ आर–पार की लड़ाई लड़ने का शंखनाद करने वाले इन नेताओं के इस रवैये ने उनके समर्थकों को हतप्रभ कर दिया. समर्थकों का कहना है कि इतनी डरी हुई सेना नीतीश कुमार से कैसे लड़ेगी. ये लोग बिहार के सम्मान और नीतीश कुमार के कुशासन की बात करते हैं और अपनी विधायकी बचाने के लिए नीतीश कुमार के आगे घुटने टेक देते हैं. मतलब साफ है कि बिहार के विकास और नीतीश को हटाने से कहीं ज्यादा मांझी गुट के नेता अपनी विधायकी को तवज्जो दे रहे हैं. अगर सत्ता और विधायकी ही महत्वपूर्ण है तो फिर चिल्ला चिल्लाकर नीतीश कुमार की आलोचना करने का क्या मतलब. जो नेता सिद्धांत के लिए अपनी विधायकी दांव पर नहीं लगा सकते ऐसे नेता जनता की भलाई की बात कैसे सोच सकते हैं. उन्हें तो बस अपनी भलाई की चिंता है.

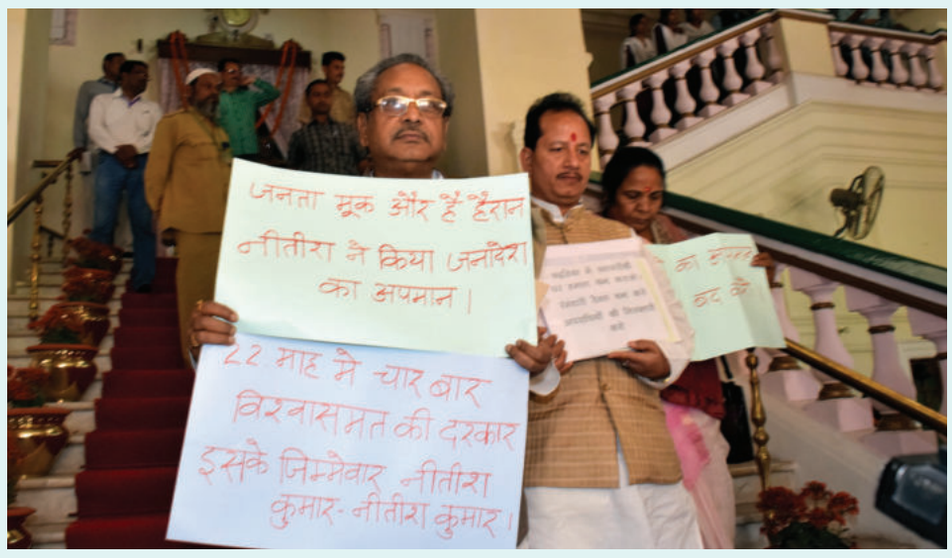

आइये सबसे पहले वोट डालने के लिए खुद जीतन राम मांझी की सफाई को समझने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा कि साथी विधायकों की सदस्यता नहीं जाए इसलिए उन्हें रणनीति के तहत सदन में जाकर मतदान करने के लिए कहा गया था. अभी सत्र चलेगा और सरकार को हर दिन बहुमत साबित करना है. जब हम बहुमत में होंगे सरकार को गिरा देंगे. अपने खुद के न जाने पर उन्होंने कहा इस विधानसभा अध्यक्ष के रहते मैं सदन में नहीं जाउंगा. वृषिण पटेल और नीतीश मिश्रा ने कहा कि हमलोग जदयू में रहकर नीतीश कुमार का विरोध करते रहेंगे. चूंकि अभी पार्टी में हैं इसलिए व्हिप मानना ही पड़ेगा. लेकिन जानकार सूत्र बताते हैं कि विश्वास मत के ठीक पहले यानि की 10 फरवरी को मांझी गुट की एक अहम बैठक इसी मसले पर विचार के लिए बुलाई गई थी. इस बैठक में वोट डालने को लेकर अलग अलग राय थी. कुछ नेताओं ने कहा कि अगर विधायकी गंवानी भी पड़े तो पड़े पर नीतीश कुमार के पक्ष में वोट डालना सही नहीं रहेगा. कहा गया कि इससे समर्थकों में बहुत ही गलत संदेश जाएगा और हमलोगों की लड़ाई की धार कमजोर हो जाएगी. लेकिन कुछ नेताओं की राय थी कि कुछ विधायक पहली बार ही जीत कर आए हैं और अगर विधायकी चली गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी. आखिरकार दो घंटे के मंथन के बाद फैसला विश्वास मत के पक्ष में वोट देने का ही ले लिया गया. लेकिन इसे लेकर मांझी गुट के कई नेता खुश नहीं हैं. उन्हें लगता है कि यह गलत लाइन है और जनता को इसके बाद भरोसे में लेना मुश्किल होगा. सूत्रों पर भरोसा करें तो मांझी गुट में बेहतर तालमेल का घोर अभाव है. हर बड़े नेता का अहंकार तालमेल बनाने के आगे आ जा रहा है. यह गलत रणनीति और विधायकी न खोने का मोह ही था कि विश्वास मत साबित करने से पहले ही जीतन राम मांझी को अपना इस्तीफा देना पड़ा. उस समय भी कई विधायकों ने अपनी विधायकी दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं दिखाई. मांझी गुट में अभी इतनी धारा है कि सबको समेटना खुद जीतन राम मांझी के लिए मुश्किल हो रहा है. बेहतर तालमेल का अभाव गांधी मैदान के धरने में भी दिखा. मांझी गुट के कई नेता नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ने का दावा तो करते हैं पर व्यवहार में उनका द्वंद साफ दिखाई पड़ जाता है. कभी हां और कभी ना की लाइन जीतन राम मांझी को कमजोर कर रही है. विधायकी बचाने के लिए नीतीश कुमार के पक्ष में वोट डाल देने से तो और भी फजीहत हो गई है.

जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि ये सारे छूटे हुए कारतूस हैं इनसे कुछ होने वाला नहीं है. ये आपस में ही लड़ते लड़ते समाप्त हो जाएंगे इसलिए इनकी चर्चा करना ही बेकार है. ये लोग बात तो बड़ी–बड़ी करते हैं लेकिन जब विधायकी की बात आई तो घुटने टेक देते हैं. ऐसे स्वार्थी लोगों पर बिहार की जनता कैसे भरोसा कर सकती है. अरे जो नीतीश कुमार का नहीं हुआ वह किसी का हो सकता है क्या? मांझी गुट पहले अपनी लड़ाई से तो निपट ले तो फिर नीतीश कुमार से लड़ने की बात सामने आएगी. जानकार बताते हैं कि मांझी खेमे को भी एहसास है कि उन्हें जो प्रारंभिक बढ़त मिली थी उसे वे लगातार गंवा रहे हैं. अगर यह सिलसिला नहीं थमा तो फिर भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. कुछ नेता मांझी गुट में बने रहने को लेकर भी दुविधा में हैं. उन्हें लगता है कि यह मोर्चा ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है. इसलिए ऐसे नेता खुलकर नीतीश के खिलाफ सामने नहीं आ रहे हैं. हां, उनकी बयानवाजी से पकड़ना मुश्किल होगा कि आखिर वे चाहते क्या हैं. अभी मांझी गुट के साथ ऐसे कई नेता हैं जिनका भाजपा की टिकट पर लड़ना लगभग तय है. इसलिए ऐसे नेता भी मांझी के साथ केवल अपना समय बिता रहे हैं. चुनाव नजदीक आते ही वे भाजपा के पाले में चले जाएंगे. इसलिए बहुत सारे नेताओं की राय है कि ऐसे नेताओं को मोर्चा के कार्यक्रमों में बहुत तवज्जो नहीं दिया जाए. कुल मिलाकर कहा जाए तो एक उहापोह की स्थिति है. लड़ाई के लिए बहुत ही स्पष्ट लाइन नहीं है समय के हिसाब से फैसले लेने का मिजाज बनता जा रहा है. अब ऐसे हालात में नीतीश कुमार के खिलाफ वास्तविक विकल्प बनने की बात कहना ज्यादती नहीं है तो क्या है? ऐसे में नीतीश सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई कैसे होगी इसका जवाब तो जीतन राम मांझी ही दे सकते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

चीनी मिल के लिए धरना

मधुबनी जिले के सकरी लोहर एवं सीमावर्ती दरभंगा जिले के रैयाम चीनी मिल को चालू करने के लिए 14 फरवरी के रोज मधुबनी समाहरणालय के सामने चीनी मिल चालू करो संघर्ष मोर्चा में मोर्चा के संरक्षक लालबहादुर सिंह के नेतृत्व में धरना दिया गया. धरनार्थी वक्ताओं ने कहा कि इन इलाके के किसानों का मुख्य आय का श्रोत उक्त तीनों चीनी मिल रहे हैं विगत 20 वर्षों से इन मिलों के बंद रहने के कारण मधुबनी व दरभंगा के किसान घोर आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं. यहां के किसानों की माली हालत बहुत ही खराब हो चुकी है. फिर भी सरकार इन चीनी मिलों को चलाने के लिए ध्यान नहीं दे रही हैं. धरना से पूर्व में माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री बिहार सरकार को समाहर्ता मधुबनी के द्वारा इन मांगों से अवगत करा दिया गया है. सत्याग्रह कार्यक्रम में मधुबनी नागरिक मंच के संयोजक अमरेश श्रीवास्तव एवं डॉ. हरेन्द्र भट्ट ने भी धरना कार्यक्रम को संबोधित किया .

लनामिविवि में विरोध-प्रदर्शन

दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा पूर्व से घोषित कार्यक्रम के तहत सीनेट की बैठक का घेराव कर विरोध-प्रदर्शन किया गया. विवि के पीजी बॉटनी विभाग में जहां सीनेट की बैठक होनी थी वहां अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह से ही आइसा अभाविप एवं छात्रा समागम के छात्र पहुंच चुके थे परंतु परिसर का मुख्य द्वार बंद होने के कारण सभी छात्र बाहरी द्वार पर खड़े थे, छात्र संगठन से जुड़े छात्र परिसर में जाना चाह रहे थे. परंतु द्वार बंद होने के कारण परिसर में जाना संभव नहीं था. मुख्य द्वार पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद छात्र द्वार को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे. इसी बीच सीनेट के एक सदस्य वहां आ पहुंचे जिन्हें बैठक में शरीक होने के लिए अंदर जाना था. जैसे ही सीनेट सदस्य के लिए वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने मुख्य द्वार को खोला कि वहां पर मौजूद विभिन्न छात्र संगठनों से जुड़े सदस्य नारेबाजी करते हुए सीनेट की बैठक स्थल तक पहुंच गए. **– जय शंकर पाण्डेय**

महिला दिवस पर गोष्ठी

जबतक देश की आधी आबादी पूरी तरह से जागरूक नहीं होती और अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पाती तब तक एक सभ्य समाज की कल्पना करना बेमानी है. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गांधी संग्रहालय में मानवाधिकार उल्लंघन नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' गोष्ठी को संबोधित करते हुए एसएसबी के सेनानायक राकेश सिन्हा ने उक्त बातें कहीं. गोष्ठी की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रभूषण पाण्डेय ने की जबकि मौके पर एसएसबी के उप सेनानायक, वरिष्ठ पत्रकार राजेश नारायण सिन्हा, आईसीडीएस के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रचीर कुमार, मानवाधिकार इल्लंघन नियंत्रण प्रकोष्ठ के जेनरल सेक्रेटरी सह पत्रकार राकेश ओझा, इंतेजारुल हक, चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विरेन्द्र जलान, रोटरियन देव प्रिय मुखर्जी, जिला स्कूल की प्राचार्या शशि कला, रेड क्रॉस के सचिव ई. विभूति नारायण सिंह, भाजपा नेत्री बिन्टी शर्मा, राजद नेत्री नसीमा खातून, जदयू नेत्री डॉ. कुमकुम सिन्हा, अधिवक्ता ममता रानी वर्मा, इन्दू पाठक, पर्यवेक्षिका संघ की श्वेता गौतम, अल्का सिन्हा समेत बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये. मंच का संचालन राकेश ओझा ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन संयोजक ज्ञानेश्वर गौतम ने किया.

किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने किया पुतला दहन

पूर्वी चम्पारण जिले के चकिया सुभाष चौक पर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश कानून के विरोध में किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुतला दहन किया. मोर्चा के अध्यक्ष नागेन्द्र सहनी के नेतृत्व में चकिया गांधी मैदान के मुख्य द्वार पर आयोजित पुतला दहन कार्यक्रम में केन्द्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों आक्रोश व्यक्त किया और जुलूस भी निकाले. पुलता दहन के बाद सभा आयोजित की गयी. सभा को संबोधित करते हुए मोर्चा के उपाध्यक्ष रामचन्द्र प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि यह अध्यादेश किसानों के लिए काला कानून होगा. किसानों का अधिकार छीना जाएगा. इस मौके पर मुकेश पटेल, भिखारी गिरी, विश्वनाथ पांडेय, बैद्यनाथ भगत, ब्रजेश ओझा, जय प्रकाश यादव, राजीव कुमार यादव, लखीन्द्र राम, सोहा सिंह, जगदीश सिंह, विक्रम राय, ध्रुव कुशवाहा, चन्दन कुमार ठाकुर, मनई राम, विपिन कुशवाहा, रामायण पासवान, कैलाश सहनी, रामएकबाल मांझी, जय प्रकाश सहनी, सुनील ठाकुर सहित अन्य थे. ■

– इंतेजारुल हक

सीतामढ़ी - शिवहर

लोजपा फेंक रही अल्पसंख्यकों पर पासा

बिहार विधानसभा चुनाव का समय जैसे –जैसे करीब आ रहा है, तकरीबन सभी राजनीतिक दलों की चुनावी कवायद जोर पकड़ने लगी है. पिछले दिनों सीतामढ़ी व शिवहर जिले में लोक जनशक्ति पार्टी के तत्वावधान में पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन संपन्न हुआ. सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक के नेताओं ने एक स्वर से स्वीकार किया कि राजद व जदयू जैसी पार्टियों ने अब तक अल्पसंख्यकों को ठगने का काम किया है. अब अल्पसंख्यकों के लिए लोजपा से बेहतर कोई विकल्प नहीं है. कार्यक्रम के बाद चर्चा यह भी जोर पकड़ने लगी है कि एक ओर अल्पसंख्यक भाजपा के नरेंद्र मोदी का पक्षधर होने से कतराती है तो दूसरी ओर आखिर भाजपा गठबंधन में शामिल राम विलास पासवान के लोजपा को अल्पसंख्यक कैसे पचा पायेगा? वैसे पार्टी नेताओं ने पहली राजनीतिक पाठशाला में लोजपा कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती के लिए लगने की बात कही है ...

विकास कुमार

चुनाव चाहे लोकसभा का हो अथवा विधानसभा का. अब गठबंधन लगभग सभी दलों की मजबूरी बन गया है. कोई भी दल वर्तमान में इस स्थिति में नही दिख रहा जो खुद की बदौलत अपनी चुनावी नौका को समर से सकुशल निकालने में कामयाब हो सके. कारण कि कमोवेश सभी ने आम जनता के बीच अपना विश्वास खो दिया है. झूठ की पटरी पर दौर रही वर्तमान राजनीति का आलम है कि विकास योजनाओं में कमीशनखोरी व भ्रष्टाचार शिखर पर ठहाका लगा रहे हैं. सरकार प्रायोजित योजनाओं का लाभ वाजिब हकदारों को मिलना मुश्किल हो गया है. बेरोजगारी की समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है. शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, शौचालय जैसी सुविधाओं के लिए लोगों को मोहताज रहने की विवशता बनी है. परंतु यह बिडंबना है कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के भाषण में कमोवेश ऐसे ही मसलों का निदान कराने की बात आम हो गयी है. साथ ही समाज को जातिगत आधार पर भड़का कर वोट बटोरने की मंशा भी. मगर अब मतदाता भी राजनीतिक दलों की नब्ज पकड़ चुका है. जो हालात बन रहे है, अगर आम लोगों की धारणा में कोई बदलाव नहीं हुआ तो सीतामढ़ी-शिवहर जिले में राजनीतिक बदलाव की संभावनाओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है. लोग यह समझने लगे हैं कि सत्ता के शिखर पर बैठे नेताओं को केवल और केवल अपनी सलामती की चिंता है. आम जनता अथवा कार्यकर्ताओं की पीड़ा से उनका कोई लेना-देना नहीं रह गया है. जहां तक राजनैतिक सम्मेलन का सवाल है तो सभी दलों ने अपनी चुनावी पारी शुरू कर दी है. पहले सत्र में कार्यकर्ताओं को खुश करने का हर संभव प्रयास किया जाने लगा है. जाति-पार्टी, धर्म-मजहब के नाम पर लोगों को चुनावी सपना दिखाने का अभियान शुरू हो गया है.

अब सीतामढ़ी एवं शिवहर जिले में संपन्न लोजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता सम्मेलन की चर्चा करें तो इसमें कई बातों पर चर्चा की गयी है. पहला कि अब तक सूबे की सत्ता में रही जदयू अथवा राजद ने अल्पसंख्यकों को कोई तरजीह नहीं दी. दूसरा कि जदयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को सत्ता से बेदखल किया है. तीसरा यह कि लोजपा के अलावा अल्पसंख्यकों के पास अब कोई विकल्प नहीं है. पहले सीतामढ़ी के गांधी मैदान में आयोजित सम्मेलन पर चर्चा आवश्यक है. जिला लोजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष फखरूद्दीन अली अहमद की अध्यक्षता एवं दलित सेना के जिलाध्यक्ष हरजीतू पासवान के संचालन में आयोजित सम्मेलन में प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. शाहनवाज अहमद कैफी ने जदयू व राजद पर अल्पसंख्यकों को ठगने का आरोप लगाया. कहा कि दोनों के शासन में अकलियतों के विकास को लेकर कोई काम नहीं हुआ है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम बिलास पासवान को अल्पसंख्यकों का सच्चा हितैषी होने की भरपुर वकालत की. जबकि पूर्व विधायक नगीना देवी, राष्ट्रीय सचिव राम पुकार राय, पार्टी के प्रदेश सचिव संजय कुमार पूर्वे, पटना महानगर अध्यक्ष शौलत राही, जिलाध्यक्ष त्रिलोकीनाथ झा उर्फ मोहन झा, वरीय नेता सबीह अहमद, हरिनारायण पासवान, सुशीला देवी पासवान, नसीर अहमद, नागेश पासवान, अहमदी खातून व राम विनय कुशवाहा समेत अन्य ने सूबे की सरकार पर जमकर निशाना साधा.

कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने इस बात का भी जिक्र किया कि दलित व पिछडों का मसीहा होने का दंभ भरने वाली जदयू सरकार के नीतीश कुमार ने दलित को सीएम की कुर्सी पर बैठा कर हटा दिया. अगर चल रही चर्चाओं पर गौर करें तो लोजपा का सीधा चुनावी निशाना दलित व अल्पसंख्यक वोट पर टकराती नजर आ रही है. पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से लोजपा के पक्ष में एकजुट होने की अपील की. दूसरी ओर शिवहर जिला मुख्यालय स्थित गांधी नगर भवन में जिलाध्यक्ष असलम आजाद की अध्यक्षता एवं तरियानी प्रखंड अध्यक्ष अजीत कुमार के संचालन में आयोजित सम्मेलन में अल्पसंख्यकों से आगामी विधानसभा चुनाव में किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील पार्टी नेताओं ने की. कार्यक्रम में पार्टी के जिलाध्यक्ष विजय कुमार पांडेय, जिला प्रभारी संजय कुमार पूर्वे, अब्बास अहमद, शौकत अली, मो मोहीउद्दीन, राम बालक राय, भगीरथ पासवान, राजेश्वर राय व अजय शर्मा समेत अन्य ने अपना विचार व्यक्त किया. दोनों ही जिलों में सपन्न लोजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम विलास पासवान को अल्पसंख्यकों का हितैषी बताया गया.

अब सवाल यह उठता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों ने गठबंधन के बावजूद भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर मतदान करने का काम किया. तब गठबंधन के तहत ही विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक भाजपा समर्थित लोजपा को किस तरह से अपना समर्थन देंगे? इस पर चर्चा कुछ अलग तरह की चल रही है. लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में मामला केंद्र सरकार से जुडा था. परंतु विधानसभा चुनाव का मसला बिहार के विकास से जुडा है. गठबंधन तब भी था और अब भी है. इस अजीबो-गरीब स्थिति पर कोई भी कुछ खुल कर बोलने को तैयार नहीं है. वैसे अल्पसंख्यकों को भाजपा को छोड़ तकरीबन सभी दलों ने अपना वोट बैंक माना है. चुनावी मौसम में अभी राजद व जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होना बाकी है. अब राजद व जदयू लोजपा के अल्पसंख्यक पाशे को किस तरह से काटेंगे, यह तो बाद की बात है. परंतु इतना तो साफ है कि अब लोजपा ने जदयू-राजद को भी अल्पसंख्यकों से मिलन की मजबूरी को बढ़ा दिया है.■

feedback@chauthiduniya.com

कैसे वापस होगी आयुर्वेद कॉलेज की प्रतिष्ठा

इंतेज़ारुल हक़

आखिर कैसे वापस हो सकेगी चम्पारण के इकलौते आयुर्वेदिक कॉलेज की प्रतिष्ठा? इसकी बदहाली के जिम्मेदार कौन लोग है? क्या फिर से इसे सीसीआईएम मान्यता दे पायेगी और सामुहिक रूप से कॉलेज से त्याग पत्र देकर राज्य के किसी दूसरे कॉलेजों में अपनी सेवा दे रहे शिक्षक वापस हो सकेंगे?चम्पारण विकास मोर्चा द्वारा इसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने व शासी समिति का गठन कराने के लिए किये जा रहे प्रयासों व हो रहे धरना-प्रदर्शनों तथा उपवास कार्यक्रमों ने इस मुद्दे पर एक गरम बहस छेड़ दी है और तरह-तरह के सवाल खड़े किये जाने लगे हैं.

पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी में वर्ष 1955 में स्थापित इस इकलौते रविन्द्र नाथ मुखर्जी आयुर्वेदिक कालेज की बदहाली के पीछे एक लम्बी कहानी है. मेडिकल की पढ़ाई के मामले में कभी बिहार समेत देश के कई राज्यों में अपनी अलग पहचान रखने वाला यह महाविद्यालय वर्ष 2008 तक ठीक-ठीक चला और हजारों की संख्या में छात्रों को चिकित्सक बनने का मौका दिया. प्रत्येक वर्ष यहां नामांकन होता था और अपनी पढ़ाई पूरी कर छात्र डॉक्टर बनते थे.किन्तु सत्ता बदलने के बाद सरकार ने पुरानी शासी समिति को भंग कर दिया और वर्ष 2008 में नई शासी समिति बनायी.स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार समिति के सचिव व प्रेम कुमार अध्यक्ष बनाये गये.जानकार बताते हैं कि जैसे ही इस नई कमिटि ने अपनी कार्यभार संभाली वैसे ही इस महाविद्यालय की हालत खराब होने लगी.यह महाविद्यालय राजनीति का अखाड़ा बन गया और प्राचार्य की कुर्सी को लेकर गुटबाजी शुरू हो गयी. यहां छह वर्षो में आठ बार प्राचार्य बदले गये और तमाम नियमों व कानूनों की खुलेआम धज्जिया उड़ाते हुए कॉलेज की मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया गया. पहले शासी समिति ने कालेज के वरिष्ठ शिक्षक कृष्णमोहन झा को प्राचार्य बनाया और कुछ ही महीनों के बाद फिर पुराने प्राचार्य डॉ. हरिशंकर सिंह ब्रह्मचारी को प्राचार्य बनाया. फिर इन की कार्यशैली सचिव को पसन्द नहीं आयी और उन्हें हटाकर डॉ. इन्द्रसेन सिंह को प्राचार्य बनाया. बेहतर कार्य करने की क्षमता रखने वाले डॉ. सिंह की भी कार्यशैली शासी समिति ने स्वीकार नहीं किया और फिर उन्हें कुछ ही महीनों के बाद बाहर रास्ता दिखा दिया. फिर कृष्णमोहन झा को प्राचार्य की जिम्मेदारी सौंपी गयी. यह ड्रामा लगातार जारी रहा और कृष्णमोहन को हटाकर डॉ. विश्वम्भर पाठक को प्रभारी प्राचार्य पत्र दिया गया. डॉ. पाठक कालेज की व्यवस्था को नहीं सह पाये और फिर डॉ. कृष्णमोहन झा प्राचार्य की कमान संभालने लगे. फिर शासी समिति ने एक नया निर्णय लेते हुए. डॉ. हरिशेखर सिंह ब्रह्मचारी को प्राचार्य की कुर्सी पर बैठा दिया जो अभी वर्तमान में अपनी सेवा दे रहे हैं.अभी कॉलेज की हालत यह है कि वर्तमान प्राचार्य को मिलाकर करीब आधा दर्जन शिक्षक बचे हैं जब कि सभी शिक्षक सामुहिक रूप से त्याग पत्र देकर किसी दूसरे महाविद्यालय में अपनी सेवा दे रहे हैं. कालेज के शिक्षक डॉ प्रो. प्रभाकर शरण, डॉ. प्रो. फिरोज अहमद, डॉ. प्रो. अबू असगर, डॉ प्रो. अरुण कुमार श्रीवास्तव, डॉ. प्रो. सच्चिदानन्द श्रीवास्तव, डॉ. प्रो. संजय कुमार श्रीवास्तव, डॉ. प्रो. विंदेश्वर वर्मा, डॉ. प्रो. अंजू वर्मा, डॉ. प्रो. रामनारायण सिंह, डॉ. प्रो. गणेश सिंह, डॉ. प्रो. अर्जुन सिंह तथा डॉ. प्रो. शिवनारायण सिंह आदि मुजफ्फरपुर स्थित नीतेश्वर महाविद्यालय में अपनी सेवा दे रहे है. वहीं डॉ. प्रो. ब्रह्मदेव तिवारी,डॉ. प्रो. इस्लाम अंसारी, डॉ प्रो. नवल किशोर सिंह व डॉ. प्रो. सत्येन्द्र सिंह रांची कॉलेज में अपनी सेवा दे रहे हैं. पूर्व प्राचार्य बीरगंज में स्थित एक मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवा दे रहे है. जानकार यहां भी बताते हैं कि महाविद्यालय के शासी समिति द्वारा एक बार भी ऑडिट नही करायी गयी और बड़े पैमाने पर राशि का बंदरबाट किया गया है. मामलों की गहनता से जांच हो तो अनेक गड़बड़ घोटाले सामने आयेंगे. अभी कॉलेज की शासी समिति ही भंग है और नई कमेटी गठित करने के लिए सरकार द्वारा जिलाधिकारी से प्रस्ताव मांगा गया है. कॉलेज की बदतर हालत में सुधार लाने व फिर से इसकी प्रतिष्ठा को वापस दिलाने के लिए चम्पारण विकास संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आंदोलन कर रहे मोर्चा के अध्यक्ष रायसुन्दर देवा शर्मा बताते हैं कि एक साजिश के तहत इस महाविद्यालय की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया गया है. वे स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार पर सीधा निशाना साधते हैं और कहते हैं कि खुले-आम विभागीय नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इस महाविद्यालय की राशि का घोटाला हुआ है जिसकी गहनता से जांच होनी चाहिए. दूसरी तरफ युवा समाज सेवी साजिद रजा इस कॉलेज को चम्पारण का एक महत्वपूर्ण धरोहर बताते हुए कहते हैं कि इसकी बेहतरी के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी,दी जायेगी.वे कॉलेज की दुर्दशा के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि इसे दुधारू गाय बना दिया गया जिस कारण स्थिति और खराब हो गयी. कॉलेज के कर्मियों की भी चिन्ता किसी को नहीं हुई और वे भुखमरी की कगार पर हैं.यहां यह भी बता दें कि मोर्चा के बैनर तले बीते दिनों समाहरणालय के समक्ष आहूत उपवास कार्यक्रम में पूर्व प्राचार्य विनय कुमार वर्मा, अब्दुल हमीद कैप्टन, शैलेन्द्र शुक्ला, साजिद रजा, आलोक कुमार, मुकेश चौधरी, डॉ0 इमेश श्रीवास्तव, अनिकेत पाण्डेय, अजहर हुसैन अंसारी, डॉ. किशुन, रामाकान्त सिंह, अक्षय कुमार, पंकज द्विवेदी, तारकेश्वर प्रसाद, डॉ0 मनीष कुमार, सुधाकर शर्मा, सुमन मांझी, सुदिष्ट नारायण ठाकुर, सत्यदेव प्रसाद, लखन प्रसाद, अशोक वर्मा, कुमार रंजन, योगेन्द्र राम, मो. एकबाल, रविन्द्र नाथ सिंह, नगीना तिवारी, मधुसूदन महतो, शिवा जी, अनिल कुमार, अखिलेश मिश्रा, मंटू मिश्रा व प्रवीण कुमार बिट्टू समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे.■

चम्पारण

feedback@chauthiduniya.com

बेगूसराय

बेगूसराय में कांग्रेस गुटबाज़ी की शिकार

पार्टी की स्थिति इतनी अजीब हो चुकी है कि जहां एक ओर पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जहां दिल्ली में हाल ही संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की पराजय का ठीकरा गुटबाज़ी पर फोड़ रहा है वहीं बेगूसराय में गुटब़ाजी अपने चरम पर पहुंच चुकी है. विडंबना यह है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस गुटबाज़ी को समाप्त करने की बजाये इसे हवा दे रहे हैं. जिले के नये पार्टी अध्यक्ष अर्जुन सिंह का मनोनयन स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को हज़म नहीं हो रहा है. इन सभी गुस्साये लोगों का कहना है कि अर्जुन सिंह को जिलाध्यक्ष बनाने का सीधा नुकसान पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा.

सुरेश चौहान

बिहार विधान सभा का चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आता जा रहा है कांग्रेसियों की गुटबाज़ी इसी रफ्तार से बढ़ती जा रही है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी इभरती गुटबाज़ी को खत्म करने की बजाये इसे हवा देते नजर आ रहे हैं.

एक बार फिर बेगूसराय में कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह ज़मीन पर आ गई. कांग्रेस पार्टी के नये जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह के पद संभालते ही पार्टी में भूचाल आ गया. जिले के कांग्रेसी नेताओ में जबरदस्त अंतर्विरोध व्याप्त है. पार्टी की स्थिति इतनी अजीब हो चुकी है कि जहां एक ओर पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जहां दिल्ली में हाल ही संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की पराजय का ठीकरा गुटबाज़ी पर फोड़ रहा है वहीं बेगूसराय में गुटब़ाजी अपने चरम पर पहुंच चुकी है. विडंबना यह है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस गुटबाज़ी को समाप्त करने की बजाये इसे हवा दे रहे हैं. जिले के नये पार्टी अध्यक्ष अर्जुन सिंह का मनोनयन स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को हज़म नहीं हो रहा है. इन सभी गुस्साये लोगों का कहना है कि अर्जुन सिंह को जिलाध्यक्ष बनाने का सीधा नुकसान पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा.

काफी पहले ही प्रदेश अध्यक्ष ने जिला कमेटी को भंग कर दिया था. इसके बावजूद भी यहां काम कर रहे कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं का मनोबल नहीं गिरा था. वे सभी पूर्व की भांति ही जिले के महत्व-पूर्ण मुद्दों को लेकर बैठक किया करते थे. इसी बीच पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू किया गया.

विचार करने वाली बात यह है कि इस समय भी प्रदेश अध्यक्ष ने स्थानीय नेताओं और पूर्व जिलाध्यक्ष की अनदेखी की थी. इसी के बाद पार्टी में व्याप्त गुटबाज़ी को बल मिलना शुरू हुआ. फिर भी पार्टी नेताओं ने सदस्यता अभियान से मुंह नहीं मोड़ा और काफी जोश के साथ सदस्य बनाने में जुट गए. इसी बीच अर्जुन सिंह को जिला अध्यक्ष बनाए जाने की सूचना प्राप्त होते ही कार्यकर्ता/नेता हतप्रभ रह गए और इसका जोरदार विरोध किया. पार्टी के जिला कार्यालय कांग्रेस भवन में पार्टी की एक पूर्व जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपस्थित पार्टीजनों ने इसके विरोध में रोषपूर्ण वक्तव्य दिया. यहां तक कह डाला कि यदि पार्टी आलाकमान इस पर पुनर्विचार नहीं करती है तो वे पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे सकते हैं. पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष अभय कुमार सिंह सार्जन के नेतृत्व में काफी संख्या में नेता एवं कार्यकर्ताओं ने पटना का रुख किया और सदाकत आश्रम में विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया. इस दौरान प्रदश अध्यक्ष के समर्थकों एवं प्रदर्शनकारियों के बीच जबर्दस्त झड़प हुई और मामला हाथपाई तक पहुंच गया. बीच-बचाव होने पर प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी, सार्जन सिंह को धरना पर से उठाकर अपने साथ ले गए. इसी बीच पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति ने पत्रांक 1105 दिनांक 04.03.15 द्वारा सार्जन सिंह को कारण बताओं नोटिस थमा दिया. जिलाध्यक्ष के बदले जाने से पार्टी नेताओं में नाराज़गी नहीं है. नाराज़गी का कारण जिले के वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा किए जाने से है. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि जिले में रामदेव राय, राम बदन सिंह, शशि शेखर राय, संजय सिंह (मोसादपुर), संजय सिंह (बरौनी) शांति स्वामी, सुबोध सिंह (शोकहारा), सुबोध कुमार सिंह (रामदीरी), रामानन्द सिंह (रतनपुर), अमीर सिंह (अधिवक्ता), मदन प्रसाद सिंह, शिव नन्दन सिंह, अनुपम कुमार अन्नु, राकेश सिंह, शमशू जोहा, लखन पासवान, राम विलास सिंह, नन्दकिशोर सिंह, नारायण प्रसाद सिंह, शिवजी सिंह, चुनचुन राय, सतीश कुमार बीरू, महेश सिंह, मिथलेश झा, सुशील मिश्र, राम प्रकाश सिंह सहित दर्जनों नेताओं की पहचान कांग्रेसी नेता के रूप में है. ये सभी जमीन से जुड़े नेता हैं. यदि इनमें से किसी को जिलाध्यक्ष बनाया जाता तो पार्टी की साख बरकरार रहती. लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने एक ऐसे गुमनाम कांग्रेसी को जिलाध्यक्ष बना दिया जिसकी खास पहचान नहीं है. पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता पहली बार उनका नाम सुन रहे हैं. सम्प्रति अर्जुन सिंह जिला पार्षद हैं. कांग्रेसी भी हैं. लेकिन पार्टी गुटबाज़ी की शिकार है. गुटबाजी को पाटने के लिए अर्जुन सिंह को काफी परिश्रम करना पड़ेगा, जो आसान नहीं है.दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामदेव राय भी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में पक्षपात करने एवं सदाकत आश्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज कराने का आरोप प्रदेश अध्यक्ष पर लगाते हुए प्रदेश कार्यसमिति से त्यागपत्र दे दिया है. जिसके प्रभाव से बेगूसराय में भी प्रदेश अध्यक्ष के मनमानी एवं पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ कोई नया गुल खिल सकता है.■

पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष अभय कुमार सिंह सार्जन के नेतृत्व में काफी संख्या में नेता एवं कार्यकर्ताओं ने पटना का रुख किया और सदाकत आश्रम में विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया. इस दौरान प्रदश अध्यक्ष के समर्थकों एवं प्रदर्शनकारियों के बीच जबर्दस्त झड़प हुई और मामला हाथपाई तक पहुंच गया. बीच-बचाव होने पर प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी, सार्जन सिंह को धरना पर से उठाकर अपने साथ ले गए.

feedback@chauthiduniya.com

अन्य ख़बरें

सूची जमा करने का निर्देश

गोगरी अनुमंडल के परबत्ता प्रखंड क्षेत्र के सेविकों से अपने अपने पोषक क्षेत्र में मतदाता सूची से वंचित लोगों को सर्वे कर जल्द से जल्द सूची संबंधित बीएलओ या बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करने का निर्देश प्रखंड के स्वयं सहायता समूह भवन के प्रांगण में आयोजित बीएलओ की बैठक में एसडीओ संतोष कुमार ने दी. मतदाता सूची में पुरुष व महिलाओं की संख्या में अत्यधिक अन्तर है, इसे दूर करने के लिए हर हाल में महिला मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ाने के लिए सख्त निर्देश दिए. विभाग द्वारा इसे संतुलित करने का निर्देश दिया गया है. इसलिए हर हाल में नाम जोड़ने के क्रम में महिला मतदाता का नाम किसी कीमत पर छूटना नहीं चाहिए. वहीं प्रभारी जीपीएस रवीन्द्र कुमार ने बीएलओ से कहा कि 18 वर्ष आयु के सभी पुरुष व महिला का मतदाता सूची में नाम जोड़ने की दिशा में आवश्यक पहल करें. बीएलओ ने शिकायत की कि मतदाता पहचान पत्र को शुद्ध कराने के लिए कई बार प्रयास किया गया लेकिन आज तक वोटर पहचान पत्र शुद्ध नहीं हो सका. वहीं एसडीओ ने कहा कि प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा हैं मौके पर बीईओ अखिलेश प्रसाद यादव, सीडीपीओ कुमारी वर्तिका सुमन, बीएलओ मंजीत कुमार, धीरेन्द्र कुमार, मो. मेराज, विजय कुमार, संजीव कुमार, पंकज कुमार मदन प्रसाद एवं राजीव कुमार आदि उपस्थित थे.

महासेतु का निर्माण शुरू

गोगरी अनुमंडल के परबत्ता प्रखंड के दक्षिणी छोर पर गंगा के उपर बनने वाले अगुवानी-सुल्तानगंज महासेतु के मुख्य भाग का वास्तविक कार्य अब शुरू हो गया है. चयनित कंपनी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट मैनेजर अनिल कुमार ने बताया कि कंपनी के द्वारा बड़े बड़े क्रेन आदि पहुंच गए हैं. इसको लेकर श्रीरामपुर ठुट्ठी व डुमरिया गांव के बीच महेशखूंट पथ से सटे बेस कैंप बनाया गया है. एप्रोच पथ समेत इस महासेतु के बनने में 17 अरब 10 करोड़ से अधिक राशि का प्रशासनिक स्वीकृति मिली है. गंगा की उपधारा में शीघ्र ही तत्कालीन ब्रिज चालू हो जायेगा. इसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है. चहुचर्चित अगुवानी, सुल्तानगंज महासेतु के निर्माण से पहले कंपनी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन को गंगा की उपधारा में तत्कालीन स्टील पाइल ब्रिज बनाने की आवश्यकता है. सर्वेयर इंजीनियार जितेन्द्र कुमार ठाकुर, राजेन्द्र कुमार ने बताया कि गंगा की मुख्य दियारा में पाईलिंग तथा अन्य कार्य करने के लिए बड़े-बड़े मशीनों को ले जाने के लिए उपधारा में स्टील पाइल ब्रिज की जरूरत है. यहां 217 एकड़ 94 डिसमिल जमीन अधिग्रहण होगा. इसकी प्रक्रिया तेज हो चुकी है. पुल निर्माण निगम द्वारा सर्वे के पश्चात खेसरा निर्धारित हेतु जिला भूअर्जन को सौंपा गया है. जहां सीओ कार्यालय को भेजा गया है. सीओ शैलेन्द्र कुमार के द्वारा सभी कर्मचारियों से विहित प्रपत्र में अधिग्रहण के लिए रिर्पोट मांगा गया है.

– गीता कुमार

एक नज़र

शांति समिति की बैठक

पुलिस कप्तान सुनिल कुमार ने आपसी सौहार्द्र के बीच सभी त्योहारों को मनाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जबतक समाज में शांति व्यवस्था कायम नहीं होगी तब तक खुशहाली संभव नहीं है. वे मोतिहारी के स्थानीय एमजेके इन्टर कॉलेज में स्थित स्टेडियम में आयोजित जिला शांति समिति की अनुमण्डल स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर जिलाधिकारी के प्रतिनिधि उप विकास आयुक्त अनिल चौधरी ने कहा कि पंचायत स्तर पर शांति समिति गठित की जायेगी और प्रत्येक माह इसकी बैठक होगी. इस अवसर पर उपस्थित समिति के कार्यकारी अध्यक्ष धर्मवीर प्रसाद ने होली के मौके पर दुश्मनों से भी गले मिलने व शिकवा-शिकायत भूलकर समाज की बेहतरी के लिए कार्य करने की अपील की और कहा कि समाज में शांति व्यवस्था कायम कराने में जिला शांति समिति एक बेहतर कार्य योजना बनाकर अपनी भूमिका निभायेगी. बैठक को सदर के अनुमण्डल पदाधिकारी ज्ञानेन्द्र कुमार, नगर सभापति प्रकाश अस्थाना, प्रखण्ड प्रमुख अवधेश सिंह, कांग्रेस नेता बबन पाण्डेय, शांति समिति के सदस्य सरफराज आलम, नसीमा खातून आदि ने संबोधित किया. अन्त में धन्यवाद ज्ञापन सत्यशरण यादव ने किया और शांति समिति की गतिविधियों पर विस्तार से जानकारी दी. **– इंतेजारुल हक**

होली मिलन समारोह का आयोजन

सीतामढ़ी शहर के कोट बाजार में व्यवसायी संघ के तत्वावधान में वृहद होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया. संघ कार्यालय के समीप आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के मौके पर संघ के संरक्षक राधे श्याम शर्मा, अध्यक्ष निर्मल कुमार वियाहुत, सचिव गणेश सिकारिया, जनार्दन भरतिया, प्रमोद सर्राफ, अनिल भवसिंका, कैलाश हिसारिया, आलोक कुमार व पवन हिसारिया समेत दर्जनों ने एक दुसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी. समारोह में व्यवसायियों ने पूर्व की तरह समाज सेवा में भागीदारी का संकल्प लिया. **– ब्रजेश कुमार**

जिलाध्यक्ष ने किया उद्घाटन

सीतामढ़ी शहर के मेहसौल चौक स्थित राजा मार्केट में एक निजी क्लिनिक का उद्घाटन राजद जिलाध्यक्ष मो. शफीक खां ने फीता काटकर किया. मौके पर डॉ. मो. शमीम, डॉ. एम ठाकुर, डॉ. केएन गुप्ता, डॉ. आरके प्रकाश, अधिवक्ता मो. अली, प्रो.हसन मुस्तफा, कांग्रेस नेता मो. शम्स शाहनवाज समेत अन्य थे.
– विकास

गन्ना मंत्री का स्वागत

सूबे की गन्ना उद्योग मंत्री डॉ. रंजू गीता का सीतामढ़ी के मेहसौल में स्वागत किया गया. मदरसा रहमानिया मेहसौल के अध्यक्ष मो. अरमान अली के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षक मो. जफर हाशिम, मो. तनवीर आलम, मो. हसमत हुसैन, नूरजहां, मो जौहरअली ताज, मो. मजहर अली, मो. गुलाब अशरफ अली, सचिव मो. जफर कमाल अल्वी, देवेंद्र झा, अचलदेव पटेल, तसलीम अंसारी, नेयाज कुरैशी, मो. शौकत अली अरमान समेत अन्य थे.

कांग्रेस ने किया पुतला दहन

सीतामढ़ी जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में जिला मुख्यालय डुमरा स्थित समाहरणालय के समक्ष पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया. जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विमल शुक्ला के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में डॉ भुवनेश्वरी मिश्र, उपाध्यक्ष सत्येंद्र तिवारी, सीताराम झा, शिव शंकर शर्मा, विजेंद्र कुमार यादव, संजय कुमार, ताराकांत झा, मणि भूषण कुमार, राजीव कुमार, कमलेश तिवारी, अंजारुल हक तौहिद व वीरेंद्र कुशवाहा समेत अन्य थे. वही शिवहर में समाहरणालय मैदान में जिलाध्यक्ष मो. असद के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में उपाध्यक्ष ध्रुव नारायण सिंह, बालदेव प्रसाद, शिवचंद्र सहनी, धर्मनाथ सिंह व सुशील कुमार सिंह समेत अन्य थे. **– ब्रजेश**

आंगनबाड़ी सेविकाओं की रैली

गोगरी अनुमंडल में अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने रैली निकाली. पहले अलग-अलग पंचायतों में सेविकाओं ने रैली निकाली. बाद में अनुमंडल मुख्यालय में एकजुट होकर महिला दिवस के अवसर पर रैली में भाग लिया. परबत्ता प्रखंड आंगनबाड़ी सेविका संघ की अध्यक्ष कमला देवी के नेतृत्व में सेविकाओं ने प्रखंड मुख्यालय से रैली की शुरुआत की जो मड़ैया बाजार तक रैली गयी. इस दौरान रैली के माध्यम से महिलाओं को जागरुक करने का प्रयास किया. मौके पर सेविका नादिरा खातून, सहायिका बीबी सहनाज खातून, युवा समाजसेवी मो. सुलेमान, आशा चांदनी देवी सहित सैकड़ों आगनबाड़ी सहायोगी उपस्थित थे.

थानाध्यक्षों की लगी क्लास

गोगरी अनुमंडल के विभिन्न थानों का एसपी धुरत सायली सबला राम ने निरीक्षण किया और लम्बित कांडों की जांच में तेजी लाने को कहा. उन्होंने कहा कि लंबित मामलों में तेजी नहीं लाने वाले थानाध्यक्षों पर कार्रवाई होगी. मड़ैया ओपी में लंबित कांडों का निरीक्षण करते हुए अनुसंधानकर्ता को आवश्यक दिशा निर्देश दिये और अपहृत बालिका की बरामदगी किये जाने के अलावा अन्य कांडो के निष्पादन को लेकर पन्द्रह दिनों का समय निर्धारित किया. छितनिया, बैसा, कदमगाछी आदि स्थलों पर चौकीदार को तैनात करने का दिशा निर्देश दिया. उक्त ओपी क्षेत्र में मात्र दो चौकीदार के कार्यरत होने की बात बतायी गई. वहीं पुलिस कप्तान ने ओपी में कार्यरत सहायक अवर निरीक्षक आदि की जमकर क्लास ली तथा लंबित पड़े कांडों का निष्पादन समय पर करने, घटना के तुरंत बाद थाने में मामले को दर्ज करने, ओपी की साफ सफाई कराने आदि का निर्देश दिया. मौके पर मड़ैया ओपी प्रभारी मनीष कुमार, अवर निरीक्षक बालेश्वर दास, मो. अंजार अहमद, मो. जियाउल खान, शंभू साह,डोमी शर्मा भूखन कुमार आदि उपस्थित थे.

एक की मौत

गोगरी अनुमंडल के मड़ैया ओपी क्षेत्र के पसराहा नया गांव पहुंच पथ स्थित बलहा मोड़ के पास ट्रैक्टर व बाइक की टक्कर में नयागांव शिरोमणी टोला निवासी प्रशांत कुमार की मौत घटना स्थल पर ही हो गई. ट्रेलर में मिट्टी लोड होने के कारण नयागांव शिरोमणि टोला के प्रमोद सिंह की 24 वर्षीय पुत्र प्रशांत कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही आसपास से लोग दौड़कर घटनास्थल की ओर आए. तबतक युवक की मौत हो चुकी थी. वहीं मृतक की मां संजू देवी का रो-रोकर बुरा हाल है. वह कह रही थी कि बहन की धूमधाम से शादी करैय के शौक लागले रही गैले. युवक की मौत के खबर गांव पहुंचते ही कुछ ही क्षण बाद नयागांव शिरोमणी टोला से सैकड़ों लोग घटना स्थल पर पहुंचे. इधर ओपी प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि मृत युवक के परिजन मृत्युंजय सिंह के बयान पर थाना में मामला दर्ज कर शव को कैंजे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया हैं. वहीं घटना स्थल से ट्रैक्टर व क्षतिग्रस्त बाइक को पुलिस अपने कब्जे में ले लिया.■ **– गीता कुमार**

तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं

नीलम बताती हैं कि रूडी जी से मेरी मुलाकात साल 1990 में एक कॉमन फ्रेंड के घर में हुई थी. रूडी जी सिर्फ 26 वर्ष की उम्र में हीं एमएलए बन गए थे. उस मुलाकात में हम दोनों के बीच काफी देर तक बात हुई. इसके बाद करीब तीन दिन बाद रूडी जी ने मुझे प्रपोज कर दिया था. लेकिन मैंने उनका प्रपोजल एक दम से नहीं माना. मैंने कहा कि अगर मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं तभी मैं आप से शादी कर सकती हूं. उन्होंने ऐसा ही किया. उन्होंने मेरे माता-पिता से बातचीत की और उन्हें मनाया. मेरे माता-पिता को मनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई क्योंकि हम दोनों राजपूत परिवार से ताल्लुक रखते हैं. इसलिए लोग आसानी से मान गए.

इश्क पर ज़ोर नहीं है ये वो आतिश ग़ालिब कि लगाये न लगे और बुझाये न बने.

राधिका

मिर्ज़ा ग़ालिब का यह अशआर केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी पर बिल्कुल सटीक बैठता है. रूडी जितने बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उतने ही बड़े प्रेमी भी रहे हैं. प्रेम करने वाले राज-नेताओं की पंक्ति में एक नाम राजीव प्रताप रूडी का भी है. राजीव की मुलाकात नीलम से तब हुई थी, जब वे इंडियन एयरलाइंस में काम करती थीं. नीलम इंडियन एयरलाइंस में एयर होस्टेस थीं. हिमाचल प्रदेश की रहने वाली नीलम और राजीव को पहली नज़र में ही प्यार हो गया था. पहली नज़र के प्यार की बात ही कुछ और होती है. बात चली और वह बढ़ती गई. दोनों ने एक-दूजे के लिए कसमें खाईं. साथ जीने मरने के वादे किए. नीलम के बारे में बताया जाता है कि जब वो तीन साल की थीं उसी दौरान उनके पापा की पोस्टिंग अमेरिका हो गई थी. लिहाज़ा उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई थी. उसके बाद अजमेर के सोफिया कॉलेज से उन्होंने साइंस में स्नातक किया. कॉलेज की पढ़ाई के बाद उनकी इच्छा नेशनल स्पोटर्स में जाने की थी, लेकिन माता-पिता की सहमति न मिल पाने की वजह से वो इस फील्ड में नहीं जा सकीं. दरअसल नीलम बचपन से हीं खेल की शौकीन रही हैं. कई ऑउटडोर खेल में हिस्सा ले चुकी हैं. जिनमें उन्हें पुरस्कार भी मिले हैं.

बताया जाता है कि सालाना स्पोटर्स में तो नीलम बैग भर कर पुरस्कार घर लाती थीं. एमए और लॉ की पढ़ाई के दौरान इंडियन एयरलाइंस के लिए उनका चुनाव हो गया. फिर करीब 14 वर्षों तक उन्होंने इंडियन एयरलाइंस में काम किया. नीलम फ्लाइट सर्विस में ऑल इंडिया हेड थीं. नीलम बताती हैं कि रूडी जी से मेरी मुलाकात साल 1990 में एक कॉमन फ्रेंड के घर में हुई थी. रूडी जी सिर्फ 26 वर्ष की उम्र में हीं एमएलए बन गए थे. उस मुलाकात में हम दोनों के बीच काफी देर तक बात हुई. इसके बाद करीब तीन दिन बाद रूडी जी ने मुझे प्रपोज कर दिया था. लेकिन मैंने उनका प्रपोजल एक दम से नहीं माना. मैंने कहा कि अगर मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं तभी मैं आप से शादी कर सकती हूं. उन्होंने ऐसा ही किया. उन्होंने मेरे माता-पिता से बातचीत की और उन्हें मनाया. मेरे माता-पिता को मनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई क्योंकि हम दोनों राजपूत परिवार से ताल्लुक रखते हैं. इसलिए लोग आसानी से मान गए. फिर बात आई कुंडल की. हम दोनों की कुंडली मिलाई गई. कुंडली मिल जाने के बाद हमारी शादी फाइनल कर दी गई और ऐसे हम दोनों की शादी हो गई. हमारे प्यार को आप लव एट फर्स्ट साइट भी कह सकते हैं. नीलम आगे कहती हैं कि रूडी जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के आदमी हैं. केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद उनका स्वभाव बहुत ही सरल है. दरअसल शुरुआत से ही उनकी सरलता ने ही मुझे उनकी तरफ खींचा था. उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं बोली जिससे मुझे कभी भी कोई दुख पहुंचा हो. रूडी जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं. मेरी हर बात को सुनते और समझते हैं. इसके अलावा मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का ख्याल रखते हैं. हमारी शादी को लव कम अरेंज मैरेज भी कहा जा सकता है.

राजीव प्रताप रूडी की बात की जाए तो वो बिहार से सांसद हैं. इसके अलावा वे यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन अनुमोदित मियामी, फ्लोरिडा के सिमसेंटर से ए-320 विमान उड़ाने की विशेषज्ञता प्राप्त वाणिज्यिक पायलट लाइसेंसधारक भी हैं. चुनावी दंगल में उतरने से पहले वे पटना के ए. एन. कॉलेज में लेक्चरर थे. 1990 में महज छब्बीस साल की उम्र में वे बिहार राज्य विधानसभा के एक विधायक के रूप में चुने गए. उनकी गिनती सबसे कम उम्र के विधायकों में से एक के रूप में की जाती है. 1996 में वे बिहार के छपरा से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में संसद के लिए निर्वाचित हुए. 1999 में वे फिर से चुने गए और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री के रूप में शामिल हुए और बाद में उन्हें पदोन्नत करते हुए एक स्वतंत्र प्रभार के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री बना दिया गया. जब राजीव प्रताप रूडी मंत्री बने तो नीलम ने अपनी एयर हॉस्टेस की नौकरी छोड़ दी. ये दोनों अपने प्यार को बड़े प्यार से जी रहे हैं. इनकी दो बेटियां हैं. दोनों दिल्ली में अध्ययन कर रही हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

जाले में धीमा पड़ा भाजपा का सदस्यता अभियान

जय शंकर पांडेय

दरभंगा में विगत दो माह से चलाए जा रहा भाजपा का ऑनलाइन सदस्यता अभियान अपने लक्ष्य से अभी काफी पीछे चल रहा है. जबकि 31 मार्च को सदस्यता अभियान का समापन होने वाला है. दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुई भाजपा की करारी हार, एवं बिहार में आठ माह पूर्व में हुए विधानसभा उप चुनाव में जिले के जाले विधानसभा उप चुनाव चुनाव में हुई पार्टी का हार से यहां के कार्यकर्ता काफी टूट चुके हैं. कहा जाता है कि जाले विधानसभा क्षेत्र में पार्टी 50 हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य रखे हुए हैं परंतु यह लक्ष्य पार्टी पूरा कर पाती है कि नहीं यह तो 31 मार्च के बाद सदस्यता अभियान पूरा होने के बाद ही पता चल सकेगा. मालूम हो कि जाले विधान सभा क्षेत्र में जाले का 26 एवं सिंहवाड़ा की 13 पंचायतें पड़ती हैं. जबसे पार्टी द्वारा ऑनलाइन सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई हैं तब से केवल जाले प्रखंड में तीन बार एवं सिंहवाड़ा प्रखंड में दो बार ऑनलाइन सदस्यता अभियान जानकारी व तैयारी को लेकर बैठक अयोजित हुई है. 26 फरवरी को कार्यकर्ताओं की बैठक भरवाड़ा में आयोजित की गई थी. परंतु इस बैठक में मुश्किल से एक तिहाई पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर के पदाधिकारी व मंच मोर्चा के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी ही उपस्थित हुए जिससे साफ जाहिर होता है कि कार्यकर्ता अब पार्टी के क्रियाकलापों से कितने रुष्ट हैं. मालूम हो कि पार्टी के 20-25 वर्षो से लगातार जुड़े रहने वाले एवं पार्टी के लिए तन व मन से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम लोगों ने बुरे दिनों में पार्टी के लिए दिन रात एक करके काम किया पार्टी की सदस्यता अभियान से लेकर पार्टी बैठक सहित पार्टी हित के लिए कार्य किया, परंतु पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा यहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं को कभी भी तरजीह नहीं दी गई. पार्टी का प्रदेश नेतृत्व शुरू से मनमानी ढंग से कार्य कर रहा है. कभी बाहरी लोगों को टिकट थमा दिया जाता है, तो कभी कल तक पार्टी को गाली देने वाले दूसरे दल से आए लोगों को टिकट दिया जाता है. कुछ कार्यकर्ताओं ने चौथी दुनिया के साथ बातचीत करते हुए अपना नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि यहां के कुछ पुराने साथी जो अब अपने को बड़ा नेता मानते हैं और अब वे चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रह गए है. यही

साथी साथी प्रदेश नेतृत्व के साथ मिलकर क्षेत्रीय ऊर्जावान कार्यकर्ताओं का मनोवल तोड़ने का काम करते हैं. यही कारण है कि 2014 के उपचुनाव में जाले में भाजपा की करारी हार हुई है. यहां से पार्टी ने अगर किसी सवर्ण को टिकट दिया होता तो उसकी जीत निश्चित थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया और नतीजा सबके सामने है.

पार्टी में सदस्यता अभियान की बात है तो 26 जनवरी को भरवाड़ा में हुई पार्टी की बैठक से साफ़ ज़ाहिर होता है,कि बार-बार पार्टी के विधानसभा प्रभारी व जिला प्रभारी के द्वारा सदस्यता अभियान में तेजी लाने के लिए बैठक की जा रही है, लेकिन सफलता के करीब पार्टी नहीं पहुंच पा रही हे. वर्तमान में यहां लगभग 33 प्रतिशत लक्ष्य के हिसाब से सदस्यता हो पाई है इसमें अगर देखा जाए तो 20 प्रतिशत सदस्यता पार्टी के दावेदार लोगों के द्वारा विभिन्न पंचायत में घूम-घूम कर की गई है. वैसे किसी भी पार्टी के लिए संगठन पार्टी की रीढ़ माना जाता है अगर पार्टी अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को फिर से रिचार्ज किए बिना संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं की अपेक्षा के विरुद्ध काम करने का कार्य करता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उपचुनाव वाली स्थिति कहीं न दोहरा जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है. जहां तक सदस्यता अभियान की बात है तो जाले वाली स्थिति तकरीबन सभी विधानसभा क्षेत्रा में है, वहीं पार्टी अंदरूनी गुटबाजी में भी लिप्त है, हाल ही में भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष शिशिर कुमार झा ने जिलाध्यक्ष हरि सहनी को त्याग पत्र दे-दिया है. श्री झा ने आरोप लगाया के ऐसा उन्होंने पार्टी के वरीष्ठ नेताओं के दबाव में आकर किया है. उन्होंने कहा कि हमें स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा था. श्री झा के साथ युवा मोर्चा के दर्जनों पदाधिकारियों ने भी सामुहिक इस्तीफा दिया है, इसका भी सदस्यता अभियान पर असर पड़ रहा है. दरभंगा के स्थानीय सांसद कीर्ति झा आजाद के द्वारा अलीनगर प्रखंड के नवानगर ग्राम को आदर्श ग्राम के रूप में चयनित किया गया है, जिस रोज सांसद ने आदर्श ग्राम में अपने कार्यो का शुभारंभ किया. उस कार्यक्रम में सांसद ने जिलाध्यक्ष हरि सहनी को आमंत्रित तक नहीं किया था इसके बावजूद जिलाध्यक्ष ने आदर्श ग्राम में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया, परंतु सांसद ने जिलाध्यक्ष के बारे में कोई चर्चा नहीं की. पार्टी में वर्तमान इस गुटबाजी की वजह से सदस्यता अभियान पूरे जिले में मंद गति से चल रहा है. जिसका सीधा ख़ामियाज़ा पार्टी इस साल होने वाले विधानसभा में भुगतेगी.■

पार्टी में सदस्यता अभियान की बात है तो 26 जनवरी को भरवाड़ा में हुई पार्टी की बैठक से साफ़ ज़ाहिर होता है कि बार-बार पार्टी के विधानसभा प्रभारी व जिला प्रभारी के द्वारा सदस्यता अभियान में तेजी लाने के लिए बैठक की जा रही है, लेकिन सफलता के करीब पार्टी नहीं पहुंच पा रही हे. वर्तमान में यहां लगभग 33 प्रतिशत लक्ष्य के हिसाब से सदस्यता हो पाई है इसमें अगर देखा जाए तो 20 प्रतिशत सदस्यता पार्टी के दावेदार लोगों के द्वारा विभिन्न पंचायत में घूम-घूम कर की गई है.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

23 मार्च -29 मार्च 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

भाजपा और सपा दोनों की साख पर बट्टा

फिर से सुलग रहा भट्टा परसौल

देशभर में मशहूर हो चुका भट्टा परसौल गांव इस बार भी सुलग रहा है. कुछ संशोधनों के बाद लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पास भी हो गया, लेकिन केंद्र की किसान विरोधी नीति के खिलाफ उत्तर प्रदेश के भट्टा परसौल गांव में किसान नेता व भारतीय प्रजा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनवीर तेवतिया का किसान-मजदूर सत्याग्रह 15 फरवरी से जारी है. तेवतिया 20 फरवरी से लगातार आमरण अनशन पर हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है. तेवतिया ने ऐलान किया है कि अगर केंद्र ने किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो भारी तादाद में किसान दिल्ली कूच करेंगे. तेवतिया कहते हैं कि देश का किसान विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन भ्रष्ट नेता नहीं चाहते कि कोई सुगम रास्ता निकले, क्योंकि इससे उनकी और नौकरशाहों की कमीशनखोरी बंद हो जाएगी. समय रहते इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो आनेवाले दिनों में इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता.

प्रभात रंजन दीन

केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीति के खिलाफ 15 फरवरी से जारी किसानों का आंदोलन व्यापक शक्ल लेने की तरफ बढ़ रहा है. इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के किसान भी शरीक होने लगे हैं. हरियाणा के किसान भी साथ आने लगे हैं. तेवतिया ने ऐलान किया है कि भट्टा परसौल में किसानों का सत्याग्रह और उनका आमरण अनशन 62 दिन चलेगा और अगर केंद्र ने किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो भारी तादाद में किसान दिल्ली कूच करेंगे. भट्टा परसौल से शुरू हुए किसानों के इस आंदोलन में मथुरा, आगरा, बागपत, अलीगढ़, आजमगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ के अलावा बड़ौत, पलवल और मेवात के किसान भी एकजुट हो रहे हैं. बिहार के कुछ इलाकों से भी किसानों के जुटने की खबर है.

कुछ संशोधनों के बाद लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पास भी हो गया, लेकिन केंद्र की किसान विरोधी नीति के खिलाफ उत्तर प्रदेश के भट्टा परसौल गांव में किसान नेता व भारतीय प्रजा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनवीर तेवतिया का किसान-मजदूर सत्याग्रह 15 फरवरी से जारी है. तेवतिया 20 फरवरी से लगातार आमरण अनशन पर हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है. इस आंदोलन के समर्थन में अलीगढ़ में टप्पल और जिकरपुर में भी आंदोलन चल रहा है, जिसका नेतृत्व भारतीय प्रजा पार्टी के उत्तर प्रदेश महासचिव स्वामी राजपाल सिंह और संचालन शौबीर सिंह विद्यार्थी व शीशराम कर रहे हैं. आंदोलनकारी किसान भूमि अधिग्रहण नीति में संशोधन तो चाहते ही हैं, साथ ही उनकी यह भी मांग है कि किसानों की आधी जमीन ही अधिग्रहीत की जाए और शेष जमीन विकसित कर उन्हें वापस कर दी जाए. किसान मांग कर रहे हैं कि 25 प्रतिशत जमीन को नि:शुल्क मिक्स लैंडयूज बनाने की अनुमति दी जाए. इसके अलावा जिस रेट में सरकार जमीन बेचती है उसके औसत मूल्य का 60 प्रतिशत मुआवजे के रूप में किसानों को दिया जाए. तेवतिया का मानना है कि इस नीति से किसानों को फायदा होगा. दूसरी तरफ किसान भूमि अधिग्रहण का खुद ही विरोध नहीं करेंगे और उनकी सहमति की जरूरत समाप्त हो जाएगी. प्राधिकरण में रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी. इससे स्मार्ट सिटी के साथ-साथ आदर्श गांव भी तैयार हो सकेगा. जो लोग गांवों में व्यवसाय कर रहे हैं, उनका धंधा तेजी से चल पड़ेगा, क्योंकि परियोजना में उन्हें कई प्रकार के काम मिल जाएंगे. लोगों को अच्छा दूध और ताज़ा सब्जी-फल प्राप्त होंगे और किसानों को अच्छा रेट मिल जाएगा.

मनवीर तेवतिया के नेतृत्व में शुरू हुए किसान आंदोलन का सबसे रोचक पहलू यह है कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने भट्टा परसौल से किसानों का आंदोलन शुरू करने की घोषणा की थी. केंद्र में आई भाजपा सरकार के नए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस उसी गांव से आंदोलन शुरू करने का मन बना चुकी थी, जिस गांव ने राहुल गांधी को काफी सुर्खियां दी थीं. तमाम प्रतिबंधों को पार करते हुए पिछली बार जब राहुल गांधी भट्टा परसौल गांव पहुंचे थे तो उसने देशभर के लोगों का ध्यान खींचा था, लेकिन कांग्रेस फिर बैकफुट पर चली गई. भू-अधिग्रहण विवाद को लेकर ही भट्टा परसौल पांच साल पहले चर्चा में आया था. मोदी सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून में किए गए बदलाव के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ इसी गांव से लड़ाई शुरू करने की जनवरी में घोषणा भी कर दी थी. पूर्व केंद्रीय मंत्री

जयराम रमेश, आदित्य जैन, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं द्वारा आंदोलन शुरू करने और फिर दिल्ली से पदयात्रा कर राहुल गांधी के इस आंदोलन में कूद पड़ने की रूपरेखा भी तैयार हो गई थी, लेकिन इसमें कोई सियासी लोचा हो गया और राहुल भी अज्ञातवास पर चले गए. कांग्रेस ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी की पदयात्रा के पहले हर ब्लॉक में नुक्कड़ सभाएं करने और माहौल बनाने की रणनीति भी तैयार कर ली थी. कांग्रेस ने भूमि अध्यादेश के मुद्दे पर व्यापक विरोध की तैयारी के लिए तीन सदस्यीय समूह का गठन भी कर दिया था, जिसमें जयराम रमेश के अलावा आनंद शर्मा और केवी थॉमस भी शामिल थे, लेकिन भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ भट्टा परसौल गांव से हल्ला बोल अभियान शुरू करने की कांग्रेसी तैयारी का बिना पट पर आए ही पटाक्षेप हो गया.

उल्लेखनीय है कि जमीन अधिग्रहण के ही खिलाफ 2010 में भट्टा परसौल गांव से बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था. पुलिस और किसानों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ था. इसमें दो किसान और पुलिस के जवानों की मौत हो गई थी. इसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया था. तब पार्टी महासचिव राहुल गांधी अचानक गांव पहुंच गए थे. उन्होंने अंग्रेजों के जमाने के अधिग्रहण कानून में बदलाव की आवाज उठाते हुए भट्टा परसौल से अलीगढ़ तक पैदल यात्रा की थी. मोदी ने केंद्र की सत्ता में आते ही प्रावधान किया कि जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों की सहमति जरूरी नहीं, जबकि कांग्रेस की सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 70 फीसद किसानों की सहमति लेने का प्रावधान किया था.

आमरण अनशन के कारण किसान नेता की हालत खराब होती जा रही है. ग्रेटर नोएडा के एसडीएम सदर बच्चू सिंह के अलावा अनशन स्थल पर कोई अधिकारी नहीं आया. बच्चू सिंह भी एक दिन फ्लाइंग स्क्वैड की तरह आए और चले गए. सरकारी इंतजाम बस इतना हुआ कि एक सरकारी डॉक्टर तेवतिया की रोजाना मेडिकल जांच कर चला जाता है. तेवतिया अब खड़े नहीं हो पा रहे हैं. उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है. ब्लड प्रेशर तेजी से घट रहा है, वजन कम हो रहा है और शुगर लेवल में गिरावट आ रही है. तेवतिया कहते हैं कि देश का किसान विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन भ्रष्ट नेता नहीं चाहते कि कोई सुगम रास्ता निकले, क्योंकि इससे उनकी और नौकरशाहों की कमीशनखोरी बंद हो जाएगी. हमारे द्वारा दिया गया प्रस्ताव निश्चित ही विकास की गति को रफ़्तार देगा. तेवतिया ने कहा कि जल्दी ही यह आंदोलन देश के अन्य हिस्सों से भी शुरू हो जाएगा. मोदी सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति किसान विरोधी है. देश का किसान इससे आहत है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ दिखावा कर रही हैं. मांस के निर्यात पर रोक लगाने की मांग पर तेवतिया जोर देकर कहते हैं कि मांस के व्यापार के कारण देश का पशुधन नष्ट हो रहा है और दूध-दही की भारी किल्लत होने लगी है. इसके अलावा मांस की कीमत भी आसमान छूने लगी है. पशुधन काटने से पशुओं की कीमतें इतनी बढ़ती जा रही हैं कि अब पशु खरीदना किसानों के सामर्थ्य से बाहर होता जा रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

ताकि किसान खुद ही खेत छोड़ कर भाग जाएं

एक तरफ किसानों की जमीनें सरकार जब चाहे तब छीन लेगी, दूसरी तरफ किसानों की फसलों को लुटा कर सरकार पहले से ही किसानों को खेत छोड़ कर भागने पर मजबूर कर रही है. गेहूं, धान, गन्ना और आलू समेत अन्य फसलों की लागत का मूल्य भी उत्तर प्रदेश के किसानों को नहीं मिल पाता. किसानों का पैदा किया हुआ अनाज दलालों और बिचौलियों द्वारा औने-पौने भाव पर खरीदा जाता है. सरकारी खरीद केंद्र दलालों के भी दलाल का काम कर रहे हैं. गन्ना की फसलें चीनी मिलों द्वारा लूटी जा रही हैं. मौजूदा सरकार के अदूरदर्शी तौर-तरीकों के कारण गन्ना भी बिचौलिए ही खरीद रहे हैं. चीनी मिलों में गन्ना किसानों का करोड़ों का बकाया है और यह बढ़ता ही जा रहा है. अब तो चीनी मिलें गन्ना लेने के एवज में किसानों को पर्चियां तक नहीं दे रही हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि चीनी मिलें गन्ना मूल्य के भुगतान में भीषण कोताही बरत रही हैं. इस करतूत पर दर्जनों चीनी मिलों का गन्ना क्षेत्र डायवर्ट भी किया गया, लेकिन चीनी मिलों की हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. गन्ना मूल्य भुगतान में लापरवाही बरतने वाली कुछ चीनी मिलों के खिलाफ गन्ना एवं चीनी आयुक्त सुभाषचंद्र शर्मा ने कार्रवाई भी शुरू की. इस क्रम में कुंदरकी, थाना भवन, मकसूदापुर, बरखेड़ा, करीमगंज और चांदपुर के कई गन्ना क्रय केन्द्रों को निकटवर्ती दूसरी चीनी मिलों को डायवर्ट किया गया. इसके बाद गोला, खम्बारखेड़ा, चिलवरिया, बिलारी एवं बेलवाड़ा चीनी मिलों के भी कई क्रय केन्द्रों को अन्य चीनी मिलों के लिए डायवर्ट किया गया. सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि पेराई सत्र 2014-15 का ही किसानों के बकाये का 3931.82 करोड़ रुपया चीनी मिलों ने भुगतान नहीं किया. पिछले बकायों की तो बात ही छोड़ दें. सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले पेराई सत्र का भी 640.24 करोड़ रुपया किसानों को नहीं दिया गया. इस तरह किसानों के बकाये की राशि बढ़ती चली जा रही है. किसानों के साथ हो रहे ऐसे सलूक के खिलाफ अब विधानसभा में भी उग्र विरोध हो रहा है. गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर विधानसभा के मौजूदा सत्र में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और बसपा को छोड़कर सम्पूर्ण विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया. विपक्ष ने आरोप लगाया कि चीनी मिलों ने पेराई सत्र 2013-14 के गन्ना मूल्य का ही किसानों को भुगतान नहीं किया तो 2014-15 के बकाये का भुगतान कैसे होगा. इस पर मंत्री रियाज अहमद ने कहा कि पेराई सत्र 2013-14 का 640.24 करोड़ रुपया बकाया रह गया है. मंत्री ने यह भी कहा कि निजी क्षेत्र की करीब दर्जनभर चीनी मिलों ने गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया, जिनके खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं और पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. कांग्रेस विधायक अजय कुमार लल्लू ने देवरिया और कुशीनगर में 15 चीनी मिलों के घटकर छह रह जाने पर गहरी चिंता जाहिर की. वहां की चीनी मिलें गन्ना किसानों और मजदूरों का अरबों रुपया दबाए बैठी हैं. भाजपा के लोकेन्द्र सिंह ने कहा कि गन्ना किसानों की आजीविका पर संकट आ गया है. किसान अपने बच्चों की पढ़ाई और उनकी शादी नहीं कर पा रहे हैं. उन पर बैंकों के कर्ज का भीषण दबाव है. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी मिल मालिक बकाये का भुगतान नहीं कर रहे हैं. सरकार चीनी मिल मालिकों को रियायतें और सुविधाएं देने में लगी रहती है. भाजपा के सतीश महाना ने कहा कि गन्ना किसानों के मामले में सरकार संवेदनहीन है. भाजपा के सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार और चीनी मिल मालिकों की साठगांठ है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती है. भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने चौथी दुनिया से कहा कि किसानों के पास खुद का हक पाने के लिए अब संघर्ष के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है. उत्तर प्रदेश के किसानों के सामने पहले से गन्ने का बकाया, धान की खरीद नहीं होने, यूरिया की कालाबाजारी, सिंचाई की सुविधा नहीं होने जैसी समस्याएं खड़ी थीं, अब उनकी जमीनें छिनने का भी खतरा मंडराने लगा है. पूर्वांचल के किसान नेता शिवाजी राय कहते हैं कि किसानों पर सरकारों का दबाव इसलिए भी है कि वे खुद ब खुद अपनी जमीनें छोड़ कर भाग जाएं और वे जमीनें कॉरपोरेट घरानों को फार्मिंग के लिए दे दी जाएं. भारत की कृषि के कॉरपोरेटाइजेशन की साजिशें चल रही हैं. ■

किसानों की मांग

- भूमि अधिग्रहण नीति में संशोधन हो (संशोधन के प्रस्ताव पीएमओ को पहले ही दिए जा चुके हैं).
- किसानों की आधी जमीन का ही अधिग्रहण किया जाए और किसानों की शेष जमीन को विकसित कर वापस किया जाए.
- किसानों की बची हुई आधी जमीन को विकसित कर उसके 25 प्रतिशत हिस्से को निःशुल्क मिक्स लैंड यूज के श्रेणी में रखने की व्यवस्था हो.
- जिस रेट पर सरकार जमीन बेचती है, उसका औसत मूल्य (रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल) का 60 प्रतिशत मुआवजे के रूप में किसानों को दिया जाए.
- रेल, सड़क, बिजली (हाई टेंशन) के लिए ली जाने वाली जमीन किसानों से लीज पर ली जाए और किसानों को उसका आजीवन लीज रेंट दिया जाए, ताकि किसानों की स्थायी आय का स्रोत बना रहे.
- भूमिहीन किसान-मज़दूर को निःशुल्क 200 वर्ग मीटर का प्लॉट मिक्स लैंड यूज की अनुमति के साथ मिले.
- किसानों को सम्बद्ध परियोजना में 25 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा मिले. उनके लिए कोई अलग रेट नहीं, बल्कि जिस रेट पर प्राधिकरण जमीन बेच रहा हो, वही किसानों के लिए भी लागू हो.
- किसानों की फसल की लागत समेत 20 प्रतिशत लाभ का मूल्य तय हो.
- दूध की भारी किल्लत को देखते हुए मीट का अंधाधुंध निर्यात तत्काल बंद हो.

उत्तर प्रदेश की खबरें इंटरनेट पर पढ़ने के लिए www.up.chauthiduniya.com लॉगऑन करें.

शिक्षा को बनाया अवैध कमाई का जरिया

किताबें तक नहीं छोड़ रहे घोटालेबाज

पाटेश्वरी प्रसाद

भ्रष्टाचारी, नेता, नौकरशाह, माफिया और दलाल मिल कर तमाम कल्याणकारी योजनाएं चट कर गए. इन लुटेरों से बच्चों के कल्याण से जुड़ी योजनाएं भी अछूती नहीं रहीं. मिड डे मील और छात्रवृत्ति योजनाओं से लेकर अन्य कई कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार किस कदर व्याप्त है, यह किसी से छिपा नहीं है. अब तो बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन में नेता अफसर और माफिया किस तरह चोरी-बटमारी कर रहे थे, सामने आ रहा है. बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा परिषदीय स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक की पुस्तकों के प्रकाशन में भारी वित्तीय अनिमितताएं किए जाने के कारण सरकार को प्रकाशन की टेंडर प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी. प्राइमरी स्कूलों का नया सत्र सरकार अप्रैल में शुरू तो करने जा रही है, लेकिन पुस्तकों के प्रकाशन का मामला अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ा है. पुस्तकों के प्रकाशन की जो प्रक्रिया निविदा के माध्यम से होनी थी, उसमें बड़ी वित्तीय अनियमितता के साथ-साथ शिक्षा माफियाओं और सम्बन्धित अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है. किताबों के लिए इको फ्रेंडली यानी वर्जिन पल्प से निर्मित कागजों का इस्तेमाल करने के बजाय रि-साइकिल्ड कागजों का इस्तेमाल किया जा रहा था.

परिषदीय स्कूलों में बच्चों को नि:शुल्क बांटी जाने वाली पाठ्यपुस्तकों की छपाई को लेकर उठे विवाद पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बेसिक शिक्षा परिषद के अफसरों को समस्त दस्तावेजों के साथ अपने आवास पर तलब किया और फटकार भी लगाई. मुख्यमंत्री ने अफसरों को यह निर्देश दिया कि बच्चों को समय पर किताबें उपलब्ध कराई जाएं, लेकिन पुस्तकों की छपाई और कागज की गुणवत्ता पर कोई समझौता न हो. ज्ञात हो कि परिषदीय स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के सभी बच्चों को मुफ्त किताबें दी जाती हैं. अगले शैक्षिक सत्र के लिए परिषदीय स्कूलों के 1.8 करोड़ बच्चों के लिए लगभग चौदह करोड़ किताबें छपनी हैं. टेंडर स्थगित होने से बेसिक शिक्षा परिषद का अगला सत्र, जो एक अप्रैल से शुरू होना है, उसमें व्यवधान उपस्थित होगा. घोर भ्रष्टाचार के कारण पुस्तकों के प्रकाशन की अवधि अब बढ़ जाएगी, जबकि सरकार ने अगले सत्र के लिए स्कूली बच्चों को दस अप्रैल तक किताबें वितरित करने की योजना बनाई है.

पूर्व के वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों में घटिया किस्म के कागजों का प्रयोग हो रहा था, जो खुले तौर पर केंद्र सरकार के स्पष्ट निर्देशों और उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना थी, जबकि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सजगता और पुस्तकों के प्रकाशन की गुणवत्ता का हमेशा बखान करती रही. इस बार के शैक्षिक वित्तीय बजट में पन्द्रह फीसदी का इजाफा भी किया गया, लेकिन इस इजाफे का गणित कुछ और ही बिठाया जा रहा था. अधिकारियों ने प्रकाशकों एवं मुद्रक समूहों से साठगांठ करके दो अलग-अलग निविदाएं जारी कीं, जिसमें कवर पेज के लिए तो इको फ्रेंडली कागज की बात कही गई, लेकिन अंदर के पेजों के लिए उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी. साफ था कि अंदर के पेजों पर घटिया कागज के इस्तेमाल की छूट दी गई, जबकि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कवर पेज और अंदर का कागज दोनों ही इको फ्रेंडली होना चाहिए. बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी शिक्षा माफियाओं से मिलकर री-साइकिल्ड कागजों पर पुस्तकें प्रकाशित कर रहे थे और इस बार भी उसे ही दोहराना चाहते थे.

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

माध्यमिक शिक्षा में हजार करोड़ का घोटाला

सपा सरकार पर माध्यमिक शिक्षा की पुस्तकों में हजार करोड़ का घोटाला करने का गंभीर आरोप है. इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों और मेरठ के प्रकाशन माफिया की साठगांठ उजागर हुई है. बसपा ने सपा सरकार पर यह आरोप लगाया है कि पुस्तक प्रकाशन आवंटन में माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों ने मेरठ के नगीन प्रकाशन को बेजा लाभ पहुंचाया. पुस्तक की कीमत के निर्धारण की शर्तों में भी गैर-वाजिब छूट प्रदान की, जिसका लाभ उठाकर प्रकाशक ने प्रति पुस्तक 553 रुपये अधिक मूल्य वसूल किया. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से स्कूल-कॉलेजों में पुस्तकों की खरीद कराई गई थी. प्रकाशक ने शपथ पत्र देने के बावजूद पुस्तक में नियम विरुद्ध विज्ञापन भी छापे, जिससे प्रकाशक को एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिला. लाखों छात्र-छात्राओं पर आर्थिक बोझ पड़ा. बसपा नेता उमाशंकर सिंह ने विधानसभा में इस मामले की शीघ्र जांच की मांग की. उन्होंने पुस्तकों के लिए लेखकों के चयन और बोर्ड के निदेशक की भूमिका पर सवाल उठाए.

पूर्व के वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों में घटिया किस्म के कागजों का प्रयोग हो रहा था, जो खुले तौर पर केंद्र सरकार के स्पष्ट निर्देशों और उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना थी, जबकि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सजगता और पुस्तकों के प्रकाशन की गुणवत्ता का हमेशा बखान करती रही. इस बार के शैक्षिक वित्तीय बजट में पन्द्रह फीसदी का इजाफा भी किया गया, लेकिन इस इजाफे का गणित कुछ और ही बिठाया जा रहा था.

शिक्षा माफिया उत्तर प्रदेश सरकार पर इस तरह हावी हैं कि प्रदेश में सपा की सरकार बनते ही पुस्तक प्रकाशन के नाम पर झांसी के प्रकाशकों ने सरकार से करोड़ों रुपये का भुगतान भी ले लिया, जबकि उन प्रकाशकों पर पहले भी यह आरोप लग चुके हैं कि निविदा होने के पहले ही वे घटिया कागज पर किताबें छापते रहे हैं. भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट आदेश है कि पाठ्य पुस्तकें बांस और लकड़ी से बने वर्जिन पल्प के कागज पर ही प्रकाशित होंगी. रि-साइकिल्ड कागज पर पुस्तकें नहीं छपेंगी. इसका बाकायदा शासनादेश भी है और इस संबंध में उच्च न्यायालय का भी आदेश है. चूंकि बांस और लकड़ी से बने इको फ्रेन्डली कागज और रि-साइकिल्ड कागज के दर में काफी अंतर है, इसलिए शिक्षा विभाग के अफसरों और शिक्षा माफियाओं ने घटिया काजग पर पुस्तकें छपवानी शुरू कीं और आगे के लिए इसका इंतजाम किया. इसमें प्रकाशकों के एक सिंडिकेट भी शामिल था. साठगांठ के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि अच्छे कागजों की कीमत पर रि-साइकिल्ड कागज खरीद लिया जाए. इसके लिए टेंडर भी आमंत्रित कर लिए गए. किसी को पता नहीं चले, इसलिए यह व्यवस्था की गई कि पुस्तकों के जिल्द में बांस और लकड़ी से बने अच्छे पेपर का प्रयोग किया जाए और अंदर घटिया कागज का इस्तेमाल हो, जैसे वे पहले से करते आ रहे थे.

बांस और लकड़ी का अच्छा कागज बनाने वाले भारत सरकार के उपक्रम हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कारगुजारियां उजागर होने के बाद उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई. विभागीय अधिकारी इस शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय कुर्तक देने लगे कि पिछले साल भी पाठ्य पुस्तकें रि-साइकिल्ड पेपर पर ही प्रकाशित हुई हैं. लिहाजा, इस बार भी उसी तरह छपेंगी. बेसिक शिक्षा अधिकारियों की इस साजिश की भनक लगते ही प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता राजनाथ शर्मा ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविन्द चौधरी, मुख्य सचिव आलोक रंजन, बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव आमोद कुमार समेत अन्य कई अधिकारियों से इसकी औपचारिक शिकायत की और इसे मीडिया के समक्ष भी उजागर किया. इससे पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के गोरखधंधे में लगा पूरा तंत्र सतर्क हो गया, जो लोग इस धंधे का हिस्सा खा रहे थे, वे भी खिलाफ में बोलने लगे. मीडिया से जुड़े कुछ लोग भी इसका फायदा उठा रहे थे और इस मसले पर चुप्पी साधे बैठे थे. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा को मामले की जांच का निर्देश दिया और 28 फरवरी को पुस्तकों के प्रकाशन का टेंडर स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया. मुख्यमंत्री के इस फैसले के बावजूद सत्तारूढ़ दल के कुछ नेता इस भ्रष्टाचार से अपने को अलग नहीं कर सकते. इसके अलावा भ्रष्ट नौकरशाह, नेताओं और मंत्रियों को भी इसमें लिप्त करा लेते हैं. मिड-डे मील, मनरेगा, एनएचआरएम जैसी योजनाओं में भीषण घोटालों के बाद अब पुस्तक प्रकाशन की केंद्र सरकार की योजना में भी भ्रष्टाचार सामने आ गया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

उच्च शिक्षा भी घोटाले से अछूती नहीं

ग्रेटर नोएडा के गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में पुस्तकों की मनमानी खरीदारी और मानकों को ताक पर रखकर की गई नियुक्तियों में भारी घोटाला उजागर हुआ है. लोकायुक्त न्यायमूर्ति एनके महरोत्रा इस सिलसिले में अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप चुके हैं. ग्रेटर नोएडा के गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के कई संकायों में छात्रों के न होते हुए भी लगभग दो करोड़ 32 लाख रुपये की पुस्तकों की खरीद की गई. इसके साथ ही मानकों को ताक पर रखकर की गई नियुक्तियों में भी भारी घोटाला सामने आया है. इस मामले में पूर्व कुलपति एसआर लाखा, कार्यवाहक कुलपति प्रो. महावीर सिंह, पूर्व कुल सचिव दिनेश चन्द्र सक्सेना और सहायक कुल सचिव शम्सुद्दीन अंसारी समेत कई लोगों के लिप्त होने का आरोप है. 2011-12 में पुस्तक खरीद में हुए घोटाले के सिलसिले में इस बात का खास तौर से उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ, जस्टिस एंड गवर्नेंस, स्कूल ऑफ स्पेशल साइंसेज स्टडीज तथा स्कूल आफ बुद्धिस्ट स्टडीज के छात्रों के लिए दो करोड़ 32 लाख रुपये से अधिक मूल्य की पुस्तकें खरीदी गयी थीं, जबकि इन संकायों में छात्र ही नहीं थे. स्पेशल साइंसेज स्टडीज फैकल्टी में केवल सात छात्र थे. इसके अलावा स्कूल ऑफ लॉ जस्टिस एवं गवर्नेंस तथा स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज में 10 संकाय सदस्यों की नियुक्ति में घोर अनियमितताएं की गईं.

हिमालय के महाकुंभ नंदा राजजात पर सुझाव पेश

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार हिमालय के महाकुम्भ को भविष्य में और भी सफल तरीके से आयोजित करने के लिए इन दिनों माथापच्ची कर रही है. यह पूरी यात्रा विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सफल रही. इसका आयोजन और बेहतर तरीके से किया जा सकता है. उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा गत वर्ष 18 अगस्त से सात सितंबर तक आयोजित की गई नंदा राजजात के अध्ययन में विस्तार से इस बात को रखा गया है. मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट में गत वर्ष की राजजात में हुई अव्यवस्थाओं का जिक्र तो है ही, साथ में पर्यावरण को पहुंचने वाले नुकसान को बचाने के लिए भी कई सुझाव रखे गए हैं. परिषद के वैज्ञानिक कैलाश नारायण भारद्वाज व अरुण कुकसाल ने यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर बारीकी से नजर रखते हुए इसे भविष्य में वृहद स्वरूप देने और वार्षिक जात को उत्तराखंड के पर्यटन के एक बेहतरीन विकल्प के रूप में उभारने के लिए कई अहम सुझाव रखे हैं. अध्ययन में चार बिंदुओं को प्रमुखता से रखा गया. इसमें यात्रा का पर्यावरणीय पक्ष, स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान, यात्रा में शामिल संस्थाओं की भूमिका व वर्ष 2024 में प्रस्तावित यात्रा के लिए सुझाव. रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व की सबसे लंबी पैदल (280 किमी) इस धार्मिक यात्रा में उत्तराखंड के साथ-साथ देश-दुनिया के हजारों लोगों ने यात्री, पर्यटक, घुमंतू, जिज्ञासू, शिक्षार्थी, शोधार्थी, वैज्ञानिक, समाज विज्ञानी व व्यवस्थापक के तौर पर भाग लिया. वाण से आगे के यात्रियों के लिए बायोमेट्रिक रजिट्रेशन व मेडिकल टेस्ट की व्यवस्था की गई थी. चुस्त व्यवस्था न होने के कारण ज्यादातर यात्री ऐसा कराये बिना वाण से आगे की यात्रा में शामिल हुए. इस पर सुझाव दिया गया है कि उच्च हिमालय क्षेत्र में यात्रा करने वाले प्रत्येक पर्यटक व यात्री का बायोमीट्रिक रजिट्रेशन और मेडिकल टेस्ट अनिवार्य करना होगा. इस वर्ष अगस्त में होने वाली नंदा लोकजात से ही इसकी शुरुआत की जाए. यही नहीं, यात्रा संबंधी आवश्यक सूचनाओं को पहुंचाने के लिए पड़ावों पर एक ही केंद्रीयकृत व्यवस्था से ज्यादातर यात्रियों को सही सूचनाएं लेने में दिक्कतें उठानी पड़ीं. प्रत्येक केंद्र पर दो या इससे अधिक सूचना केंद्रों के साथ ही सचल सूचना केंद्र बनाने की सिफारिश की गई है. राजजात मार्ग पर कूड़ा निस्तारण बड़ी समस्या थी. यात्रियों को प्लास्टिक व कांच आदि को ले जाने और इस्तेमाल करने की कोई रोक नहीं थी. पर्यावरणीय सृष्टि से हानिकारक वस्तुओं के इस्तेमाल और इधर-इधर न फेंकने की अपील का लोगों पर प्रभाव नहीं दिखा. ऐसे में आगामी लोकजात के लिए कड़े नियम बनाने होंगे. पूरे मार्ग पर वाण तक स्थायी और इसके बाद अस्थायी शौचालय बनाये गये. निर्जन स्थानों पर बने यह शौचालय पानी की कमी के कारण उपयोग में नहीं आ पाये. भविष्य में अस्थायी शौचालय ऐसे बनाये जाएं, जिसकी टॉयलेट सीट-सीधे गड्ढे से जुड़ी हो. पैदल पथ बारिश के कीचड़ के ढेर बन गये, जिससे यात्रियों ने इधर-इधर से नये रास्ते बना दिये. इससे पर्यावरणीय क्षति के साथ ही दुर्घटना की आशंका बनी रही. पैदल रास्तों को कम खोदने व रास्ते पर पत्थरों का अधिक उपयोग करने को कहा गया है. संपूर्ण राजजात क्षेत्र (280 किमी) का गहन पारिस्थितिकीय अध्ययन करके लोकजात व राजजात के लिए जुटाई जाने वाली सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का वैज्ञानिक दृष्टि से आंकलन कराने और क्षेत्र के पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए मानवीय व व्यवस्थागत दबाव न्यूनतम करने के उपायों पर काम करने की पैरवी की गई है. इसके अलावा संचार, मौसम की जानकारी और स्थानीय निवासियों को यात्रियों के साथ अच्छे व्यवहार का प्रशिक्षण व अनुपयोगी सामान को न ले जाने देने के लिए कई तरह के सुझाव रखे गये हैं. पूरी सरकार चाहती है कि यह यात्रा जो विश्व मीडिया में चर्चा में रहती है, वह पूरी तरह से बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए भव्य रूप से सम्पन्न हो. ■

पर्यावरणीय दृष्टि से हानिकारक वस्तुओं के इस्तेमाल और इधर-इधर न फेंकने की अपील का लोगों पर प्रभाव नहीं दिखा. ऐसे में आगामी लोकजात के लिए कड़े नियम बनाने होंगे. पूरे मार्ग पर वाण तक स्थायी और इसके बाद अस्थायी शौचालय बनाये गये.

feedback@chauthiduniya.com

गंगा को लेकर आश्रमों की बेरुखी

चौथी दुनिया ब्यूरो

धर्म नगरी ऋषिकेश, हरीद्वार में जो आश्रम गंगा की जीतनी बड़ी आरती उतारते हैं, उनकी गंगा के प्रति उतनी ही बेरुखी सामने आयी है. यह सच्चाई गंगा में गंदगी डालने वाले बड़े आश्रमों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) नई दिल्ली की ओर से आई रिपोर्ट में उजागर हुई है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से किए गए सर्वे के बाद गंगा में गंदगी बहाने वाले आश्रमों पर शिकंजा कसना तय है. बोर्ड की ओर से हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा किनारे स्थित ऐसे 17 बड़े आश्रमों पर कार्रवाई के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट भेजी गई है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली की ओर से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा में गंदगी बहाने वाले किनारे पर स्थित बड़े आश्रमों पर रिपोर्ट तलब की गई थी, जिस पर 11 से 15 फरवरी के बीच प्रदूषण बोर्ड और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की ओर से 22 आश्रमों का सर्वे किया गया.

सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, हरिद्वार और ऋषिकेश में अधिकांश आश्रमों द्वारा बिना किसी रोकटोक के गंगा में गंदगी बहाई जा रही है. गंगा किनारे के जिन आश्रमों का सर्वे किया गया है, उनमें ऋषिकेश स्थित वानप्रस्थ आश्रम, गीता भवन स्वर्गाश्रम, स्वामी सुखदेवानंद ट्रस्ट, हरपीठ आश्रम, सच्चाधाम आश्रम, वेदांत निकेतन धाम, हरिद्वार स्थित पावन धाम आश्रम, सप्तऋषि आश्रम, शांतिकुंज, संत आसाराम आश्रम सहित कुल 22 आश्रम शामिल हैं. सबसे हैरानी की बात यह है कि ऋषिकेश स्थित वह आश्रम जहां भाजपा के दिग्गज आडवणी, उमा भारती जैसे लोगों सहित बहुतायत वीआईपी गंगा आरती कर गंगा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, वहीं पर के आश्रम सबसे ज्यादा गंगा को प्रदूषित करते पाया गया. इनमें से 17 आश्रमों द्वारा गंदगी के शोधन के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं और इसे सीवर के जरिए गंगा में बहाया जा रहा है. क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी डॉ. अंकुर कंसल के अनुसार, रिपोर्ट तैयार कर दिल्ली भेज दी गई है. ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में अब तीर्थधाम में गंदगी फैलाने वाले इन आश्रमों पर शिकंजा कसना तय माना जा रहा है. हरिद्वार और ऋषिकेश में स्थापित सैकड़ों आश्रमों में से वैसे तो अधिकतर आश्रमों की गंदगी सीवर के जरिए गंगा में बहाई जा रही है. गंगा किनारे स्थित जिन 22 बड़े आश्रमों का सर्वे किया गया है, उनमें से महज पांच आश्रमों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, जिनमें अधिकांश खराब मिले हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

राज बब्बर उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद बने

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गजों के बीच खींचतान के चलते कांग्रेस नेतृत्व ने बाहरी प्रदेश के नेता राजबब्बर को राज्यसभा भेजने का फैसला किया. इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने अपनी खुली दावेदारी पेश कर दिल्ली की राजनीति करने का संकेत दिया था. बहुगुणा राज्य की सितारगंज सीट से विधायक हैं. हरीश एंव विजय के दो गुटों में बटी कांग्रेस में हरीश ने एक बार फिर विजय की राह में रोड़ा अटका कर आपसी कलह को सतह पर ला दिया. राजबब्बर की उम्मीदवारी से एक बार फिर उत्तराखंड में बाहरी नेताओं को यहां से राज्यसभा भेजने की पुरानी परंपरा लौटी है. राज्य ने अभी बाहरी नेताओं में सुषमा स्वराज और संघ प्रिय गौतम (भाजपा), सत्यव्रत चतुर्वेदी और कैप्टन सतीश शर्मा (कांग्रेस) को राज्यसभा भेजा है.

हरीश ने बहुगुणा को राज्यसभा भेज कर उपचुनाव का रिस्क लेने को तैयार नहीं हुए, जिसके चलते कांग्रेस हाईकमान को बाहर से प्रत्याशी भेजने का फैसला करना पड़ा. कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड की राज्यसभा सीट के लिए फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद राजबब्बर को उम्मीदवार बनाया है. राजबब्बर राहुल गांधी की पहली पसंद माने जाते हैं. राजबब्बर ने देहरादून पहुंच कर राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया. यह राज्यसभा सीट मनोरमा शर्मा डबरियाल के अचानक निधन की वजह से खाली हुई. मनोरमा शर्मा पिछले साल नवंबर में चुनाव में राज्यसभा की सदस्य चुनी गई थीं. उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए कई स्थानीय नेताओं के नाम पर विचार किया गया. आगरा और फिरोजाबाद से सांसद रहे राजबब्बर पिछले लोकसभा चुनाव गाजियाबाद से हार गए थे. विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रचार में राजबब्बर पार्टी का एक अहम चेहरा होते हैं. भूमि अधिग्रहण के खिलाफ भी उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ बुलंद आवाज उठाई है. भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में कांग्रेस को वाकओवर देने के मूड में है. भाजपा संगठन की ओर से भी कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत का कहना है कि यह चुनाव अंकों का खेल है और हमारे पास आंकड़ा नहीं है. उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने या न उतारने का निर्णय पार्टी नेताओं से आपसी बातचीत के बाद ही लिया जाएगा. भाजपा के असमंजस के लिए उपचुनाव का अंकगणित इसके पक्ष में न होने को ही मुख्य वजह माना जा रहा है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने भी माना कि राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए पार्टी के पास पर्याप्त आंकड़ा नहीं है. साथ ही, भाजपा खरीद-फरोख्त की राजनीति पर भी विश्वास नहीं करती. समाचार लिखने तक राज बब्बर का संसद में जाना पूरी तरह से तय माना जा रहा है. दो दिग्गजों की कलह ने उत्तराखंड से राजबब्बर को संसद में जाने का राह आसान कर दिया. ■

हरीश ने बहुगुणा को राज्यसभा भेज कर उपचुनाव का रिस्क लेने को तैयार नहीं हुए, जिसके चलते कांग्रेस हाईकमान को बाहर से प्रत्याशी भेजने का फैसला करना पड़ा. कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड की राज्यसभा सीट के लिए फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद राजबब्बर को उम्मीदवार बनाया है. राजबब्बर राहुल गांधी की पहली पसंद माने जाते हैं. राजबब्बर ने देहरादून पहुंच कर राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया. यह राज्यसभा सीट मनोरमा शर्मा डबरियाल के अचानक निधन की वजह से खाली हुई. मनोरमा शर्मा पिछले साल नवंबर में चुनाव में राज्यसभा की सदस्य चुनी गई थीं.

उत्तराखंड के सम्पन्न हुए राज्य सभा के चुनाव में प्रत्याशी के चयन में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मर्जी सब पर भारी सिद्ध हुई. इस बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत को विजय बहुगुणा को प्रत्याशी बनने से रोकने में सफलता जरूर मिली. रावत अपनी पसंद के प्रत्याशी को राज्य सभा भेजने में पूरी तरह असफल सिद्ध हुए. कांग्रेस के अन्दरखाने के जिम्मेदार सूत्रों का मानना है कि कांग्रेस के युवराज राहुल ने उत्तराखंड में सतह पर पहुंची गुटबाजी से नाराज होकर दोनों गुटों को आईना दिखाते हुए अपनी पहली पसंद राजबब्बर को प्रत्याशी बनाया, जबकि सूबे के मुख्यमंत्री की पसंद कुछ और ही थी. इस बार फिर हाईकमान द्वारा सम्मान न दिए जाने से बहुगुणा खेमा को भारी निराशा हाथ लगी है. ज़मीनी कार्यकर्ताओं का मानना है कि सोनिया गांधी को फैसला लेना होता तो इन्हें मायूसी न मिलती. बहुगुणा खेमे के नेता भी मानते हैं कि पूरी तरह से राहुल गांधी की ही चली है. राहुल के इस फैसले ने दोनों गुट में एक ऐसी असंतोष की चिंगारी को पैदा कर दिया है, जो किसी भी समय शोला बन सकती है.

feedback@chauthiduniya.com

कागजी सदस्यता अभियान पर बबाल

चौथी दुनिया ब्यूरो

उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेता बोगज सदस्यता के जरीये बड़ी संख्या में धन बल के आधार पर लाखों लोगों को अपना सदस्य बना कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं. यह खुलासा देहरादून में आप पार्टी के जिला संयोजक ने खुद को फर्जी तरीके से भाजपा का सदस्य बनाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए की है. इस मामले में आप समर्थकों ने स्थानीय कोतवाली पहुंचकर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रवक्ता अश्वनी उपाध्याय के खिलाफ तहरीर दी. आप के जिला संयोजक संजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं के साथ शहर कोतवाली पहुंचकर भाजपा पर फर्जी तरीके से सदस्य बनाने का आरोप लगाया. पुलिस को दी गयी तहरीर में कहा गया है कि उन्हें काफी समय से भाजपा का सदस्य बनने का एसएमएस आते रहे हैं. छह मार्च को पहले हिंदी और बाद में अंग्रेजी में दो एसएमएस आए, जिसमें भाजपा में स्वागत करते हुए सदस्यता का नंबर तक दिया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के दिल्ली प्रवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने पार्टी को बदनाम करने के लिए यह साजिश रची है. संजय भट्ट ने बताया कि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा. पुलिस का कहना है कि आरोप की जांच के बाद किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस मामले ने उत्तराखंड के भाजपाई दिग्गजों की जमीनी हकीकत की पोल खोल कर रख दी है, जिसके चलते पार्टी के नेता जमीनी कार्यकर्ताओं से दूर होते जा रहे हैं.

चारधाम यात्रा को लेकर सरकार बेपरवाह

रेनु शर्मा

उत्तराखंड की सरकार के चारधाम यात्रा के मामले में हसब ठठाब फुलाइब गालू की कहावत चरितार्थ करने पर लोग हैरान है. सरकार एक तरफ चाहती है कि यात्रियों की संख्या सीमित रखा जाए तो दूसरी तरफ कोशिश यह भी है कि इस बार चार धाम यात्रा में अधिक से अधिक यात्री पहुंचे. सच्चाई यह भी है कि चार धाम यात्रा मार्ग पर अधिक यात्रियों को संभालने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है. जून 2013 की आपदा के बाद से ही यह साफ होने लगा था कि प्रदेश सरकार को चार धाम यात्रियों की संख्या को किसी तरह से सीमित करना पड़ेगा. चारों धाम उच्च हिमालयी क्षेत्र में हैं और यहां मौसम की अनिश्चितता लगातार बनी रहती है. पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी कहा जाता रहा है कि यात्रियों की संख्या कम होनी चाहिए. खुद सरकार ने बायोमेट्रिक पंजीकरण और केदारनाथ में एक समय में पांच सौ लोगों से ज्यादा न जाने देने की व्यवस्था कर इसकी शुरुआत की थी. परेशानी यह है कि यात्रियों की संख्या कम होने पर हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक के व्यावसायियों का कारोबार प्रभावित होता है. ट्रेवल एजेंट से लेकर होटल व्यवसाय तक इस यात्रा से जुड़े हुए हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार की कोशिश है कि इस बार यात्रा में अधिक से अधिक यात्री पहुंचें. मुख्यमंत्री हरीश रावत इसके लिए राज्यों में रोड शो करने का ऐलान कर चुके हैं और मुंबई में उन्होंने रोड शो किया भी. इसके अलावा पर्यटन विभाग भी लगातार अपनी तरफ से सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश देने की कोशिश कर रहा है.

जून 2013 की आपदा को दो साल होने को है. पहली बार शुरू हुई शीतकालीन यात्रा में भी करीब 67 हजार यात्री उत्तराखंड पहुंचे. यह सब इस बात का भी संकेत है कि इस बार चार धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या में खासा इजाफा हो सकता है. वहीं, चार धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव चमोली, रुद्रप्रयाग अधिक यात्रियों की संख्या का बोझ उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए हैं. सबसे अधिक समस्या रहने, खाने और ठहरने से जुड़े व्यवसाय की है. जून 2013 की आपदा ने इस व्यवसाय की कमर तोड़ दी थी और अभी तक यह पटरी पर नहीं आ पाया है. जाहिर है कि इस समस्या का सामना यात्रियों को करना पड़ सकता है. राज्य के मुख्यमंत्री की मानें तो केदारनाथ यात्रियों को सरकार मुफ्त का रहने-खाने का इंतजाम करने जा रही है.

यात्रा मार्ग को व्यवस्थित करने में जुटी राज्य सरकार के लिए बदरीनाथ यात्रा मार्ग के लामबगड़ का स्लाइड जोन को व्यवस्थित करना ही असली परीक्षा भी होगी. यदि यह स्लाइड जोन यात्रा शुरू होने से पहले व्यवस्थित हो गया तो इसी पर बदरीनाथ यात्रा का भविष्य भी निर्भर करेगा. वर्ष 2013 की भीषण दैवीय आपदा के चलते चारधाम यात्रा अभी तक भी पटरी पर नहीं लौट पाई है. इससे जहां केदारनाथ धाम बर्बाद होकर रह गया था, वहीं सभी धामों के यात्रा मार्ग तबाह होकर रह गए थे. हरीश रावत की सरकार केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण में जुटी है. इसके बाद भी यात्रा मार्ग को व्यवस्थित करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं हैं. सरकार दो साल गुजर जाने के पश्चात अभी तक पांच धामों (हेमकुंड साहिब समेत) के यात्रा मार्ग को व्यवस्थित करने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है. इससे अभी तक यात्रा पटरी पर नहीं लौट आ पाई है और उत्तराखंड के सभी धामों की यात्रा से जुड़े व्यवसायी अब तक भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रह कर सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों पर टकटकी लगाए बैठे हैं. बदरीनाथ, हेमकुंड, केदारनाथ, गंगोत्री तथा यमुनोत्री जैसे प्रमुख पांचों धामों की यात्रा अभी तक ठहरी हुई है. अब जबकि अप्रैल के अंतिम सप्ताह से यात्रा शुरू होनी है तो सरकार को धरातल पर उतर कर काम करना होगा. हालांकि सरकार ने इस ओर कदम बढ़ा दिए है और विभिन्न विभागों से यात्रा शुरू होने से पूर्व तैयारियों को अभी से व्यवस्थित करने पर जोर दिया है. इसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री हरीश रावत अधिकारियों को लगातार दिशा-निर्देश जारी कर रहे हैं. इस सबके बावजूद बदरीनाथ जैसे भारत के प्रमुख धाम की यात्रा को पटरी पर लाने के लिए लामबगड़ स्लाइड जोन को व्यवस्थित करना सबसे बड़ी चुनौती होगी. इस स्लाइड जोन ने ही बदरीनाथ यात्रा पर अब तक ब्रेक लगा रखा है. वर्ष 2013 की आपदा में बेनाकुली से लेकर पांडुकेश्वर तक जिस तरह सड़क तथा पुल साफ हो गए थे, उसके चलते किसी तरह बीआरओ ने सड़क और पुल का निर्माण कर आवाजाही तो शुरू की, लेकिन सुखद व निरापद यात्रा की चुनौतियां अभी तक बनी हुई है. पिछली यात्रा के पहले दिन ही लामबगड़ स्लाइड जोन जवाब दे गया था और शुरुआत के पहले ही दिन इस स्लाइड जोन पर यात्रियों के फंस जाने के कारण इसका संदेश देश भर में गलत गया और यात्रा लौटने का नाम नहीं ले पाई. सरकार भी इस मसले पर कोई खास पहल नहीं कर पाई. लामबगड़ स्लाइड जोन को लेकर बदरीनाथ के व्यावसायियों, हकहकूकधारियों तथा तीर्थ पुरोहितों ने जोरदार आंदोलन भी चलाया. सरकारी स्तर से इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया गया. इसलिए राज्य सरकार के सम्मुख लामबगड़ की चुनौती अब भी बरकरार है. मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लामबगड़ को लेकर कमिश्नर सीएस नपलच्याल को इस स्थल का निरीक्षण करवाने भेजा और स्वयं मुख्यमंत्री ने इस मसले पर बीआरओ के महानिदेशक ले जनरल आरएम मित्तल से भी भेंट कर लामबगड़ व बेनाकुली स्लाइड जोन के ट्रीटमेंट के लिए अभी से प्राथमिकता के साथ काम करने को कहा है. यह बात किसी से छिपी नहीं है कि यदि राज्य सरकार ने लामबगड़ स्लाइड जोन के ट्रीटमेंट के लिए अभी से कोई कदम नहीं उठाए तो फिर बदरीनाथ यात्रा के भविष्य पर संशय के बादल मंडराते रहेंगे. यदि सरकार के प्रयासों से इस स्लाइड जोन का बेहतर ट्रीटमेंट हो गया तो इसी पर बदरीनाथ यात्रा का भविष्य भी तय होगा. वैसे ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर कंचनगंगा, हनुमानचट्टी, बल्दोड़ा, पैनी, हेलंग, पागलनाला, पातालगंगा, टंगणी, विरही, नंदप्रयाग, लंगासू, देवलीबगड़, कालेश्वर, पंचपुलिया, कमेड़ा, शिवनानंदी, व्यासी, तोताघाटी, साकनीधार, मूल्यागांव, चमधार, स्लाइड जोन भी हैं. यही नहीं, केदारनाथ, बदरीनाथ तथा हेमकुंड के लिए सिरोबगड़ स्लाइड जोन तो बरसात के अलावा अन्य दिनों भी मुश्किलों का सबब बना हुआ है. अब देखना यह है कि सरकार इस तरह की चुनौतियों से जूझ कर किस तरह चार धाम यात्रा को पटरी पर लाती है. इस पर ही यहां के तीर्थधामों की यात्रा का भविष्य निर्भर करेगा. हरीश के अपने पार्टी के अन्दर और बाहर के विरोधी इस चारधाम यात्रा को असफल होने का इन्तजार कर रहे हैं. पूरी सरकार चारधाम यात्रा को सफल बनाने में जुटी है. ■

जून 2013 की आपदा को दो साल होने को है. पहली बार शुरू हुई शीतकालीन यात्रा में भी करीब 67 हजार यात्री उत्तराखंड पहुंचे. यह सब इस बात का भी संकेत है कि इस बार चार धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या में खासा इजाफा हो सकता है. वहीं, चार धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव चमोली, रुद्रप्रयाग अधिक यात्रियों की संख्या का बोझ उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए हैं.

feedback@chauthiduniya.com

राज्य मंत्री की विधायकी खतरे में

सीएम की छतरी के नीचे सजायाफ्ता मंत्री

मीरजापुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश भारद्वाज ने 20 साल पहले एक डाकिये से मारपीट करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में प्रदेश के बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास पुष्टाहार राज्य मंत्री कैलाश चौरसिया को दोषी करार दिया है. केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी मंत्री जी की विधानसभा की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश कर दी है. सदस्यता खत्म करने की घोषणा विधानसभा अध्यक्ष को ही करनी है. अब देखना है कि विधानसभा मंत्री जी की सदस्यता खत्म करने पर क्या फैसला लेती है.

सूफी यायावर

अखिलेश सरकार प्रदेश के बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास पुष्टाहार राज्य मंत्री कैलाश चौरसिया को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने आखिरकार चौरसिया की विधानसभा की सदस्यता खारिज कर उनकी सीट रिक्त घोषित किए जाने की सिफारिश कर ही दी. इस पर आखिरी फैसला अब उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय को करना है. हालांकि राज्य मंत्री ने सजा पर मिले स्टे की कॉपी केंद्रीय चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष को भेज दी है. 1995 में ही एक डाकिये से मारपीट करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में मीरजापुर की अदालत ने चौरसिया को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई थी और बीस-बीस हजार के मुचलके पर जमानत भी दे दी थी. अदालत का फैसला आने के बाद से ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर चौरसिया के निष्कासन का दबाव पड़ना शुरू हुआ. सवाल उठा कि अदालत से सजा प्राप्त व्यक्ति सरकार में मंत्री कैसे रह सकता है. इस पर अदालत में याचिका तक दाखिल हो गई.

मीरजापुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश भारद्वाज ने 20 साल पहले एक डाकिये से मारपीट करने, चिट्ठियों का बंडल छीनने तथा उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में प्रदेश के बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास पुष्टाहार राज्य मंत्री कैलाश चौरसिया को दोषी करार देते हुए पिछले दिनों तीन वर्ष के कारावास और नौ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी. पोस्टमैन कृष्ण देव त्रिपाठी ने मीरजापुर के कटरा कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. गवाहों के परीक्षण व उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने चौरसिया को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. फैसले के वक्त मंत्री भी कोर्ट में मौजूद थे. फैसले के बाद मंत्री चौरसिया की ओर से कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया. अदालत ने उन्हें मुचलके पर रिहा कर दिया.

तब राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया ने कहा था कि इस फैसले से विधानसभा की उनकी सदस्यता पर आंच नहीं आएगी, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया की विधानसभा की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश कर दी है. यूपी के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरके पांडेय ने कहा कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कैलाश चौरसिया की सदस्यता खत्म करके सीट रिक्त घोषित करने की संस्तुति विधानसभा सचिवालय से कर दी है. विधानसभा सचिवालय को यह पत्र प्राप्त करा दिया गया है. सदस्यता खत्म करने की घोषणा विधानसभा अध्यक्ष को ही करनी है. विधानसभा ने अभी उनकी सदस्यता खत्म करने पर कोई फैसला नहीं लिया है. कैलाश चौरसिया, सपा के दूसरे विधायक और ऐसे पहले मंत्री होंगे, जिनकी सदस्यता किसी अदालत द्वारा सजा मिलने पर खत्म की गई है. इससे पहले चरखारी के विधायक कप्तान सिंह राजपूत की सदस्यता भी सजा मिलने के बाद स्वत: समाप्त हो गई थी. वहीं चौरसिया ने विधानसभा अध्यक्ष को मीरजापुर कोर्ट से सजा पर मिले स्टे की कॉपी सौंप दी है. विधानसभा सचिवालय इसका कानूनी परीक्षण करवा रहा है. जानकार बताते हैं कि प्रदेश के राज्य मंत्री कैलाश चौरसिया की विधानसभा की सदस्यता समाप्त होने में केवल प्रक्रियागत विलंब है और उसके बाद उनका मंत्री पद जाना भी तय है, लेकिन चौरसिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अपने तरीके से परिभाषित करने पर अड़े हैं. सजा मिलने के कारण विधानसभा की सदस्यता से हाथ धोने वाले महोबा की चरखारी सीट से सपा विधायक रहे कप्तान सिंह राजपूत के ताजा उदाहरण के बारे में पूछने पर कैलाश चौरसिया कहते हैं कि कप्तान सिंह के केस का नेचर अलग था. उन्हें हाईकोर्ट से सजा हुई थी, जबकि मुझे निचली अदालत से. उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई, 2013 को दिए अपने ऐतिहासिक फैसले में जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-8 के अनुच्छेद चार को असंवैधानिक घोषित कर दिया था. इसके तहत सांसद व विधायक सजा पाने के बावजूद तीन महीने तक अपने पद पर बने रहते हुए सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकते थे. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि सजा सुनाए जाने के क्षण से ही सांसद अथवा विधायक की सदस्यता समाप्त मानी जाएगी. इसी आधार पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को लोकसभा व पूर्व केंद्रीय मंत्री रशीद मसूद को राज्य सभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी.

बहरहाल, कैलाश चौरसिया प्रकरण में सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर की तरफ से वकील अशोक पांडेय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ में याचिका भी दाखिल कर दी थी. याचिका में राज्य मंत्री कैलाश चौरसिया के तीन साल की सजा पाने के बाद कानूनन मंत्री नहीं रहने के कारण उन्हें तत्काल हटाए जाने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिली थॉमस केस में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (4) को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद धारा 8 (3) के अनुसार दो साल से अधिक अवधि के लिए सजा मिलने पर सजा की तिथि से ही विधायक और सांसद अयोग्य घोषित हो जाते हैं. इसी प्रकार बीआर कपूर बनाम जयललिता केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि जो व्यक्ति विधायक नहीं बन सकता, वह मंत्री भी नहीं रह सकता है. लिहाजा, तीन साल की सजा घोषित होते ही उन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया. इसके पहले राज्यपाल राम नाइक से भी शिकायत करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी.

मीरजापुर की अदालत से मुकर्रर सजा के खिलाफ सत्र न्यायालय में स्टे के लिए दाखिल राज्य मंत्री की अपील का सरकारी वकील द्वारा कोई विरोध नहीं करने पर भी तीखे सवाल उठने लगे हैं. आरोप लग रहे हैं कि सरकार के इशारे पर सरकारी वकील ने चुप्पी साध ली. इस बारे में भी न्याय विभाग से शिकायत की गई है. सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने राज्य मंत्री कैलाश चौरसिया द्वारा सत्र न्यायालय में दाखिल की गई अपील में जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) फौजदारी द्वारा कोई भी विरोध नहीं करने के सम्बन्ध में मीरजापुर के जिलाधिकारी और प्रमुख सचिव न्याय को औपचारिक शिकायत भेजी है. उन्होंने कहा है कि 10 मार्च, 2015 के सत्र न्यायाधीश के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि डीजीसी फौजदारी ने न तो कैलाश चौरसिया की अपील का विरोध किया और न ही जमानत का विरोध किया. उन्होंने कहा कि यह सरकारी वकील द्वारा शासकीय अधिवक्ता (एलआर) मैनुअल में निर्धारित कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लंघन है. नूतन ठाकुर ने यह भी कहा कि कैलाश चौरसिया ने विधानसभा को भ्रामक सूचना दी है, क्योंकि सत्र न्यायालय के आदेश में दंडादेश के क्रियान्वयन पर रोक लगी है. उस आदेश में दंडादेश पर रोक का कोई उल्लेख नहीं है. ■

कैलाश चौरसिया, सपा के दूसरे विधायक और ऐसे पहले मंत्री होंगे, जिनकी सदस्यता किसी अदालत द्वारा सजा मिलने पर खत्म की गई है. इससे पहले चरखारी के विधायक कप्तान सिंह राजपूत की सदस्यता भी सजा मिलने के बाद स्वत: समाप्त हो गई थी. वहीं चौरसिया ने विधानसभा अध्यक्ष को मीरजापुर कोर्ट से सजा पर मिले स्टे की कॉपी सौंप दी है. विधानसभा सचिवालय इसका कानूनी परीक्षण करवा रहा है.

जौहर विश्वविद्यालय पर सदन में बवाल

उत्तर प्रदेश के कद्दावर बातबहादुर मंत्री आजम खान के रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय के मुद्दे पर विधान परिषद में खूब हंगामा हुआ. बसपा सदस्यों ने विश्वविद्यालय बनाने में लूट-खसोट और अवैध चंदा वसूली का आरोप लगाया. करीब 20 करोड़ रुपये का एजुकेशन सेस न देने पर कार्रवाई की मांग भी की. सरकार के गोल-मोल जवाब से असंतुष्ट बसपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया. बसपा ने शून्य काल में यह मुद्दा उठाया था कि जौहर विश्वविद्यालय में अब तक 20 अरब रुपये का निर्माण कार्य हुआ है. खुद श्रम विभाग ने उसके खिलाफ आरसी जारी की है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई. साथ ही बसपा ने देश-विदेश से चंदा उगाही का भी हिसाब मांगा. मंत्री शाहिद मंजूर के टालू रवैये पर बसपा ने मांग की कि जौहर विश्वविद्यालय में आरसी जारी होने के बाद अगली कार्रवाई की समय सीमा क्या तय की गई है और क्या कार्रवाई होनी है, इसके बारे में सदन को जानकारी दी जाए. इस पर मंत्री ने इतना ही कहा कि जो प्रक्रिया है, उसके तहत कार्रवाई होगी. सरकार के जवाब से नाराज बसपा सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सदन से बाहर चले गए.

दागी विधायकों की भरमार

आपराधिक मुकदमों में अभियुक्त नेताओं के खिलाफ आ रहे अदालतों के फैसले से माननीयों में खासी बेचैनी है. खास तौर पर उत्तर प्रदेश के विधायकों को अधिक परेशानी है, क्योंकि संख्या बल में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले विधायकों की संख्या बहुमत से थोड़ी ही कम है. प्रदेश के कुल 403 विधायकों में से 47 प्रतिशत यानी 189 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें से 98 ऐसे हैं, जिनके ऊपर हत्या, बलात्कार जैसी संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज है. इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि अदालतों के फैसलों से सबसे अधिक तूफान उत्तर प्रदेश में ही मचेगा. समाजवादी पार्टी आपराधिक मामलों वाले माननीयों के मामले में बहुत समृद्ध है. दागी विधायकों के मामले में भी वह अन्य दलों के मुकाबले कहीं आगे है. सपा के 224 विधायकों में से 111 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें से 56 के खिलाफ गंभीर मामले हैं.

दागी विधायकों में सपा के बाद दूसरा नम्बर बसपा का है. उसके 80 विधायकों में से 29 विधायकों पर आपराधिक मुकदमे हैं, जिनमें 14 विधायकों पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं. इस मामले में भाजपा का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है. उसके 47 में से 25 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जबकि इनमें 14 पर गंभीर आरोप हैं. कांग्रेस के 28 में से 13 विधायकों पर आपराधिक मामले हैं. गंभीर अपराधों वाले टॉप टेन विधायकों में नंबर एक पर समाजवादी पार्टी के बीकापुर के विधायक मित्रसेन यादव हैं. उनके खिलाफ 36 मामले हैं. इनमें से अकेले 14 मामले हत्या के हैं. दूसरे नंबर पर माफिया डॉन बृजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह का नाम है. सकलडीहा से निर्दलीय विधायक सुशील सिंह पर 20 मामले दर्ज हैं. इनमें से 12 मामले हत्या के हैं. तीसरे नंबर पर जसराना के सपा विधायक रामवीर सिंह का नाम है. रामवीर के खिलाफ कुल 18 मामले दर्ज हैं. मऊ से कौमी एकता दल से चुने गए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी हत्या के 38 मामलों सहित लगभग दो सौ रिपोर्ट दर्ज हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com